राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 9 अंक 327

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, बुधवार, 6 मई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी

>> 5

जागरण विशेष

आंगन में बांग्ला तो चौखट पार घुलता अवधी का रस

लखीमपुर : पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आकर लखीमपुर में बसे लोग दोनों संस्कृतियों को जी कर पेश कर रहे मिसाल। • पेज-7

संपादकीय

आतंक के विरुद्ध और मजबूत हो मुहिम: जब तक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक वह भारत के लिए खतरा बना रहेगा। **राजा मुनीव** का आलेख।

फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल: अब यह फ्राड नहीं चलेगा कि मुस्लिम गोलबंदी तो सेक्युलर राजनीति है, मगर हिंदुओं को गोलबंद करना सांप्रदायिक। **राजीव सचान** का दृष्टिकोण। • पेज-8

विमर्श

भारत की बदलती व्यापार नीति : भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुआ एफटीए केवल टैरिफ में किया गया बदलाव नहीं है, बल्कि यह खंडित होती वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ एक रक्षात्मक ढांचे का निर्माण भी है। **डा. स्नेहा भगत** का आलेख।

हौसला बढ़ा, पर भाजपा की राह आसान नहीं : बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित भाजपा अब पंजाब में भी जीत हासिल करने के लिए करने लगी तैयारी। **रमनजीत सिंह मण्कू** की पंजाब डायरी। • पेज-9

ममता बोलीं- नहीं दूंगी इस्तीफा, भाजपा ने दिखाया संविधान का आईना

विस चुनाव में तृकां की करारी हार के बाद पार्टी सुप्रीमो ने कहा- मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इन्कार कर दिया। आरोप लगाया कि बंगाल विस चुनाव का परिणाम जनादेश नहीं बल्कि साजिश है। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि उसकी लड़ाई निर्वाचन आयोग से थी, जिसने भाजपा के लिए काम किया। कहा, मैं हारी नहीं बल्कि मुझे हराया गया है। ममता ने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने व विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए को मजबूत करने का संकल्प लिया। वहीं भाजपा ने ममता के इस बयान पर कहा, संवैधानिक प्रक्रिया में भरोसा करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। भवानीपुर में ममता को हराने वाले भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा,संविधान में सब लिखा है। ज्ञात हो, बंगाल में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर 294 सदस्यीय विस में प्रचंड बहुमत हासिल किया है। सात मई को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। देश में यह संभवतः पहला ऐसा मामला है, जिसमें किसी मुख्यमंत्री ने चुनाव में अपनी व पार्टी की हार के बाद पद छोड़ने से मना किया है।

बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के एक दिन बाद ममता ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा,मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमारी हार जनादेश से नहीं, साजिश के तहत हुई है। मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि करीब 100 सीटों पर जनादेश को लूटा गया। उनकी पार्टी का मनोबल गिराने के लिए जानबूझकर मतगणना धीमी की गई। ममता ने कहा, वह संवैधानिक मानदंडों के अनुसार कार्रवाई कर सकती हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त खलनायक बन गए हैं : ममता ने कहा, मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। इतिहास में एक काला अध्याय जुड़ गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त खलनायक बन गए हैं। केंद्रीय एजेंसियां और अधिकारी मिलीभगत से काम कर रहे थे। छापेमारी, तबादले औक पक्षपात ने हालात ऐसे बना दिए कि मुकाबला निष्पक्ष ना रहे।

विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी पेज>>5

- भाजपा की जीत अनैतिक, मैं अब आजाद पक्षी, लोगों की सेवा के साथ विपक्षी गठबंधन को करूंगी मजबूत

कोलकाता में मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करतीं तृकां सुप्रीमो ममता बनर्जी। एएनआइ

- भवानीपुर में ममता को हराने वाले भाजपा नेता सुवेंदु ने कहा- संविधान में सब लिखा है

कोलकाता में मंगलवार को भाजपा कार्यालय पहुंचे सुवेंदु अधिकारी। एएनआइ

खुद को ही हास्यास्पद बना रही हैं

भाजपा के प्रवक्ता देबजीत सरकार ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ममता जैसी बातें बोल रही हैं, उनसे वो खुद को ही हास्यास्पद बना रही हैं। वो कुछ दिनों तक प्रचार की रोशनी में रहना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल ने कहा कि मामले में मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, तृणमूल कांग्रेस की मुखिया के आरोप निराधार और झूठे

भवानीपुर सीट की मतगणना को लेकर उठे विवाद के बीच कोलकाता दक्षिण के जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) रणधीर कुमार ने स्पष्ट किया है कि तृकां उम्मीदवार ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार और झूठे हैं। डीईओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे कभी बंद नहीं किए गए। सीएम संग धक्का-मुक्की या मारपीट की घटना पूरी तरह काल्पनिक है। मतगणना प्रक्रिया कुछ समय के लिए रोकी गई थी, क्योंकि ममता ने इसे रोकने पर जोर दिया था। बाद में चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार उन्हें सूचित कर दोबारा प्रक्रिया शुरू की गई। तृणमूल सुप्रीमों ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि भवानीपुर में मतगणना के दौरान उन्हें और उनके एजेंटों को केंद्र के अंदर जाने से रोका गया, साथही उनके साथ मारपीट भी की गई।

ममता बनर्जी इस्तीफा दें या नहीं, नई सरकार गठित होगी

माला दीक्षित • जागरण

नई दिल्ली : बंगाल चुनाव में करारी शिकस्त के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हार मानने को राजी नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह लोकभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई सीएम चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा नहीं देता तो क्या होगा? संविधानविदों का कहना है कि चुनाव हो चुका है और ममता चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में उनके पद से इस्तीफा देने या न देने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नई विधानसभा का गठन होने के बाद नई सरकार बनेगी।

राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेन्द्र नारायण कहते हैं कि उनके इस्तीफा देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिला है वो दल राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा करेगा। राज्यपाल उसे सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। नई सरकार गठित हो जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश एसआर सिंह कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 172 (1) कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। कार्यकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा भंग मानी जाती है।

जब विधानसभा ही नहीं रही तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कहां रहा? जस्टिस एसआर ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री संविधान के पालन की शपथ लेता है और उसे संविधान का पालन तो करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुशील जैन का कहना है कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देंगे और नई सरकार को शपथ दिलाएंगे।

> पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा भंग मानी जाती है। जब विधानसभा ही नहीं रही तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कैसे रहेगा?
> **- एसआर सिंह, सेवानिवृत न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट।**

बंगाल में नौ मई को होगा भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पेज>>4

...तो मुस्लिम वोटरों ने ही ढहा दिया ममता का अभेद्य दुर्ग पेज>>4

केरलम में सीएम पद की रेस में सतीशन, वेणुगोपाल और चेन्निथला पेज>>5

विमान के भीतर यात्री के पावर बैंक में विस्फोट, कई यात्री घायल

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इंडिगो की हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची फ्लाइट 6ई-108 के केबिन में धुआं भर गया। विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लगने से यह घटना हुई, जिससे कुछ ही देर में केबिन धुएं से भर गया। इमरजेंसी स्लाइड से उतरते समय कई यात्री घायल हो गए। (पेज-6)

डूबे क्रूज को जांच के पहले किया नष्ट, साक्ष्य मिटाने का आरोप

जबलपुर : जबलपुर बरगी बांध में क्रूज हादसे की जांच पूरी होने के पहले ही उसे नष्ट किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। घटना के 40 घंटे के भीतर ही क्रूज को टुकड़े-टुकड़े कर देने से नया विवाद भी खड़ा हो गया है। सुरक्षित बचे पर्यटक और पेशे से अधिवक्ता रोशन आनंद का आरोप है कि जांच पूरी होने से पहले दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को नष्ट कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। (पेज-7)

तमिलनाडु में टीवीके ने किया सरकार गठन का दावा, विजय कल ले सकते हैं शपथ

- नई सरकार को लेकर विजय ने विधायकों के साथ किया मंथन
- टीवीके 108 सीटें जीतकर चुनाव में बनी है सबसे बड़ी पार्टी
- सरकार बनाने के लिए 10 विधायकों की दरकार, कांग्रेस से मांगा समर्थन

चेन्नई में मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते टीवीके प्रमुख विजय। प्रेट्र

दलगत स्थिति (कुल सीटें- 234)

टीवीके	108
द्रमुक	59
अन्नाद्रमुक	47
कांग्रेस	5
पीएमके	4
आइयूएमएल	2
भाकपा	2
वीसीके	2
माकपा	2
भाजपा	1
डीएमडीके	1
एएमएमकेएमएनकेजेड	1

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कणगम (टीवीके) ने मंगलवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। विस में बहुमत का आंकड़ा 118 का है और टीवीके को 10 सीटें कम मिली हैं, अतः पार्टी ने सदन में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल से दो हफ्ते का समय मांगा है। राज्यपाल से आमंत्रण मिलने के बाद विजय गुरुवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पूर्व पीएम नरेन्द्र मोदी व लोस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विजय को जीत पर बधाई दी, जिस पर उन्होंने दोनों को धन्यवाद दिया।

विजय मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पहुंचे और नवनिर्वाचित विधायकों संग बैठक की। प्रेट्र के अनुसार, विजय ने विधायक दल के नेता के चुनाव, सरकार गठन और विस में विधायकों के आचरण पर मंथन किया। टीवीके नेता नांजिल संपत से जब पूछा गया कि पार्टी बहुमत कैसे प्राप्त करेगी, तो उन्होंने कहा, पार्टी प्रमुख इस मामले को सुलझा लेंगे। इससे पूर्व पार्टी मुख्यालय में विजय का जोरदार स्वागत किया गया। वहां उन्होंने पेरियार ईवी रामासामी, बीआर आंबेडकर, के. कामराज, वेलू नाचियार को पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी इन सभी को अपना वैचारिक नेता मानती है।

यह जनादेश राजनीति में धनबल की अस्वीकृति का संकेत है : विजय पेज>>5

सरकार बनाने के लिए छोटे दलों से भी ले सकती है समर्थन पेज>>5

यूएई पर ईरानी हमले में भारतीयों के घायल होने पर पीएम मोदी बोले- अस्वीकार्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ईरानी ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम जोन में लगी आग, तीन भारतीय घायल
- भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, कूटनीति से समाधान ढूंढने की अपील

पश्चिम एशिया में फिर तनाव बढ़ने के संकेत मिले हैं। यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन पर हुए ईरानी ड्रोन हमले में भीषण आग लग गई, जिसमें तीन भारतीय घायल हो गए। इस घटना को अप्रैल में हुए अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम के बाद पहला बड़ा उल्लंघन माना जा रहा है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे "अस्वीकार्य" बताते हुए नागरिकों व सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने पर आपत्ति जताई।

मोदी ने एक्स पर लिखा-भारत यूएई संग मजबूत एकजुटता रखता है और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद व कूटनीति का समर्थन करता है।

नरेन्द्र मोदी। फाइल

ज्ञात हो, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक आठ भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक लापता बताया जा रहा है।

यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, हमले में 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, तीन क्रूज मिसाइलें व चार ड्रोन दागे गए, जिनमें अधिकांश को निष्क्रिय कर दिया गया, पर एक ड्रोन फुजैरा जोन में आग लगाने में सफल रहा। यूएई ने इसे "सार्वजनिक क्षेत्रों पर आतंकी हमला"बताते हुए जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा है। हालांकि, ईरान ने इस हमले को अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का नतीजा बताया है। इस घटना ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि यूएई में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं, जो सालाना 15 अरब डालर से ज्यादा राशि भारत भेजते हैं। साथ ही यूएई भारत का प्रमुख ऊर्जा साझेदार है। दोनों देशों के बीच 200 अरब डालर का द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध भी है।

सबरीमाला केस में सुप्रीम सवाल, क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती देने के मामले में जनहित याचिका पर बुधवार को सवाल उठाया और कड़ी टिप्पणियां भी कीं। सीजेआइ सूर्यकांत ने याची वकील से सवाल किया कि क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं। क्या आप जैसी संस्था की कोई आस्था हो सकती है? न्यायिक संस्था का अंतरात्मा नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसी याचिका दाखिल करने के बजाय वकीलों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। (पेज-3)

गोलीबारी के बावजूद अमेरिका-ईरान युद्धविराम बरकरार

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मंगलवार को राहत की बात रही कि होर्मुज जलडमरूमध्य में झड़पों के बावजूद अमेरिका व ईरान के बीच युद्धविराम कायम है। जहाजों को निकालने की अमेरिकी कोशिशों के विरोध में ईरान ने हमले किए, जिनके जवाब में अमेरिकी कार्रवाई भी हुई, पर दोनों पक्षों ने स्थिति को सीमित रखा। (पेज-11)

सीबीआइ के डीएसपी व पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने अपने ही डीएसपी व उसकी पत्नी पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का एक नया केस दर्ज किया है। डीएसपी के खिलाफ बीएसएफबी में पोस्टिंग के दौरान घूस के एक मामले में पहले से ही जांच चल रही है। बीएसएफबी ने ही नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है। (पेज-7)

एमएसएमई और एयरलाइनों को बड़ी राहत, पांच साल के लिए बिना गिरवी लोन मिलेगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला
- सरकार ने 2.50 लाख करोड़ की व्यवस्था की, गारंटी के रूप में बैंकों को 18,000 करोड़ सरकार देगी

पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम) को बिना किसी गिरवी के 2.50 लाख करोड़ रुपये का लोन देने का फैसला लिया है। यह कदम एमएसएमई को संकट के समय वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए उठाया गया है, ताकि वे कारोबार जारी रख सकें और रोजगार में कटौती को रोक सकें। इस योजना के तहत गैर एमएसएमई व एयरलाइंस कंपनियां भी एक सीमा तक लोन प्राप्त कर सकेंगी। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत सभी एमएसएमई को बिना गिरवी के लोन दिया जाएगा। इस लोन की गारंटी लागत 18,000 करोड़ रुपये आएगी, जिसका भुगतान बैंकों को सरकार करेगी। एयरलाइंस कंपनियां भी स्कीम के तहत 5000 करोड़ का लोन ले सकेंगी। एयर टरबाइन फ्यूल (विमान ईंधन) के दाम में वृद्धि से एयरलाइंस कंपनियों पर दबाव काफी बढ़ गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में किसी एमएसएमई की तरफ से खर्च की गई कार्यशील पूंजी का 20 प्रतिशत लोन उस एमएसएमई को इस स्कीम के तहत दिया जाएगा, पर इसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये होगी। मार्च 2027 तक एमएसएमई स्कीम के तहत लोन ले सकेंगे। इसे पांच साल में चुकाना होगा। पहले साल उन्हें लोन के भुगतान से छूट मिलेगी। एयरलाइंस कंपनियां अधिकतम 1500 करोड़ का लोन ले सकेंगी और उन्हें चुकाने को सात साल का समय दिया जाएगा।

अश्विनी वैष्णव। फाइल

कैबिनेट ने यह अहम फैसले भी लिए

- गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ा 365 रुपये प्रति क्विंटल किया
- टेक्सटाइल सेक्टर की जरूरतों के मद्देनजर काटन की उत्पादकता बढ़ाने को अगले पांच वर्षों में 5659.22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें रिसर्च व उच्च तकनीक के उपाय शामिल होंगे। देश के 14 राज्यों के 140 जिलों में काटन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
- गुजरात में सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी दो प्लांट लगाए जाएंगे। इससे 2230 रोजगार सृजित होंगे।
- गुजरात के वडिनार में 1,570 करोड़ के निवेश से जहाज मरम्मत केंद्र बनाने को स्वीकृति दी गई।

रेलवे की तीन परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी पेज>>3

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज का मैच

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स

शाम 7.30 बजे स्थान : हैदराबाद

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

दैनिक जागरण सप्तरंग

सेहत भरे जीवन का

पानी ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरी

स्क्रीन न बढ़ा दे आटिज्म का जोखिम

• पेज-13

साइबर ठगी उजागर करने वाले दो भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर

न्यूयार्क : दो भारतीय पत्रकारों ने पत्रकारिता क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी उजागर करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को हुई। (पेज-11)

ध्रुवीकरण का असर

इस तरह की राजनीति में कांग्रेस को फायदा, क्षेत्रीय दलों को खतरा, केरलम और असम में मिलाकर 80 प्रतिशत का रहा कांग्रेस का स्ट्राइक रेट

मुस्लिमों ने थामा कांग्रेस का हाथ, पांच राज्यों में जीते 29 उम्मीदवार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में ध्रुवीकरण की राजनीति का असर साफ दिखाई दिया, जहां कांग्रेस और उसके सहयोगियों के मुस्लिम उम्मीदवारों ने अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उल्लेखनीय जीत दर्ज की। खासकर असम, केरल और बंगाल में पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत समर्थन मिला है, पर अन्य वर्गों में उसका आधार सिमटता नजर आ रहा है। यही कारण है कि इन नतीजों को कांग्रेस के लिए 'धूप-छांव' जैसी स्थिति के रूप में देखा जा रहा है।

आंकड़ों के अनुसार, इन राज्यों में जीतने वाले मुस्लिम प्रत्याशियों में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट करीब 80 प्रतिशत रहा। असम में कांग्रेस ने 20 मुस्लिमों को टिकट दिया, जिनमें से 18 जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके उलट, पार्टी के 79 गैर-मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ एक ही जीत सका, जो पार्टी में सामाजिक आधार के असंतुलन की ओर इशारा करता है।

केरल में कुल 140 सीटों में से 35 पर मुस्लिम प्रत्याशी विजयी हुए, जिनमें 30 कांग्रेस नीत यूडीएफ गठबंधन के हैं। इनमें आठ कांग्रेस के और 22 सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर जीते। यह परिणाम मुस्लिम मतदाताओं के बीच कांग्रेस गठबंधन की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। तमिलनाडु में कांग्रेस ने दो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए, जिसमें एक ने जीत दर्ज की।

बंगाल में कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के 47 के मुकाबले 63 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, पर उसे दो मुस्लिम बहुल सीटों पर ही सफलता मिली। दोनों सीटों पर विजयी उम्मीदवार इसी वर्ग से रहे। यह संकेत देता है कि मुस्लिम मतों में समर्थन के बावजूद व्यापक सामाजिक आधार बनाने में पार्टी को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि मुस्लिम मतदाताओं का यह झुकाव कांग्रेस के लिए अवसर के साथ-साथ चुनौती भी है। हिंदी पट्टी के राज्यों में यदि ध्रुवीकरण की राजनीति तेज होती है, तो यह समीकरण पार्टी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर यह मुद्दा अहम बन सकता है। वैसे भी सपा नहीं चाहती कि उसने वर्षों तक 'एमवाई' यानी मुस्लिम-यादव की रणनीति के साथ जो वोटबैंक तैयार किया है, उसका और कोई हिस्सेदार प्रदेश की राजनीति में खड़ा हो। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर दावेदारी को लेकर दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच खींचतान की खबरें सामने आई थीं।

इसके साथ ही यह रुझान राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय दलों के लिए भी संकेत है, जिनका पारंपरिक आधार मुस्लिम मतदाता रहे हैं। राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस परिणाम से उत्साहित होकर अपने पुराने वोटबैंक की वापसी की उम्मीद कर सकती है, लेकिन उसे व्यापक सामाजिक संतुलन साधने की चुनौती से भी जूझना होगा।

कहां कितने मुस्लिम कांग्रेस उम्मीदवार जीते

राज्य	जीते
असम	18
बंगाल	02
केरलम	08
तमिलनाडु	01

611 राजधानी के आंगनबाड़ी केंद्र आधुनिक तरीके से विकसित किए जाएंगे। जहां पर सभी सुविधाएं व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी। इन केंद्रों का डिजाइन तैयार करने के लिए दिल्ली के विभिन्न आर्किटेक्ट की मदद ली जाएगी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 6 मई, 2026

आज का मौसम

बुधवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शाम या रात के समय गर्जन वाले बादल बनने के भी आसार हैं।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
6 मई	35.0	21.0
7 मई	36.0	23.0
नोएडा		
6 मई	35.0	21.0
7 मई	35.0	22.0
गुरुग्राम		
6 मई	39.0	24.0
7 मई	40.0	25.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

वायु प्रदूषण टास्क फोर्स के निरीक्षण में 61 मामले मिले

नई दिल्ली : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की टास्क फोर्स ने 11 से 28 अप्रैल के दौरान दिल्ली समेत एनसीआर में 174 निरीक्षण किए। इनमें औद्योगिक इकाइयों, निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) साइटों और डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों की जांच की गई। जांच के दौरान 61 मामलों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, जिसमें सबसे अधिक 41 मामले डीजल जनरेटर सेटों से संबंधित थे। (राब्यू)

सुकेश चंद्रशेखर का हवाला लेनदेन संभाल रहा करीबी पकड़ा

नई दिल्ली: दो सौ करोड़ की ठगी के मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर के करीबी साथी नवस कक्कट इस्माइल उर्फ नवस केआइ को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित सुकेश चंद्रशेखर का मुख्य हवाला आपरेटर है। वह वर्ष 2021 से फरार था और ईओडब्ल्यू द्वारा उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया था। इसी के आधार पर इसे दुबई में गिरफ्तार किया गया है। (जासं)

जेल में बंद चीनी नागरिक, प्रेमिका को उपलब्ध कराया वकील

गाजियाबाद : नोएडा-ग्रेटर नोएडा में दो कंपनी व होटल क्लब चलाकर करोड़ों कमाने वाले चीनी नागरिक सु-फाई के पास अब वकील की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। जून 2022 से सु-फाई अपनी प्रेमिका पेटेख रेनुओव संग डासना जेल में बंद है। उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निश्शुल्क वकील मांगा है। प्राधिकरण ने अधिवक्ता विचित्र वीर सिंह को दोनों की पैरवी की जिम्मेदारी सौंपी है। (जासं)

सबसे ज्यादा जाम वाले तीन कारिडोर को बनाया जाएगा सिग्नल फ्री

वी के शुक्ला • जागरण

- इनमें इंडिया गेट से बदरपुर, पंजाबी बाग से टीकरी बार्डर और अंधेरिया मोड़ से गुरुग्राम बार्डर मार्ग शामिल
- व्यवहार्यता अध्ययन व डीपीआर प्रक्रिया शुरू, कुछ वर्षों में दूर होगा जाम

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार द्वारा करीब एक साल पहले किए गए अनुरोध पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने सबसे ज्यादा जाम वाले तीन कारिडोर को सिग्नल फ्री कर जाम मुक्त बनाने की जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली है। आमतौर पर दिल्ली की आंतरिक सड़कों का रखरखाव पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाता है, लेकिन इन मार्गों की जटिलता और राष्ट्रीय राजमार्गों से इनके जुड़ाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एनएचएआइ से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। एनएचएआइ ने इन व्यस्त मार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है।

इनमें इंडिया गेट से बदरपुर तक जाने वाला मथुरा रोड, पंजाबी बाग से पीरागढ़ी होते हुए हरियाणा बार्डर तक जाने वाला टीकरी बार्डर मार्ग और अंधेरिया मोड़ से गुरुग्राम बार्डर तक महरौली गुरुग्राम (एमजी रोड) मार्ग शामिल हैं। इनके सिग्नल फ्री होने से दिल्ली ही नहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा के लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं का काम पूरा होने पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ के बीच आवाजाही काफी सुगम हो जाएगी। परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है, तो यह न केवल यातायात की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि राजधानी की अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर को भी नई गति प्रदान करेगा।

पंजाबीबाग से पीरागढ़ी होते हुए टिकरी बार्डर।

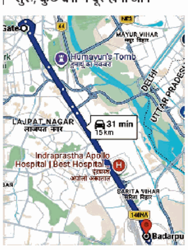

इंडिया गेट से बदरपुर।

महरौली के अंधेरिया मोड से गुरुग्राम की सीमा तक महरौली गुरुग्राम रोड।

ये तीन कारिडोर बदलेंगे दिल्ली की सूरत:

मथुरा रोड : इंडिया गेट से बदरपुर तक 15 किमी लंबा यह मार्ग दक्षिण दिल्ली को फरीदाबाद और आगरा से जोड़ता है। इस पर प्रमुख रूप से सात लालबत्तियां हैं। इंडिया गेट से 500 मीटर की दूरी पर पहली लालबत्ती है। इसके बाद निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, भोगल, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, जामिया कट, सीआरआरआइ और अपोलो अस्पताल प्रमुख लालबत्तियां शामिल हैं। इस मार्ग पर काफी जाम लगता है।

रोहतक रोड : रोहतक रोड पंजाबी बाग से पीरागढ़ी होते हुए हरियाणा बार्डर तक जाता है। भारी वाहनों के दबाव और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण इस मार्ग के कई हिस्सों में अक्सर जाम की स्थित रहती है। इस मार्ग की लंबाई करीब 17 किमी है। इस मार्ग पर छह लालबत्तियां हैं।

एमजी रोड : दिल्ली और गुरुग्राम के बीच चलने वाले लाखों पेशेवरों के लिए यह मार्ग लाइफलाइन है। यह करीब 18 किलोमीटर लंबा है। इस मार्ग पर चार लालबत्तियां हैं, जिनमें सुल्तानपुर, घिटोरनी, अर्जनगढ़ और सिकंदरपुर प्रमुख हैं। मेहरौली से गुरुग्राम के बीच का यह मार्ग काफी व्यस्त रहता है।

आम जनता को क्या होगा लाभ? : इन कारिडोर के जाम मुक्त होने से यात्रियों के यात्रा समय में 30 से 40 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। वाहनों के कम रुकने से ईंधन की खपत घटेगी।

उद्देश्य दिल्ली की आंतरिक सड़कों पर दबाव कम करना: केंद्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि इन परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य दिल्ली की आंतरिक सड़कों पर दबाव कम करना और वाहनों की औसत गति को बढ़ाना है। डीपीआर में तय किया जाएगा कि इन सड़कों पर कहां फ्लाईओवर, अंडरपास या फुटओवर ब्रिज की आवश्यकता है।

वर्षों से ये लालबत्तियां हटने का है इंतजार: पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख अभियंता दिनेश कुमार का कहना है कि इंडिया गेट से बदरपुर, अंधेरिया मोड़ से गुरुग्राम और पंजाबी बाग से टीकरी बार्डर यह तीनों मार्ग व्यस्त मार्गों में शामिल हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है कि एनएचएआइ ने इन्हें अपने अंतर्गत ले लिया है।

दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों का वेतन किया दोगुना

फैसला ▶ शिक्षकों का वेतन 20 हजार से बढ़कर हुआ 38,100 रुपये

समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों का वेतन बढ़कर 35,420 रुपये हुआ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के स्कूलों में तैनात 1131 वोकेशनल शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक परामर्श व मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के साथ ही उनका कौशल आकलन कर उचित परामर्श देते हैं। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित विशेष केंद्रों में तैनात शिक्षक पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु इन शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। पिछले काफी समय से इन शिक्षकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग की जा रही थी। इसे अब पूरा किया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में इनके वेतन वृद्धि को स्वीकृति दी गई। अब वोकेशनल शिक्षकों का वेतन लगभग दोगुना हो गया है।

दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करती हुई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। सौ. दिल्ली सरकार

मुख्यमंत्री ने बताया कि वोकेशनल शिक्षकों का पहले 20 हजार से 23 हजार रुपये के बीच वेतन मिलता था। इसे बढ़ाकर 38,100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे 784 विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 35,420 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इन केंद्रों के माध्यम से स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को शिक्षा से जोड़कर मुख्यधारा में लाया जाता है।

सीएम ने कहा कि यह निर्णय केवल शिक्षकों के लिए आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि शिक्षकों के समर्पण व कठिन परिश्रम का सम्मान है। अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के समान वेतन मिलेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को और मजबूत किया जा रहा है। नियमित निगरानी, अभिभावकों की काउंसलिंग और विभागीय समन्वय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो।

राजधानी में कहीं पड़े ओले, कहीं गरज चमक के साथ पड़ी बौछारें

राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : मंगलवार को राजधानी में दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद पालम, द्वारका और आइजीआइ एयरपोर्ट सहित कई हिस्सों में वर्षा हुई और ओले भी पड़े। वर्षा के कारण तापमान में भी कमी आई। इससे पहले सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह भी कई इलाकों में वर्षा दर्ज की गई थी। मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह वर्षा की संभावना को लेकर यलो अलर्ट भी जारी कर दिया था। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक पालम में आयानगर में 1.4 मिमी, नजफगढ़ में 6.5 मिमी और मयूर विहार में 1.5 मिमी वर्षा दर्ज की गई। सफदरजंग में नाममात्र की वर्षा हुई।

पश्चिमी दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि। सौजन्य :इंटरनेट मीडिया

केजरीवाल, सिसोदिया, पाठक के लिए न्याय मित्र नियुक्त करेगा हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पूर्व सीएम व अन्य के सुनवाई से खुद को अलग करने पर लिया निर्णय

आबकारी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आप नेता दुर्गेश पाठक की तरफ से जिरह के लिए दिल्ली हाई कोर्ट एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त करेगा। ट्रायल कोर्ट के निर्णय के सीबीआइ की अपील याचिका पर सुनवाई में शामिल नहीं होने के आप नेताओं के निर्णय को देखते हुए मंगलवार को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि मामले पर आगे बढ़ना तभी उचित होगा, जब इन नेताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को नियुक्त कर दिया जाए। पीठ ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया, पाठक की तरफ से जिरह के लिए एमिकस क्यूरी के तौर पर तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाएगा। मामले की सुनवाई आठ मई तक के लिए स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि एमिकस क्यूरी की नियुक्ति पर आदेश पारित किया जाएगा और इसके बाद सुनवाई शुरू होगी।

ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी घोटाला मामले में केजरीवाल, सिसोदिया व 21 अन्य लोगों को आरोपमुक्त कर दिया था। सीबीआइ की याचिका पर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को प्रथमदृष्टया गलत कहा था और सीबीआइ जांच अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश पर

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक। फाइल

रोक लगा दी थी। केजरीवाल, सिसोदिया कुछ अन्य आरोपितों ने न्यायमूर्ति शर्मा को सुनवाई से अलग करने की मांग को लेकर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को पत्र लिखा था। हालांकि, यह कहते हुए मांग को ठुकरा दिया था कि एक जज स्वयं सुनवाई से अलग हो सकता है। इस पर कोई प्रशासनिक आदेश नहीं पारित किया जा सकता है।

इसके बाद केजरीवाल सहित अन्य ने न्यायमूर्ति शर्मा के समक्ष अर्जी दायर कर उनसे मामले की सुनवाई से अलग होने का अनुरोध किया। 20 अप्रैल को न्यायमूर्ति शर्मा ने केस से अलग होने की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि किसी पक्षकार के भेदभाव के बेबुनियाद डर को पूरा करने के लिए जज खुद को अलग नहीं कर सकते। केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने एक के बाद एक पत्र लिखकर कहा था कि वे मामले की सुनवाई में शामिल नहीं होंगे।

कोर्ट ने ईडी को संजय भंडारी की कुछ संपत्तियां जब्त करने की दी अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में भगोड़े घोषित किए जा चुके हथियार डीलर संजय भंडारी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने आदेश दिया कि बाकी संपत्तियों की जब्ती पर सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इससे पहले पांच जुलाई 2025 को अदालत ने भंडारी को मनी लांड्रिंग मामले में भगोड़ा घोषित किया था।

ईडी ने बताया था कि भंडारी के पास भारत के अलावा दुबई और यूके में भी बेनामी संपत्तियां हैं। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शापिंग कांप्लेक्स और शाहपुर जाट समेत नोएडा और गुरुग्राम में भी संपत्तियां होने का दावा किया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, भंडारी की पत्नी के नाम पर भी कई बैंक खाते हैं और कुल संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

इससे पहले ईडी इस मामले में पंचशील पार्क स्थित एक संपत्ति को जब्त कर चुकी है।

बुराड़ी में नाले में गिरने से बच्ची की मौत मामले में अनुबंधित जेई बर्खास्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने की कार्रवाई
- सीएम ने खतरनाक नालों को जल्द ठीक करने के दिए निर्देश

बुराड़ी क्षेत्र के मुकुंदपुर में खुले नाले में गिरने से दो वर्षीय बच्ची की मौत के बाद राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त जूनियर इंजीनियर (जेई) को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस आपराधिक लापरवाही के लिए क्या सिर्फ अनुबंधित जूनियर इंजीनियर ही जिम्मेदार है, वरिष्ठ अधिकारी नहीं?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्ची की मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में खुले नालों व जान-माल के लिए खतरा पैदा करने वाले स्थलों की पहचान कर उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से ऐसा ही आदेश गत सात फरवरी को जनकपुरी हादसे के बाद भी दिया गया था।

सदमे में बच्ची की मां, नाले के पास बैठकर बोलीं- 'आ जा बेटी दूध पी ले...' : भलस्वा थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर में रविवार को खुले नाले में गिरने से हुई दो वर्षीय बच्ची की मौत के बाद परिवार दुख में डूबा है। बच्ची की माता स्वीटी व पिता विकास सदमे में हैं। दिवगंत बच्ची दंपती की इकलौती संतान थी। स्वीटी रह-रह कर उस नाले के पास चली जाती हैं, जहां मासूम डूबी थी। उस समय सबकी आंखें नम हो गईं, जब मंगलवार दोपहर स्वीटी नाले के पास बैठकर बोलने लगीं-आ जा बेटी दूध पी ले। स्वजन बड़ी मुश्किल से स्वीटी को ढांढस बंधाते हुए घर के भीतर ले गए।

मंगलवार को एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वजन व स्थानीय लोगों से घटना के बारे में बात की। नाला पहले की ही तरह खुला पड़ा है।

15 जून को नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान मुंबई के लिए, अयोध्या की भी तैयारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को इंडिगो की पहली उड़ान मुंबई के लिए शुरू होगी। यात्री विमान सेवा के लिए टिकट बुकिंग गुरुवार से शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट के पहले चरण में जमीन देने वाले किसानों को लखनऊ में सम्मानित कराने व अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दर्शन के लिए इंडिगो की दूसरी विशेष उड़ान रवाना हो सकती है।

अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय इकाइयों व कारोबार के सिलसिले में मुंबई से प्रतिदिन काफी संख्या में लोग नोएडा सहित एनसीआर के लिए आवाजाही करते हैं। व्यापारी और कारोबारियों के लिए आवाजाही सुगम करते हुए इंडिगो की नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू होगी। इससे नोएडा के आर्थिक विकास को और गति मिलेगी। इंडिगो के साथ आकासा और एअर इंडिया एक्सप्रेस भी नोएडा एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू करेंगी। देश के विभिन्न शहरों के लिए नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानों और किराये की स्थिति जल्द स्पष्ट हो जाएगी।

महिला पीटीआइ पर धार्मिक टैटू हटाने व मतांतरण का दबाव, हिंदू संगठनों का हंगामा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- शिक्षिका बोली, छात्रों को जबरन चर्च ले जाकर कराया जाता था ब्रेनवाश -काट दिए जाते थे हाथों में बंधे कलावे, तिलक लगाने की नहीं थी अनुमति

सेंट टेरेसा पब्लिक स्कूल में मंगलवार को तब हंगामा खड़ा हो गया, जब महिला पीटीआइ ने उस पर धार्मिक टैटू हटाने व मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। साथ ही छात्रों को भी कथित रूप से चर्च ले जाकर ब्रेनवाश करने, हाथों में बंधे कलावे काटने व माथे पर तिलक लगाने पर रोक जैसे गंभीर आरोप सामने आए। घटनाक्रम ने माहौल को इतना गरमा दिया कि हिंदू संगठनों के पदाधिकारी भड़क उठे व स्कूल परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गेट पर 'जय श्रीराम', 'ओम' व 'बजरंग दल' लिखकर प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। धरना देते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस व संगठन पदाधिकारियों के बीच नोकझोंक भी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। महिला पीटीआइ की तहरीर पर प्रधानाचार्य व फादर पर गंभीर आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है।

स्कूल गेट पर जय श्रीराम लिखने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते पदाधिकारी। जागरण

अरुणा रानी पिछले 12 साल से संतपुरा कालोनी के सेंट टेरेसा स्कूल में पीटीआइ हैं। उनके मुताबिक, स्कूल में छात्रों को जबरन चर्च ले जाकर उनका ब्रेनवाश कराया जा रहा है।

गाजियाबाद में चार मंजिला अपार्टमेंट में आग, नौ लोग निकाले गए सुरक्षित

नीति खंड दो में फ्लैट में लगी आग को बुझाते दमकल कर्मी व मौजूद लोग। जागरण

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- भूतल पर पार्किंग में स्टाफ रूम में खाना बनाते वक्त सिलिंडर में लगी थी आग

दिल्ली के विवेक विहार में हालिया अग्निकांड की दहशत अभी थमी भी नहीं थी कि मंगलवार को जिले के इंदिरापुरम के नीतिखंड-दो में वैसा ही खौफनाक मंजर सामने आ गया, जब एक चूक ने पूरे चार मंजिला अपार्टमेंट को आग व धमाकों की जद में ला दिया।

भूतल पर गैस रिसाव से भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया व तीन गैस सिलिंडरों के धमाकों ने हालात और विस्फोटक बना दिया। धमाकों की गूंज, घना धुआं व चीख-पुकार के बीच नौ लोग ऊपरी मंजिलों में फंसकर जिंदगी की जंग लड़ते रहे। बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद होने पर ये छत पर शरण लेने को विवश हुए। मौके पर पहुंची दमकल व पुलिस टीम ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू आपरेशन चलाया। पांच गाड़ियों की मदद से करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि नीतिखंड-दो स्थित प्रगति लेन कालोनी स्थित बैकुंठम अपार्टमेंट भूतल से तीन मंजिला बना है। भूतल पर बनी पार्किंग में ही बने एक कमरे में तीनों फ्लैटों की सुरक्षा करने वाले गार्ड मनोज स्वजन संग रहते हैं। सीएफओ ने बताया कि वैशाली फायर स्टेशन को मंगलवार दोपहर डेढ़ बजे अपार्टमेंट में आग की सूचना मिली थी।

विदेश मंत्रालय से ईरान से सिखों को वापस लाने की मांग

वि, नई दिल्ली: ईरान में फंसे सिखों को भारत लाने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) सक्रिय हो गया है। इसे लेकर डीएसजीएमसी के पदाधिकारियों ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की।

कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह काहलों और कमेटी के विदेश मामलों के सलाहकार परमजीत सिंह चंडोक ने इस मामले को विदेश मंत्रालय के सामने उठाया है। उनका कहना है कि कई सिख ईरान में फंसे हैं। उन्हें वापस लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि शीघ्र ही तेहरान से विशेष उड़ान की व्यवस्था की जाएगी। सिख नेताओं ने कहा कि इस बचाव अभियान में दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी केंद्र का सहयोग करेगी।

लोगों की सुरक्षा का दु:स्वप्न नहीं बन सकते साप्ताहिक बाजार : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के विभिन्न इलाकों में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। उत्तम नगर इलाके के साप्ताहिक बाजार को हटाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर अदालत ने टिप्पणी की है कि साप्ताहिक बाजारों को वहां रहने वालों के लिए सुरक्षा और संरक्षा के लिहाज से कोई दुःस्वप्न नहीं बनने दिया जा सकता।

याचिका के साथ दाखिल की गई तस्वीरों को देखने के बाद न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से कहा कि ऐसे अनियंत्रित साप्ताहिक बाजारों को नियंत्रित करना चाहिए। मामले पर एमसीडी सहित स्थानीय नागरिकों को नोटिस जारी कर अदालत

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल

ने स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।

अदालत ने कहा कि इन बाजारों में लगने वाली अस्थायी दुकानों की संख्या और उनके द्वारा घेरी गई जगह को नियंत्रित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने उत्तम नगर सेक्टर-तीन के सोम बाजार रोड स्थित गली नंबी-15 में सोमवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को हटाने की मांग की है।

चार वर्षीय बच्ची से हैवानियत करने वाला दुष्कर्मी दोषी करार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कारिडोर रोहिणी कोर्ट ने त्वरित न्याय का एक और उदाहरण पेश किया है। लगभग पांच वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले दुष्कर्मी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मात्र साढ़े पांच महीने की अपना निर्णय दिया। इसी सप्ताह सुनवाई के बाद कोर्ट सजा की घोषणा कर सकती है। इस मामले में गत दिसंबर महीने में न्यायाधीश ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट देखकर बिना वीआइआर (विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट) के ही पांच लाख रुपये सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने 30 अप्रैल को आरोपित को कई धाराओं के अलावा पाक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी ठहराया गया। इस मामले में कुल 41 गवाह थे।

1476 करोड़ का अनुबंध देश की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ किया है। इसके तहत भारतीय सेना के लिए पांच जमीन पर स्थित मोबाइल इलेक्ट्रानिक सिस्टम खरीदे जाएंगे।

'मेड इन इंडिया' हथियारों से दुनिया की रक्षा करेगा भारत'

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ व केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने सैन्य शक्ति को सराहा
- नार्थ टेक सिंपोजियम का आज समापन, ड्रोन, एंटी ड्रोन व अन्य हथियारों का होगा प्रदर्शन

प्रयागराज में मंगलवार को 'नार्थ टेक सिम्पोजियम 2026' में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हथियारों के बारे में जानकारी लेते हुए। एएनआइ

रक्षा आयात पर निर्भरता को छोड़ निर्यातक बनने की दिशा में बढ़ रहे भारत की वर्तमान स्थिति को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सैन्य शक्ति में बढ़ता वैश्विक कद बताया। कहा कि भारत अब रक्षा आयात पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा प्रणालियों से दुनिया की रक्षा करने वाला राष्ट्र बन गया है। अब 'मेड इन इंडिया' हथियार दुनियाभर में नजर आएंगे।

न्यू कैंट स्थित कोबरा आडिटोरियम में 'नार्थ टेक सिंपोजियम 2026' के दूसरे दिन उद्घाटन सत्र में रक्षा राज्य मंत्री ने पिछले वर्ष हुए 'आपरेशन सिंदूर' की सफलता को भारतीय सेना के साहस और स्वदेशी तकनीक का बेजोड़ संगम बताया। उन्होंने कहा कि मेड-इन-इंडिया हथियारों ने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। यह इस बात का प्रमाण है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता धरातल पर उतर चुकी हकीकत है।" युवाओं और स्टार्टअप्स का आह्वान किया कि वे 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को पाने के लिए भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप 'आउट आफ द बाक्स' समाधान तैयार करें। स्पष्ट किया कि भारत की सैन्य शक्ति अब विदेशी धरती पर नहीं, बल्कि देश की फैक्ट्रियों में गढ़ी जा रही है। उप्र रक्षा औद्योगिक गलियारे की चर्चा करते हुए कहा, "हमारे स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई इस युग के 'विश्वकर्मा' और भविष्य के विकास की प्रेरक शक्ति हैं। वे 2047 तक 'विकसित भारत' के प्रधानमंत्री मोदी के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

दूसरे सत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्षों में भारत का रक्षा उत्पादन 1.54 लाख करोड़ के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। बड़ी उपलब्धि निर्यात के मोर्चे पर रही है, जिसमें 34 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपये के पार है, जिसमें निजी क्षेत्र की 15 हजार करोड़ रुपये की बड़ी हिस्सेदारी है। सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के रक्षा बजट में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 6.81 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

ड्रोन व एआइ तकनीक से वार, भविष्य के युद्ध के लिए सेना तैयार

विवेक सिंह • जागरण

जम्मू : आपरेशन सिंदूर अब आतंक के खिलाफ जंग में देश की बदली रणनीति का प्रतीक बन चुका है। एक वर्ष पहले यह पहलगाम हमले के बाद देश की प्रतिक्रिया भर नहीं थी, बल्कि नए भारत के उदय का शंखनाद था। आपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने यह साबित कर दिया कि वह भविष्य की लड़ाई के लिए न केवल तैयार है, बल्कि करार जवाब देने में भी सक्षम है। चीन और तुर्किए की तकनीक व ड्रोन से लड़ रहे पाकिस्तान को तीन दिन में घुटने पर लाने के बाद भी हम थमे नहीं और एक साल में बड़े बदलाव लाकर सेना को आधुनिक, तकनीकी और बहुआयामी युद्ध के लिए तैयार कर लिया।

एक वर्ष में ड्रोन और ड्रोनरोधी अभ्यास हमारी सेनाओं का हिस्सा बन गए हैं। एआइ तकनीक आधारित हथियार के साथ ड्रोन और इलेक्ट्रानिक वारफेयर अब युद्धकला का हिस्सा है। हर सैनिक के लिए ड्रोन प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया दिया है। अब हमारे जवान राइफल व तोप से ही आग नहीं उगलते, ड्रोन से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। आपरेशन सिंदूर और उसके बाद दुनियाभर में चल रहे युद्धों से सीखते हुए हमारी सेनाएं भविष्य के युद्धों की चुनौतियों का सामना करने के लिए तकनीकी रूप से बेहतर बनने में जुट गईं। आज सेना की हर बटालियन ड्रोन से दुश्मन पर सटीक प्रहार करने के साथ दुश्मन के ड्रोन को हवा में मार गिराने वाले आधुनिक यंत्रों से लैस है।

उत्पादन में 174 प्रतिशत और निर्यात में 34 गुना वृद्धि : नेतृत्व के स्तर पर अधिक स्पष्टता और सजगता ने सेना की तैयारी को नई ऊर्जा दी। आपरेशन सिंदूर के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन को गति मिली। स्वदेशी हथियार प्रणालियों, संचार उपकरणों व निगरानी तकनीकों के उपयोग से यह सिद्ध हुआ कि देश अब रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम कर रहा है।

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली सेना की पश्चिमी कमान के जवान युद्ध अभ्यास करते हुए। फाइल/फोटो सेना

कभी न भूलने वाला सबक सिखाया : ब्रिगेडियर देवेंद्र

कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर देवेंद्र कुमार ने कहा कि आपरेशन सिंदूर में दुश्मन को कभी न भूलने वाला सबक दिया गया। साइबर स्पेस, अंतरिक्ष, सूचना युद्ध, एआइ जैसे क्षेत्रों में सैन्य क्षमताओं को और सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया।

सेना के आधुनिककरण की रफ्तार हुई तेज

40 हजार करोड़ रुपये के आपातकालीन खरीद अधिकार मिलने से बदला सेना का स्वरूप

300 धनुष तोपें, अतिरिक्त वायु रक्षा ट्रैक खरीदने की प्रक्रिया

159 बुलेटप्रूफ ट्रूप वाहन राष्ट्रीय राइफल्स को खरीदने की प्रक्रिया जारी

5 हजार करोड़ रुपये के भारत निर्मित ड्रोन के खरीद की प्रक्रिया

850 नागस्त्र-1आर स्वदेशी ड्रोन खरीदे जा रहे, पहली खेप सेना को मिल चुकी

5 इलेक्ट्रानिक वारफेयर की खरीद का करार

रेलवे की तीन परियोजनाओं को मंजूरी

बड़ा कदम ▸ 23,437 करोड़ से बिछेंगी 901 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनें

परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत छह राज्यों को होगा फायदा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अश्विनी वैष्णव। फाइल

रेलवे नेटवर्क को अधिक तेज, सुगम और विश्वसनीय बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 23,437 करोड़ रुपये की लागत से तीन मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। करीब 901 किलोमीटर नई लाइन बिछाई जाएगी, जिससे छह राज्यों के 19 जिलों में रेल संपर्क में इजाफा होगा। मंजूर परियोजनाओं में मथुरा से नागदा, बुढ़वल से सीतापुर और गुंटकल से वाडी खंड पर तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक को फायदा होगा। तीनों प्रोजेक्ट को अगले चार से पांच वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं सिर्फ रेल लाइनों का विस्तार ही नहीं, बल्कि तेज विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में ठोस कदम हैं, जिनका असर आगामी वर्षों में दिखाई देगा। प्रोजेक्ट के पूरा होने से इन रूटों पर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। भीड़ घटेगी। समयबद्ध सेवा का लाभ मिलेगा। वर्तमान ट्रैक पर दबाव को देखते हुए यह विस्तार अहम माना जा रहा है।

वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं का सीधा फायदा आम आदमी को बेहतर यात्रा अनुभव के रूप में मिलेगा। ट्रेनों की उपलब्धता के साथ गति भी बढ़ेगी। लंबी दूरी के यात्रियों को कम प्रतीक्षा करना पड़ेगा। खास बात यह भी कि लगभग 4,161 गांवों की 83 लाख लोगों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। सरकार का फोकस सिर्फ यात्री सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि लाजिस्टिक्स को सस्ता और तेज बनाना भी है। ये रेल मार्ग कोयला, खाद्यान्न, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, लोहा-इस्पात और उर्वरक जैसे जरूरी सामानों के परिवहन के लिए अहम हैं। क्षमता बढ़ने के बाद हर साल करीब 600 लाख टन अतिरिक्त ढुलाई संभव होगी, जिससे उद्योगों की सप्लाई चेन मजबूत होगी और लागत में कमी आएगी। पर्यटन के लिहाज से भी महत्व है। महाकालेश्वर, रणथंभौर, कूनो और केवलादेव जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों के साथ मथुरा-वृंदावन, नैमिषारण्य और दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन परियोजनाओं को पीएम-गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और लाजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाना है। समेकित योजना और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही निर्बाध हो सके।

पर्यावरण के मोर्चे पर भी यह कदम महत्वपूर्ण है। रेलवे को ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल परिवहन माना जाता है। इन परियोजनाओं के जरिये देश को हर साल 37 करोड़ लीटर तेल आयात में कमी और 185 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी, जो करीब सात करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल किया

प्रथम पृष्ठ से आगे

कैबिनेट ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 10 रुपये बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इससे गन्ना उत्पादक किसानों को एक लाख करोड़ से अधिक का लाभ मिलने की उम्मीद है। मंजूर किया गया एफआरपी मौजूदा 2025-26 सत्र की दर (355 रुपये प्रति क्विंटल) से 2.81 प्रतिशत अधिक है। सत्र 2026-27 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 182 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, वहीं निर्धारित एफआरपी उत्पादन लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक है। चीनी मिलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसानों से गन्ना एफआरपी या उससे अधिक कीमत पर खरीदें।

देश को इसी महीने मिलेगा पहला 'ज्वाइंट आपरेशंस कंट्रोल सेंटर'

सैन्य शक्ति का महासंगम

- 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान एक एकीकृत कमान की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की गई
- इसी अनुभव को आधार बनाकर सीडीएस के नेतृत्व में जेओसीसी की परिकल्पना की गई है

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय रक्षा इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात होने जा रहा है। पिछले वर्ष मई में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध चलाए गए 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान मिली सीख के तहत भारतीय सेनाएं इसी महीने दिल्ली कैंट में अपने पहले ज्वाइंट आपरेशंस कंट्रोल सेंटर (जेओसीसी) को क्रियान्वित करने के लिए तैयार हैं। यह केंद्र केवल ईंट-पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि थल, नभ और जल की संयुक्त सैन्य शक्ति का वह 'मस्तिष्क' होगा, जो किसी भी भावी चुनौती का उत्तर एक स्वर में देगा।

पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए जब भारत ने 'आपरेशन सिंदूर' चलाया, तो एक एकीकृत कमान की आवश्यकता शिद्दत से महसूस की गई। इसी अनुभव को आधार बनाकर सीडीएस के नेतृत्व में जेओसीसी की परिकल्पना की गई है। यहां तीनों सेनाओं के जांबाज अधिकारी और जवान कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे, जिससे युद्ध की स्थिति में शीर्ष कमांडरों को एक ही स्थान पर पूरी सैन्य स्थिति की स्पष्ट और एकीकृत तस्वीर मिल सकेगी। इतना ही नहीं, सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए भविष्य में एक भूमिगत 'कमांड एंड कंट्रोल सेंटर' बनाने की योजना भी पाइपलाइन में है।

सैन्य सुधारों की यह बयार यहीं नहीं रुकती। जयपुर में सात-आठ मई को होने जा रहे 'ज्वाइंट कमांडर्स कान्फ्रेंस' में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष थिएटर कमांड्स का रोडमैप पेश किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार, उत्तरी, पश्चिमी और समुद्री खतरों से निपटने के लिए जयपुर, लखनऊ और तिरुअनंतपुरम में विशेष थिएटर कमांड स्थापित किए जा सकते हैं। इन कमांड्स का नेतृत्व फोर-स्टार रैंक के अधिकारियों के हाथों में होगा। यह बदलाव न केवल सैन्य परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि आधुनिक युद्धक्षेत्र में भारत की स्थिति को एक अजेय महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। यह कदम उन ताकतों को कड़ा संदेश है जो भारत की शांति को भंग करने का दुस्साहस करते हैं।

भारतीय सेना की यह नई रणनीति न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि देश की रक्षा क्षमताओं को भी एक नई दिशा प्रदान करेगी। भारत सैन्य ढांचे में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, जो भविष्य में किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेगा।

पंजाब व हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जजों की नियुक्ति की सिफारिश

नई दिल्ली, आइएएनएसः प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा तथा आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कहा कि चार मई को हुई अपनी बैठक में उसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तीन अधिवक्ताओं प्रविन्द्र सिंह चौहान, राजेश गौर और मिंदरजीत यादव की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजों के रूप में सात और अधिवक्ताओं की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। इनमें मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक शामिल हैं। इसके अलावा, कोलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतलपुडी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया के अनुसार, नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा आरंभ किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री किसी नाम की अनुशंसा करना चाहते हैं, तो उसे विचारार्थ मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए।

शोध और नवाचार में निजी क्षेत्र भी बढ़ाए निवेश : प्रधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आइआइटी मद्रास के समिट को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया संबोधित

नई दिल्ली में आइआइटी मद्रास की समिट में एक स्टाल पर जानकारी लेते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व जयंत चौधरी। एएनआइ

देश में शोध और नवाचार के प्रति बढ़ते रुझान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निजी क्षेत्र से भी शोध व नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने की वकालत की। साथ ही कहा कि देश में शोध के क्षेत्र में अभी होने वाले निवेश की करीब 70 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से दी जाती है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा का कोई कमी नहीं है, सिर्फ जरूरत है कि शोध व नवाचार की प्रक्रिया को अत्याधुनिक बनाया जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान मंगलवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आइआइटी मद्रास के टेक्नोलाजी समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने शोध व नवाचार के लिए दी जाने वाली वित्तीय मदद में काफी बढ़ोतरी की है लेकिन इंडस्ट्री का योगदान बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शोध व नवाचार की रफ्तार को और गति देने के लिए जरूरी है कि सरकार के साथ निजी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी आगे आएं। दोनों के बीच यह योगदान 50-50 पार्टनरशिप की ओर बढ़ना चाहिए। समिट को केंद्रीय कौशल विकास व शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी संबोधित किया।

सबरीमाला केस में सीजेआइ का सवाल, क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले में इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन की याचिका पर उठाए सवाल
- कहा- क्या आपके पास कोई और काम नहीं है, आपको वकीलों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती देने के मामले में इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन की जनहित याचिका पर बुधवार को सवाल उठाया और कड़ी टिप्पणियां भी कीं। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत ने एसोसिएशन की पैरोकारी कर रहे वकील से सवाल किया कि क्या आप देश के मुख्य पुजारी हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या आप जैसी संस्था की कोई आस्था हो सकती है? यह तो किसी व्यक्ति की होती है। न्यायिक संस्था का अंतरात्मा नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि उसे ऐसी जनहित याचिका दाखिल करने के बजाय वकीलों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ आजकल धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव के मुद्दे पर विचार कर रही है। इस मामले की शुरुआत केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले से हुई थी। मूल याचिका इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन ने दाखिल की थी, जिस पर 2018 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में प्रतिबंध को गलत ठहराया था। इस फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाएं लंबित हैं। इस मामले को नौ न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिए भेज दिया गया था।

> यह मामला काफी गंभीर है। जिन लोगों की देवता में आस्था है, वे सभी वो कार्य करेंगे जो आवश्यक हैं। लेकिन कोई कहता है कि वह सभी नियम तोड़ देगा, तो यह अदालत इसे बढ़ावा नहीं दे सकती। आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की देवता में क आस्था या विश्वास नहीं है, उन्हें प्रवेश करने दिया जाए तो आप सच्चे आस्थावान नहीं हैं।
>
> - जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुनवाई पीठ की अगुआई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं और पीठ में न्यायाधीश बीवी नागरत्ना, एमएम सुंद्रेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, एजी मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. माधवन और जोयमाल्या बागची शामिल हैं।

बुधवार को इंडियन यंग लायर्स एसोसिएसन के वकील रवि प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जून, 2006 में अखबार में चार लेख छपे थे। उन्होंने उन लेखों का विवरण दिया, जिनमें ज्योतिषियों ने कहा था कि एक महिला के मंदिर में प्रवेश करने के बाद वह पवित्र स्थल अपवित्र हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे चार नए न्यायाधीश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी, चीफ जस्टिस समेत अब न्यायाधीशों की कुल संख्या 38 हो जाएगी

सुप्रीम कोर्ट।

संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया जाएगा

न्याय को गति देने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी। चार न्यायाधीशों के बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सीजेआइ को मिला कर न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम 1956 में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यानी चीफ जस्टिस को मिला कर सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 हो जाएगी जो कि अभी 34 है। न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारियों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर होने वाला व्यय भारत की संचित निधि से पूरा किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रविधान किया गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश व संसद के कानून द्वारा अधिक संख्या निर्धारित न किये जाने तक सात से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे यानी सीजेआइ को मिला कर आठ न्यायाधीश होंगे। इसके बाद 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए अधिनियम पारित किया गया।

सुनवाई

कहा- सांसद, मंत्री, जज व अन्य ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी ही इस सम्मानसूचक संबोधन के हकदार

सिविल सेवकों को 'माननीय' लिखना उचित नहीं : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

- सांसद, मंत्री, जज व अन्य पदाधिकारी सम्मानसूचक संबोधन के हकदार
- निजी नाराजगी के आधार पर संवैधानिक पदाधिकारी को वैधानिक संबोधन से वंचित नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि संप्रभु कार्यों का निर्वहन करने वाले संवैधानिक दायित्व धारियों को प्रत्येक आधिकारिक संचार माध्यमों में 'माननीय' संबोधन दिया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सांसद, मंत्री, जज तथा अन्य ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी इस सम्मानसूचक संबोधन के हकदार हैं, जबकि किसी भी रैंक के सिविल सेवक इस विशेष संबोधन के पात्र नहीं हैं। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति की निजी नाराजगी या पारिवारिक परिचय के आधार पर किसी संवैधानिक पदाधिकारी को उसके वैधानिक सम्मानसूचक संबोधन से वंचित नहीं किया जा सकता।

मथुरा निवासी हर्षित शर्मा व दो अन्य की आपराधिक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा, 'केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष/सभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष तथा सांसद एवं विधायक 'माननीय' संबोधन के अधिकारी हैं।' प्रोटोकाल के अनुसार अन्य समान पदाधिकारी भी इस सम्मान के पात्र हो सकते हैं और जो भी इसके हकदार हों, उन्हें उसी प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। इससे पहले 31 मार्च को सुनवाई के समय अदालत ने पुलिस द्वारा एफआइआर में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम से पहले माननीय न उल्लेखित किए जाने पर आपत्ति जताई थी। अपर मुख्य सचिव (गृह) से स्पष्टीकरण तलब किया था।

इसी क्रम में 30 अप्रैल को दायर हलफनामे में बताया गया कि वादी मुकदमा खजान सिंह ने टाइपशुदा शिकायत में अनुराग ठाकुर के नाम के साथ माननीय नहीं लिखवाया था। वही विवरण हूबहू एफआइआर में दर्ज कर लिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसे सांसदों या पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के लिए ऐसे प्रोटोकाल की जानकारी नहीं थी।

इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सांसद होने के नाते अनुराग ठाकुर 'माननीय' संबोधन के पूर्णतः अधिकारी हैं। माननीय शब्द केवल उन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों के नाम के साथ लगाया जाना चाहिए, जो शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हालांकि यह सम्मानसूचक संबोधन सिविल सेवकों पर लागू नहीं होता है, चाहे उनका पद कितना भी ऊंचा क्यों न हो। इस पहलू पर राज्य सरकार और प्रतिवादी पक्ष द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामों को रिकार्ड पर लेते हुए अदालत ने विवाद का यह भाग समाप्त कर दिया। मुख्य मामला आपराधिक धमकी और आपराधिक न्यासभंग से संबंधित एफआइआर रद कराने की याचिका से जुड़ा है। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम प्राथमिकी में उल्लेखित है। हालांकि उन्हें आरोपित नहीं बनाया गया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

323 वोटों से विजयी घोषित हो गए थे राजारहाट-न्यूटाउन सीट पर पहले तृणमूल प्रत्याशी तापस बनर्जी। दोबारा मतगणना के बाद भाजपा के पीयूष कनोड़िया को 316 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। इससे भाजपा की सीटों की संख्या बढ़कर 207 हो गई है।

शाह ने ऐसे लिखी ममता की हार की पटकथा

भवानीपुर के लिए बनाई अलग टीम, सीधे लेते रहे रिपोर्ट

नीलू रंजन ● जागरण

नई दिल्ली: भाजपा के 'चाणक्य' कहे जाने वाले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस बार जब बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू की थी तो उसी वक्त यह तय कर लिया था कि न सिर्फ तृणमूल, बल्कि पार्टी का सबसे सशक्त चेहरा ममता बनर्जी को भी उनके ही गढ़ भवानीपुर में हराना होगा। लिहाजा, शुरूआत से ही इसकी पटकथा लिखी गई और हर कोण से निर्देशन शाह का रहा। मतदान के आखिरी पल तक वह खुद इस सीट पर हो रही हर गतिविधि की जानकारी लेते रहे। इसके पहले, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी शाह की सूक्ष्म प्लानिंग अरविंद केजरीवाल की हार सुनिश्चित करने में सफल रही थी।

पश्चिम मेदिनीपुर में चुनावी जनसभा के दौरान समर्थकों में जोश भरते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। फाइल

ममता बनर्जी न सिर्फ 15 वर्षों से भवानीपुर से विधायक रहीं, बल्कि उनका घर भी वहीं है। उनको उनके ही घर में हराना आसान नहीं था, लेकिन अमित शाह की व्यूह रचना ने इसे संभव कर दिखाया। रणनीति में जुड़े विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, चुनाव की घोषणा होते ही शाह ने नंदीग्राम में 2021 में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी से कहा कि राजनीतिक लड़ाई के लिए बल दिखाना होता है। पिछली बार ममता आपके क्षेत्र में आई थीं, इस बार आप उनके गढ़ में जाओ और हराओ ताकि समर्थकों और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखा जा सके।

सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारने के बाद शाह ने भवानीपुर के लिए अपने सबसे विश्वस्त लोगों की एक अलग टीम बनाई थी, जो पार्टी को नहीं, बल्कि सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थी। शाह 15 दिन कोलकाता में रहे। वहां रहते हुए हर रात भवानीपुर सीट को लेकर बैठक करते थे। इस सीट पर गुजराती समाज के लगभग 25 हजार और मारवाड़ी समाज के लगभग 21 हजार मतदाता हैं, जो चुनाव में निर्णायक साबित हो सकते थे। शाह ने दोनों समाजों के लोगों के साथ अलग-अलग बैठकें और डिनर किए।

इन लोगों ने शाह को बताया कि ममता बनर्जी के गुंडे उन्हें वोट नहीं डालने देते, उनके नाम पर छापा (फर्जी) वोट पड़ जाता है। उनकी सोसायटियों को सुरक्षा मिलेगी, तभी वे वोट डाल पाएंगे। गृहमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि भवानीपुर में हर जगह सुरक्षा हो, ताकि सभी वोट डाल पाएं और एक भी फर्जी वोट न पड़े। गौरतलब है कि एसआइआर में भवानीपुर से लगभग 47 हजार मतदाताओं के नाम कटे। इनमें मर चुके, डुप्लिकेट वोट शामिल थे। पहले टीएमसी के गुंडे इनके नाम पर फर्जी वोट डालते थे।

शाह ने भवानीपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं और बूथ इंचार्ज के बीच समन्वय भी सुनिश्चित किया। उन्होंने अपनी टीम से ही भवानीपुर के हर बूथ का इंचार्ज बनाया। इसका उद्देश्य था कि अगर पार्टी के अंदर कहीं भी मतभेद उभरे, तो उसकी सूचना तत्काल उन्हें मिल सके। साथ ही, ये इंचार्ज हर बूथ पर टीएमसी के गुंडों पर नजर रखते थे, ताकि उनके सक्रिय होने की स्थिति में सीधे शाह को इसकी सूचना दी जा सके। पिछले चुनावों में मतदान के दिन दोपहर बाद टीएमसी के गुंडों के सक्रिय होने को देखते हुए शाह ने भाजपा समर्थक सभी मतदाताओं का 11 बजे से पहले वोट डालने का लक्ष्य दिया। परिणाम यह हुआ कि भाजपा समर्थक सभी मतदाता 12 बजे तक वोट डाल चुके थे।

शाह बंगाल तो नड्डा बने असम के पर्यवेक्षक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा व राजग को तीन राज्यों में बहुमत मिला है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में राजग के सहयोगी दल एआइएनआरसी के एन. रंगासामी का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है। अब तैयारी बंगाल और असम में सरकार के गठन को लेकर है। इन राज्यों में विधायक दल के नेता का चुनाव कराने के लिए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने अति वरिष्ठ नेताओं को जिम्मा सौंपा है। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह और असम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। नौ मई को शपथ ग्रहण संभव है।

- **विधायक दल नेता का चुनाव कराने जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता, नौ मई को शपथ ग्रहण संभव**

बंगाल में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 293 में से 207 विधानसभा सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। यहां तृणमूल कांग्रेस का मजबूत किला ढहाने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में ऐसा विकल्प राज्य को देना चाहती है, जो यहां पुरानी शासन व्यवस्था का स्वरूप बदले और केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। इस दौड़ में सबसे आगे सुवेंदु अधिकारी का नाम चल रहा है, जिन्होंने भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया है। इस बेहद महत्वपूर्ण माने जाने वाले राज्य में विधायक दल के नेता का चुनाव कराने के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड ने अमित शाह को पर्यवेक्षक, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

इसी तरह असम में भाजपा ने लगातार तीसरी बार बहुमत प्राप्त किया है। 126 सीटों में से 82 सीटें जीतने वाले राजग की अगली सरकार की कमान किसके हाथों में होगी, वैसे इसे लेकर खास संशय किसी को नहीं है।

बंगाल में नौ मई को होगा भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- **प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दी जानकारी, पीएम मोदी, शाह समेत भाजपा शासित राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद**
- **कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में हो सकता है भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन**

बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी तय हो गई है। नई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आगामी नौ मई को कविगुरु रवींद्र नाथ टैगोर की जयंती के दिन आयोजित किया जाएगा। चुनाव नतीजों के एक दिन बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में इसकी जानकारी दी। नए मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।

पार्टी के संसदीय बोर्ड ने गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल में भाजपा विधायक दल का नेता यानी नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए मंगलवार को केंद्रीय पर्यवेक्षक जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माजी को सह-पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में होने की संभावना है। हालांकि भाजपा ने स्थान की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भट्टाचार्य ने बताया कि नौ मई का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उस दिन कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। राजाराम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्रनाथ जैसी महान हस्तियों की यह भूमि है। राज्य की इसी गरिमा और पहचान को फिर से स्थापित करने की दिशा में नई सरकार काम करेगी।

राइटर्स बिल्डिंग से चलेगी नई भाजपा सरकार : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि नई भाजपा सरकार का संचालन राइटर्स बिल्डिंग (पुराने राज्य सचिवालय) से किया जाएगा। यानी ममता बनर्जी ने जिस नबान्न बिल्डिंग (नए राज्य सचिवालय) से 15 साल तक राज्य में शासन चलाया, उसकी जगह भाजपा पुराने राज्य सचिवालय से सत्ता चलाएगी। बता दें, 2011 में लगातार 34 साल के वाममोर्चा शासन का अंत कर सत्ता में आने के बाद ममता राज्य सचिवालय को राइटर्स बिल्डिंग से स्थानांतरित कर नबान्न में लेकर चली गई थीं। अब प्रचंड जीत के बाद भाजपा खुद को बंगाली संस्कृति के करीब दिखाना चाहती है, इसलिए वह नई सरकार का राज्य सचिवालय फिर से राइटर्स बिल्डिंग में बनाना चाहती है।

बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा, टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ व आगजनी

जासं, दुर्गापुर : बंगाल के आसनसोल-दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में मतगणना के बाद राजनीतिक हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। बाराबनी, सालानपुर, जामुड़िया और दुर्गापुर समेत विभिन्न इलाकों में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। कुछ जगहों पर फायरिंग की भी सूचना है। कई स्थानों पर भाजपा समर्थकों पर इन घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है, हालांकि भाजपा ने इससे दूरी बना ली है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि टीएमसी के ही कुछ कार्यकर्ता चोला बदलकर ऐसा कर रहे हैं।

बताया गया कि बाराबनी विधानसभा क्षेत्र के सालानपुर और पानुरिया में टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई, जबकि रूपनारायणपुर में भी हमला हुआ। जामुड़िया के ईस्ट केंदा, चाकदोला मोड़, परसिया कोलियरी, पुनिआरटी और खास केंदा सहित कई जगहों पर कार्यालयों में घुसकर कुर्सी, टेबल, पोस्टर व दस्तावेज नष्ट किए गए और कई स्थानों पर आग लगा दी गई।

तृणमूल के वोट पर पड़ गई एसआइआर की चोट

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

- **सीमावर्ती जिलों में पहुंचा सबसे अधिक नुकसान, 147 विस सीटों पर 25,000 से अधिक नाम हटाए गए**

बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया से तृणमूल कांग्रेस को विस चुनाव में सीटों का भारी नुकसान पहुंचा है जबकि भाजपा के लिए यह फायदेमंद साबित हुई है। समीक्षा के मुताबिक बंगाल की 147 विस सीटों पर 25,000 से अधिक नाम हटाए गए। इनमें से बड़ी संख्या में सीटें भाजपा के खाते में गईं। उसने 147 में से 95 सीटें जीतीं, जबकि तृणमूल को सिर्फ 51 सीटें मिलीं। वहीं, कांग्रेस के हिस्से में एक सीट आई। 67 सीटें ऐसी रहीं, जहां 15,000 से 25,000 तक नाम कटे। वहां भी भाजपा आगे रही। उनमें से 47 सीटों पर भाजपा जीती। तृणमूल की झोली में मात्र 19 सीटें आईं और कांग्रेस को एक सीट मिली। 62 सीटों पर 5,000 से 15,000 के बीच नाम कटे। इनमें से 50 सीटें भाजपा ने जीतीं और बाकी 12 तृणमूल के पास गईं। वहीं जिन 13 सीटों पर 5,000 से कम नाम हटे, वे सभी भाजपा ने जीतीं।

एसआइआर में सबसे अधिक 'अपात्र' मामले मुर्शिदाबाद जिले से सामने आए। वहां 4.55 लाख से अधिक नाम कटे। उसके बाद उत्तर 24 परगना जिले में 3,25,666 व मालदा में 2,39,375 नाम मतदाता सूची से हटाए गए। मुर्शिदाबाद में तृणमूल ने 2021 में 22 में 20 सीटें जीती थीं, जो इस बार घटकर नौ रह गईं। यह आंकड़ा अल्पसंख्यक वोटों में बंटवारे और हिंदू वोटों के भाजपा के पक्ष में एकजुट होने का परिणाम है। वहीं, उत्तर 24 परगना की 33 सीटों में तृणमूल ने 2021 में 28 सीटें जीती थीं, जो इस बार आठ पर सिमट गईं। इसी तरह मालदा की 12 सीटों में तृणमूल का आंकड़ा आठ से घटकर छह रह गया। बाकी चार सीटें भाजपा ने जीत लीं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं, जहां सबसे अधिक नाम कटने के बावजूद तृणमूल को जीत हासिल हुई है।

...तो मुस्लिम वोटरों ने ही ढहा दिया ममता का अभेद्य दुर्ग

जयकृष्ण वाजपेयी ● जागरण

- **बंगाल में बदला वोट का समीकरण, सीमावर्ती जिलों के नतीजों ने तोड़ी पारंपरिक धारणाएं**
- **बांग्लादेशी घुसपैठिये का बोझ ढोने को अब तैयार नहीं मूल निवासी**

कोलकाता: बंगाल विस चुनाव के ताजा नतीजों ने राज्य की पारंपरिक राजनीतिक धारणाओं को चुनौती दी है। खासकर उन जिलों में, जहां दशकों से एकतरफा मतदान पैटर्न देखने को मिलता रहा था, इस बार अप्रत्याशित बदलाव सामने आया है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर व उत्तर व दक्षिण 24 परगना जैसे सीमावर्ती और मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा का प्रदर्शन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए अध्ययन का विषय बन गया है। बंगाल की राजनीति में दशकों से एक अलिखित सत्य रहा है- 'जिसका मुस्लिम वोट, उसकी सत्ता।' लेकिन हालिया चुनावी आंकड़ों ने इस धारणा की चूलें हिला दी हैं।

प्रतीकात्मक

मुर्शिदाबाद का 'मिराज' : 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी और आठ भाजपा सीटें : कभी कांग्रेस तो कभी वाम और पिछले लोकसभा चुनाव तक ममता का सबसे सुरक्षित किला माना जाने वाला मुर्शिदाबाद जिला आज चर्चा के केंद्र में है। 70 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाले इस जिले में भाजपा का दो से बढ़कर आठ सीटों पर पहुंचना कोई सामान्य घटना नहीं है। जंगीपुर (62 प्रतिशत मुस्लिम) और बेलडांगा जैसे क्षेत्रों में भाजपा की जीत यह बताती है कि मतदाता अब केवल मजहबी पहचान के आधार पर वोट नहीं कर रहा। इसी तरह मालदा की 12 सीटों में से छह और उत्तर दिनाजपुर की नौ में से चार सीटों पर भाजपा की जीत इस बात का संकेत देती है कि मतदाताओं के व्यवहार में बदलाव आया है। विपक्षी दलों के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा-कांग्रेस, वाममोर्चा, आइएसएफ और अन्य दलों द्वारा बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से वोटों का ध्रुवीकरण कमजोर हुआ। तृणमूल ने भी 45 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 31 जीते। इस परिणाम का सबसे चौंकाने वाला पहलू 'घुसपैठ' के मुद्दे पर उपजी आंतरिक सुगबुगाहट है। हालांकि, कोई खुलकर बात तो नहीं करते लेकिन अंदरखाने चर्चा है। राजनीतिक गलियारों में यह प्रश्न तैर रहा है कि क्या बंगाल का 'मूल निवासी' मुसलमान अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोझ मानने लगा है? विश्लेषण बताता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन, रोजगार की कमी और बढ़ते अपराध ने स्थानीय मुस्लिमों के मन में असुरक्षा पैदा की है।

डनैरेटिव की हार : 'प्रवासी श्रमिक' बनाम 'कुशासन'

ममता ने चुनाव के दौरान भाजपा शासित राज्यों में बांग्लाभाषी श्रमिकों के उत्पीड़न का मुद्दा खूब उछाला था। उन्होंने इसे बंगाली अस्मिता और सुरक्षा से जोड़ा, लेकिन जमीन पर स्थिति भिन्न थी। भ्रष्टाचार, स्थानीय स्तर पर सिंडिकेट राज और विकास की धीमी गति ने उस नैरेटिव को कमजोर कर दिया। एक वरिष्ठ वामपंथी मुस्लिम नेता का यह स्वीकार करना कि 'मुस्लिमों ने ममता के कुशासन से तंग आकर भाजपा को चुना,' इस बात की पुष्टि करता है कि अब 'डर की राजनीति' की एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। मुस्लिम बहुल जिलों में भाजपा का परचम लहराना यह साबित करता है कि बंगाल अब 'पहचान की राजनीति' से निकलकर 'अस्तित्व की राजनीति' की ओर बढ़ रहा है। यदि बंगाल का मुसलमान घुसपैठ के मुद्दे पर खड़ा हो रहा है, तो यह भारतीय राजनीति के लिए सबसे बड़ा 'टर्निंग पाइंट' हो सकता है। यह चुनाव परिणाम ममता के लिए चेतावनी है और भाजपा के लिए एक नई जिम्मेदारी। क्या भाजपा इस भरोसे को बरकरार रख पाएगी? और क्या बंगाल का मुस्लिम समाज 'घुसपैठ' के कलंक से खुद को अलग करने की दिशा में यह कदम बढ़ा चुका है? जवाब आने वाले समय के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल बंगाल की आबो-हवा बदल चुकी है।

आयोग की 'तिकड़ी' ने बंगाल में किया कमाल

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) व उसके बाद शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से मतदान व मतगणना संपन्न कराने में राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता व पुलिस पर्यवेक्षक एनके मिश्रा की 'तिकड़ी' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनोज अग्रवाल ने बंगाल की परिस्थितियों के मुताबिक सही समय पर चुनाव आयोग से सही सिफारिशें कीं। चुनाव आयोग ने भी उनपर गंभीरता से ध्यान देते हुए उन्हें कड़ाई से लागू कराया। अग्रवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पसंदीदा अधिकारियों में से एक माने जाते हैं। वहीं सुब्रत गुप्ता ने पहले एसआइआर की प्रक्रिया में रोल पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी निभाई। उनकी कार्य दक्षता देखकर बाद में उन्हें चुनाव में विशेष पर्यवेक्षक का दायित्व सौंपा गया। इसे भी उन्होंने प्रभावी तरीके से अंजाम दिया।

वहीं, 1988 के सिक्किम बैच के अधिकारी व वर्तमान में सेवानिवृत्त आइपीएस एनके मिश्रा ने पुलिस पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। मिश्रा केंद्र में खुफिया विभाग में लंबे समय तक काम कर चुके हैं।

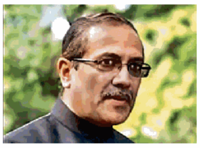

एनके मिश्रा

सुब्रत गुप्ता

- **एसआइआर, शांतिपूर्ण मतदान व मतगणना कराने में सीईओ, विशेष पर्यवेक्षक व पुलिस पर्यवेक्षक ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका**
- **इन्होंने बंगाल विधानसभा चुनाव से संबंधित हर एक पहलू को बारीकी से समझा और सही समय पर सही कदम उठाया**

मनोज कुमार अग्रवाल

बंगाल में भी काम करने का उन्हें सात-आठ वर्षों का अनुभव रहा है इसलिए यहां की परिस्थितियों से भली-भांति परिचित हैं। इस तिकड़ी ने बंगाल चुनाव से संबंधित हरेक पहलू को बारीकी से समझा और सही समय पर सही कदम उठाया। मालूम हो कि बंगाल में दशकों बाद हिंसा-मुक्त मतदान हुआ। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा में राज्य में 24 लोगों की मौतें हुई थीं।

नियमित पूजा के लिए आसनसोल में खोला गया बस्तिन बाजार दुर्गा मंदिर

जागरण संवाददाता, आसनसोल

2009 के बाद से दुर्गा, लक्ष्मी व काली पूजा में सीमित दिनों के लिए ही खोला जाता था मंदिर

बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत के बाद लंबे समय से बंद पड़े बस्तिन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए सोमवार की शाम खोल दिया गया। इधर, मंदिर का ताला खुलते ही घंटी की आवाज के साथ-साथ जय श्रीराम के नारे गूंजने लगे।

आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र स्थित श्री श्री दुर्गामाता चैरिटेबल ट्रस्ट के इस मंदिर में 2009 के बाद से ही नियमित पूजा बंद थी। केवल दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और काली पूजा के दौरान सीमित दिनों के लिए ही मंदिर खोला जाता था।

सोमवार को आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी की जीत की घोषणा हुई। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता व सनातनी संगठनों के लोग मंदिर पहुंचे और विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना शुरू कर मंदिर को खोल दिया।

मंगलवार को भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब मंदिर नियमित रूप से खुलेगा और पूजा होगी। इस वर्ष मंदिर अपने निर्माण के 75 वर्ष भी पूरे कर रहा है, जिससे इसकी महत्ता और बढ़ गई है।

बताते चलें कि बंगाल चुनाव के दौरान बस्तिन बाजार दुर्गा मंदिर चर्चा में था। आसनसोल की चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी अपने भाषण में मंदिर का जिक्र किया था। वहीं, मंदिर खोले जाने के बाद भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि एक समुदाय विशेष को खुश रखने के लिए तृणमूल सरकार ने मंदिर को बंद रखा था।

इधर, ट्रस्ट के प्रमुख संजय अग्रवाल के अनुसार नई सरकार के गठन के बाद सरकार के स्तर से विधिवत पत्र मिलने के बाद मंदिर के विकास को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

आसनसोल के बस्तिन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालु। जागरण

ऐतिहासिक हार

1984 के बाद पहली बार किसी संवैधानिक पद पर नहीं, भवानीपुर ने 'घर की बेटी' से ही मोड़ा मुंह

ममता बनर्जी की राजनीतिक यात्रा का 'ट्रैजिक' मोड़

इंद्रजीत सिंह ● जागरण

कोलकाता : बंगाल की राजनीति में 'दीदी' के नाम से मशहूर ममता बनर्जी के लिए 2026 का विधानसभा चुनाव एक ऐतिहासिक और भावनात्मक झटका लेकर आया। 'मैं यह लड़ाई अकेले लड़ूंगी'-चुनाव से पहले उनका यह आत्मविश्वास भरा बयान अब उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज हो गया है। भवानीपुर, जिसे तृणमूल का अभेद्य किला माना जाता था, वहीं से भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने ममता को 15,105 वोटों से करारी शिकस्त दी।

- **भवानीपुर को तृणमूल कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था, वहीं से भारतीय जनता पार्टी के के सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से करारी शिकस्त दी है**

ममता बनर्जी। फाइल

आवास के बाहर से हटे बैरिकेड, बदला माहौल

मुख्यमंत्री व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित आवास के बाहर वर्षों से लगे बैरिकेड्स को आंशिक रूप से हटा दिया गया है। यह कदम तृणमूल कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने और भवानीपुर सीट से उनकी हार के एक दिन बाद उठाया गया। मंगलवार सुबह कोलकाता पुलिस के कर्मियों को हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर स्थित उनके 30बी आवास के पास लगे नीले-सफेद गार्डरेल्स को हटाते देखा गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें मंगलवार सुबह उच्च अधिकारियों के निर्देश पर स्मार्ट बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया। इलाके में पुलिस की एक चौकी अभी भी मौजूद है, लेकिन पहले की तुलना में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था अब काफी कम दिख रही है।

2021 में नंदीग्राम से हार के बाद ममता बनर्जी ने उपचुनाव में भवानीपुर से जीत दर्ज की थी। उस समय नारा था-बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। 2026 में यही नारा 'भवानीपुर की अपनी बेटी' बन गया, लेकिन इस बार जनता ने इसे नकार दिया। ममता ने घर-घर जाकर प्रचार किया, छोटी बैठकों, चाय-चर्चा और व्यक्तिगत संपर्क पर जोर दिया, फिर भी नतीजा उनके खिलाफ गया। वर्ष 1984 में सांसद बनने के बाद पहली बार वह किसी संवैधानिक पद पर नहीं हैं। चार मई की रात ने बंगाल की राजनीति को यह दिखा दिया कि कभी अजेय मानी जाने वाली नेता भी समय के साथ चुनौती का सामना करती है। यह हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि एक लंबे राजनीतिक अध्याय के 'ट्रैजिक' मोड़ की कहानी बन गई है।

बता दें कि 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कर ममता ने बंगाल की राजनीति में नया अध्याय लिखा। 34 वर्षों के लंबे वाम शासन को उखाड़ फेंक 2011 में वह बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है।

आउसग्राम में घरेलू सहायिका कलिता भी बनीं विधायक

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर

- **पीएम भी कलिता की दृढ़ इच्छाशक्ति और संघर्ष की कर चुके हैं सराहना**

पूर्व बर्द्धमान जिला की आउसग्राम सीट पर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस सीट पर पहली बार कमल खिला है। भाजपा प्रत्याशी कलिता माझी ने अपने प्रतिद्वंद्वी तृणमूल कांग्रेस के श्यामा प्रसन्न लोहार को 12,535 मतों के अंतर से करारी शिकस्त दी है। कलिता पूर्व में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और संघर्ष की सराहना कर चुके हैं। 2021 में भी कलिता आउसग्राम सीट से उम्मीदवार थीं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें जीत का ताज पहनाया है। कलिता को कुल 1,07,692 मत प्राप्त हुए। उन्होंने कुल मतदान का 47.68 प्रतिशत वोट अपने नाम किया। वहीं, दूसरे स्थान पर रहे तृणमूल कांग्रेस के श्यामा को कुल 95,157 वोट मिले, जिनमें 94,694 ईवीएम और 463 पोस्टल बैलेट वोट शामिल हैं।

कलिता माझी। जागरण

सीएम पद की रेस में सतीशन, वेणुगोपाल और चेन्निथला

केरल में नई सरकार के गठन को लेकर कोशिशें तेज

राज्य में यूडीएफ को मिली हैं 102 सीटें

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत के बाद कांग्रेस नेतृत्व के सामने मुख्यमंत्री चुनने की चुनौती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार नजर आ रहे हैं। इस बीच नई सरकार के गठन को लेकर कोशिशें तेज हो गई हैं। केरलम में विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीतीं, जबकि माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ को 35 सीटें मिलीं।

केरलम में मुख्यमंत्री पद के लिए तीन प्रमुख दावेदार हैं। इनमें विपक्ष के नेता वीडी सतीशान, कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला शामिल हैं।

इस बीच यूडीएफ की जीत के एक दिन बाद मंगलवार को वेणुगोपाल जब राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे तो हवाईअड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

वेणुगोपाल ने कहा, केरल की जनता ने कांग्रेस और यूडीएफ गठबंधन पर पूरा भरोसा जताया है। उन्हें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है।

लोग वाम मोर्चे की सरकार से तंग आ चुके थे। इसीलिए उन्होंने यूडीएफ को चुना। वेणुगोपाल ने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ कई बैठकें भी कीं।

रमेश चेन्नीथला, वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल (बाएं से)। फाइल

'विजयन के निरंकुश नेतृत्व ने एलडीएफ को पहुंचाया भारी नुकसान'

एएनआइ के अनुसार केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री पी. विजयन के "निरंकुश नेतृत्व" एलडीएफ की हार का प्रमुख कारण है। जोसेफ ने कहा कि निर्वाचित विधायकों से परामर्श करने के बाद पार्टी हाई कमान अगले मुख्यमंत्री चुनने को लेकर निर्णय लेगा। मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए जोसेफ ने कहा कि जनादेश एलडीएफ सरकार की नीतियों से जनता की असंतुष्टि को दर्शाता है।

केरलम के मुख्यमंत्री विजयन ने संदेशवाहक के जरिये राज्यपाल को भेजा इस्तीफा

तिरुअनंतपुरम, आइएएनएस : केरलम में विधानसभा चुनाव में वामदलों के गठबंधन एलडीएफ की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पी. विजयन ने राज्यपाल राजेंद्र वी. आर्लेकर को संदेशवाहक के जरिये सोमवार को ही इस्तीफा भेज दिया। राज्यपाल ने विजयन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राजभवन के अनुसार, राज्यपाल ने विजयन से अनुरोध किया है कि जब तक नई सरकार शपथ नहीं ले लेती और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वे अपने पद पर बने रहें, लेकिन विजयन ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर अब तक चुप्पी साधना ही बेहतर समझा है। हालांकि जब विजयन मंगलवार को कन्नूर से तिरुअनंतपुरम हवाईअड्डे पहुंचे और वहां से प्राइवेट वाहन में अपने आधिकारिक आवास क्लिफ हाउस के लिए रवाना हुए। इस दौरान सुरक्षा वाहनों का काफिला और कमांडो कवर नहीं था। इस बीच प्रेट्र के अनुसार केरलम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू. केलकर ने विधानसभा चुनावों में विजयी उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को सौंप दी।

पुडुचेरी का पांचवीं बार नेतृत्व करने को रंगासामी तैयार

पुडुचेरी, प्रेट्र: पुडुचेरी के शांत और मृदुभाषी मुख्यमंत्री एन रंगासामी पांचवीं बार इस केंद्र शासित प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी आल इंडिया एनआर कांग्रेस (एआइएनआरसी) के नेतृत्व वाले राजग ने विधानसभा चुनावों में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। यहां नौ अप्रैल को मतदान हुआ था और सोमवार को मतगणना हुई।

एआइएनआरसी ने 16 सीटों में से 12 पर जीत हासिल की है, जबकि 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने चार पर जीत दर्ज की है। राजग के अन्य घटक दलों अन्नाद्रमुक और एलजेके ने एक-एक सीट पर सफलता हासिल की। राजग के पास 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटें हैं, जो सरकार बनाने के लिए सामान्य बहुमत से दो अधिक हैं। जबकि अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली टीवीके दो सीटों पर विजयी रही। विपक्षी द्रमुक ने पांच सीटें जीतीं और कांग्रेस को एक सीट मिली।

75 वर्षीय रंगासामी पहले कांग्रेस में थे और इस पार्टी से (2001, 2006 में) दो बार मुख्यमंत्री रहे। 2011 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई। 2011 में रंगासामी ने दिवंगत तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक प्रमुख जे जयललिता से हाथ मिलाया और तब उनके गठबंधन ने चुनाव जीते, लेकिन बाद में उनके बीच संबंध बिगड़ गए। 2016 में वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। 2021 में उनकी पार्टी ने राजग के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा और चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। राज्य में दूसरी बार एआइएनआरसी नीत राजग ने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की है और यहां वह लगातार दूसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। रंगासामी के पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभालने की पूरी संभावना है।

30 सदस्यीय विधानसभा में राजग के खाते में आई हैं 18 सीटें

एन रंगासामी। फाइल

एआइएनआर सी के नेतृत्व वाले राजग ने लगातार दूसरी बार दर्ज की जीत

लाटरी किंग मार्टिन परिवार के तीन सदस्य बने विधायक

चेन्नई, प्रेट्र: लाटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के नेतृत्व वाले मार्टिन समूह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2026 विधानसभा चुनावों में इस बार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलिब्ध हासिल की है। मार्टिन परिवार के तीन सदस्यों ने विभिन्न दलों के टिकट पर सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अन्नाद्रमुक का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्टिन की पत्नी, लीमारोज ने तिरुचि जिले के लालगुडी विधानसभा क्षेत्र में एक करीबी मुकाबले में जीत हासिल की जबकि उनके बेटे जोस चार्ल्स मार्टिन ने पुडुचेरी के कमराज नगर क्षेत्र में एलजेके के बैनर तले चुनाव लड़ा और आसानी से जीत गये। इसी तरह सैंटियागो मार्टिन के दामाद आदव अर्जुन ने विजय की पार्टी टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ा। उन्होंने चेन्नई के विलिवक्कम विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, लीमारोज मार्टिन ने लालगुडी सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और टीवीके उम्मीदवार केयू पीए कृष्णन को 2,739 मतों के अंतर से हराया। जबकि जोस चार्ल्स मार्टिन ने कांग्रेस के उम्मीदवार पीके देवदास को 10,205 मतों के अंतर से हराया। इसी तरह आदव अर्जुन ने द्रमुक उम्मीदवार कार्तिक मोहन को 17,302 मतों के अंतर से हराया।

केरलम में अगले विधानसभा चुनाव में बड़ी ताकत बनेगी भाजपा : मुरलीधरन

- नवनिर्वाचित भाजपा विधायक कहा- सबरीमाला में सोने की चोरी के मुद्दे को उठाने से मिली मदद
- भाजपा ने केरलम विधानसभा चुनाव में पहली बार जीती हैं तीन सीटें

तिरुवनंतपुरम, एएनआइ : केरलम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित भाजपा विधायक वी. मुरलीधरन ने कहा है कि राज्य में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा बड़ी ताकत बनेगी। भाजपा ने राज्य में तीन सीटें जीतकर इतिहास रचा है। 2021 में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2016 में राज्य में पहली बार भाजपा को जीत मिली थी।

इस बार चुनाव जीतने वाले भाजपा विधायकों में केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन और बीबी गोपाकुमार शामिल हैं। इन विधायकों का मंगलवार को तिरुअनंतपुरम स्थित पार्टी कार्यालय में स्वागत किया गया।

मुरलीधरन ने कहा, केरल में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रमुख दल के रूप में उभरेगी। हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों और नीतियों के कारण केरलम की जनता ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। यह दर्शाता है कि केरल की राजनीति में बदलाव आ रहा है। प्रेट्र के अनुसार मुरलीधरन ने कहा कि राज्य में सत्ता विरोधी भावना और सबरीमाला में सोने की चोरी के मुद्दों को जोर शोर से उठाने से भाजपा को तीन सीटें जीतने में मदद मिली। मुरलीधरन ने कज़ाकूटम विधानसभा सीट 428 वोटों के अंतर से जीती है। एएनआइ के अनुसार राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रामक हथकंडों के माध्यम से कई सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने एफसीआरए से जुड़े झूठ और माकपा-भाजपा समझौते की मनगढ़ंत कहानी के जरिए कई सीटें जीती हैं।

चंद्रशेखर ने कहा, अब तक हम विधानसभा के बाहर से केरल की जनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगले पांच वर्षों तक तीन भाजपा विधायक विधानसभा में कांग्रेस और माकपा की संयुक्त ताकत का सामना करेंगे। हम राज्य के विकास के लिए जी जान से लड़ेंगे। भाजपा आने वाले वर्षों में भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ कड़ा संघर्ष करेंगे।

इस बीच प्रेट्र के अनुसार नेमोम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारने वाले केरलम के मंत्री वी. शिवनकुट्टी, जो ने मंगलवार को दावा किया कि यूडीएफ-भाजपा के बीच हुए डील के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

वी. मुरलीधरन। फाइल

बंगाल की जीत पर ट्रंप ने मोदी को दी बधाई

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

वाशिंगटन, आइएएनएस: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है। व्हाइट हाउस ने ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत बताया है।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, "पिछले महीने फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत सौभाग्यशाली है कि उसका नेतृत्व आप जैसे नेता के हाथों में है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस हालिया ऐतिहासिक और निर्णायक चुनावी जीत के लिए बधाई दी है।

सिर्फ एक वोट से हारे तमिलनाडु के मंत्री

30 मतों से चल रहे थे आगे, आखिरी राउंड में हुए पराजित

- प्रदेश में 10 से अधिक उम्मीदवार 1000 से कम वोटों से हारे
- सिर्फ 285 मतों से जीते पलानीस्वामी, स्टालिन के 15 प्रमुख मंत्री हारे

शिवगंगा, एएनआइ : चुनाव में हर एक वोट मायने रखता है! यह बात एमके स्टालिन सरकार में सहकारिता मंत्री रहे केआर पेरियाकरुप्पन से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। जिले की तिरुपत्तूर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर में वह तमिलगा वेत्री कणगम (टीवीके) प्रत्याशी सीनिवास सेतुपति से सिर्फ एक वोट से हार गए।

पेरियाकरुप्पन 20 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनकी यह पराजय देश के चुनावी इतिहास में शायद सबसे करीबी और चौंकाने वाले उलटफेरों में से एक के रूप में दर्ज होगी। इस चुनाव में स्टालिन सरकार के 15 प्रमुख मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है।

सोमवार को मतगणना के आखिरी से पहले वाले राउंड तक पेरियाकरुप्पन 30 वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन आखिरी राउंड में पासा पूरी तरह पलट गया और चुनाव अधिकारियों ने उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी सेतुपति को विजेता घोषित कर दिया।

सेतुपति को 83,365 वोट मिले और पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट मिले। भाजपा के केसी तिरुमारन 29,054 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। पेरियाकरुप्पन समेत 10 से अधिक उम्मीदवार 1000 से भी कम मतों से हारे हैं, जिससे दशकों से पार्टी के गढ़ माने जाने वाले इलाके बदल गए।

दूसरा सबसे करीबी मुकाबला वेप्पनहल्ली विधानसभा सीट पर हुआ, जहां द्रमुक के पीएस श्रीनिवासन ने अन्नाद्रमुक के केपी मुनसामी को 138 वोटों से हराया। पोलुर विधानसभा सीट पर टीवीके के आर. अभिषेक ने डीएमडीके प्रत्याशी पी. सरवनन को 227 वोटों से हराया। कल्लाकुरिची सीट पर टीवीके प्रत्याशी अरुल विग्नेश ने अन्नाद्रमुक के एस. राजीव गांधी को 798 वोटों से हराया।

कुंभकोणम सीट पर टीवीके प्रत्याशी विनोद ने द्रमुक के जी. अनबलगन को सिर्फ 679 वोटों से हराया। द्रमुक का 1996 से इस सीट पर कब्जा था। कुम्बम में द्रमुक विधायक को टीवीके के पीएलए जगन्नाथ मिश्रा के हाथों 751 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तिरक्कोयिलुर में एक और रोमांचक मुकाबले में अन्नाद्रमुक के महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी अपने टीवीके प्रतिद्वंद्वी विजय आर. बरानी बालाजी से सिर्फ 285 वोटों से ही जीत पाए। परमथी-वेलुर में अन्नाद्रमुक के एस. शेखर ने द्रमुक के केएस मूर्ति को 308 वोटों से हराया।

कुलितलाई में द्रमुक के सूरियानुर ए. चंद्रन ने टीवीके के जी. बालासुब्रमणि को 579 वोटों से हराया।

केआर पेरियाकरुप्पन और सीनिवास सेतुपति

यह जनादेश राजनीति में धनबल की अस्वीकृति का संकेत है : विजय

प्रथम पृष्ठ से आगे

बाद में 'एक्स' पर बयान में विजय ने ऐतिहासिक और बदलाव लाने वाला जनादेश देने के लिए तमिलनाडु के लोगों का शुक्रिया अदा किया। 23 अप्रैल के चुनाव को भारतीय राजनीति को हिला देने वाला चमत्कार बताते हुए विजय ने कहा कि युवा मतदाताओं और विशेषकर युवाओं ने चुनाव परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह जनादेश राजनीति में धनबल की अस्वीकृति का संकेत है, जिसने लंबे समय तक राज्य की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया है।

सरकार बनाने के लिए छोटे दलों से भी ले सकती है समर्थन : टीवीके को बहुमत के लिए 10 विधायकों की जरूरत है। आइएएनएस के अनुसार, सरकार बनाने के लिए टीवीके पीएमके, वामपंथी दलों और वीसीके जैसे छोटे दलों से समर्थन मांग सकती है। कांग्रेस ने पहले ही टीवीके को समर्थन देने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि द्रमुक के गठबंधन सहयोगियों एमडीएमके, वीसीके और डीएमडीके ने टीवीके से दूरी बनाए रखने का संकेत दिया है और वे समर्थन देने के इच्छुक नहीं हैं।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने नई दिल्ली में बताया कि टीवीके प्रमुख ने सरकार बनाने के लिए पार्टी से समर्थन मांगा है। कांग्रेस नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को जनादेश की भावनाओं को ध्यान में रखकर अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में मंगलवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर शीर्ष नेताओं की बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी और तमिलनाडु में पार्टी के प्रभारी गिरीश चोडनकर भी उपस्थित थे। इससे पहले चोडनकर ने संकेत दिया था कि कांग्रेस के कई नेता टीवीके को समर्थन देने को तैयार हैं।

वहीं, द्रमुक नेता टीकेएस एलनगोवन ने दावा किया कि टीवीके सिर्फ कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बना सकती। उसे अन्नाद्रमुक के समर्थन की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भाजपा ने अन्नाद्रमुक को क्या निर्देश दिए हैं।

विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी

प्रथम पृष्ठ से आगे

चुनाव में हार के बाद रणनीति में बदलाव का संकेत देते हुए ममता ने कहा कि अब वह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। कहा कि गठबंधन के नेताओं ने मुझे फोन करके एकजुटता व्यक्त की। सोनिया और राहुल गांधी ने भी मुझसे बात की है। अरविंद केजरीवाल, उद्धवे, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन के भी फोन आए।

ममता ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलनकारी राजनीति में लौटने की घोषणा की। कहा कि जब तक मैं कुर्सी पर थी, मैंने बहुत कुछ सहन किया। अब मैं एक आजाद पंछी हूं, एक आम इंसान हूं। मैं संघर्ष करने वाली हूं। मैं सड़कों पर रहूंगी और सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ूंगी। ममता ने चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए 10 सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति के गठन की भी घोषणा की।

'असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी'

- असम के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में राजग की जीत असम के मूल निवासियों की जीत, विकास कार्य जारी रहेंगे

गुवाहाटी, प्रेट्र: असम में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन की लगातार तीसरी जीत के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को उसी जोश के साथ जारी रखेगी। सरमा ने आश्वासन दिया कि अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "हमारी पहचान के लिए लड़ाई जारी रहेगी।"

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बांग्लादेश मूल के मुसलमानों के खिलाफ उनकी सरकार के कठोर रुख ने विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के पक्ष में जनता का रुझान बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन को दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि राजग की जीत असम के मूल निवासियों की जीत है और राज्य में विकास कार्यों को जारी रखने का आश्वासन दिया। सरमा ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार और पिछले पांच वर्षों में राज्य में हुए अभूतपूर्व विकास हमारी जीत के मुख्य कारणों में से हैं। उन्होंने कहा कि हमने असमिया समुदाय की सुरक्षा का आश्वासन दिया था और इसे पूरा करने के लिए कदम उठाए। असम ने सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की है। बांग्लादेश मूल के मुसलमानों के खिलाफ हमारे कठोर रुख का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने राज्य में भाजपा की शानदार जीत के लिए असम की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया।

हिमंत बिस्व सरमा। फाइल

डाक मतों की गिनती में पलटा मामला, भाजपा प्रत्याशी पर केस से हाई कोर्ट नाराज

- डाक मतों से छेड़छाड़ केस रद, हाई कोर्ट की पुलिस को फटकार
- श्रृंगेरी सीट पर मतगणना विवाद में भाजपा प्रत्याशी जीवराज को राहत

बेंगलुरु, आइएएनएस: कर्नाटक हाई कोर्ट ने श्रृंगेरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डीएन जीवराज के खिलाफ डाक मतों से कथित छेड़छाड़ के मामले को रद करते हुए पुलिस और संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि 2023 की घटना को लेकर 2026 में केस दर्ज करना न्यायसंगत नहीं है और यह कार्रवाई राजनीतिक प्रभाव में की गई प्रतीत होती है।

दरअसल, 2023 के विधानसभा चुनाव में श्रृंगेरी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेगौड़ा को 201 वोटों से विजयी घोषित किया गया था। इसके बाद जीवराज ने डाक मतों की दोबारा गिनती के लिए हाई कोर्ट में अपील की। अदालत के आदेश पर छह अप्रैल को हुई पुनर्गणना में नतीजे बदल गए और जीवराज को 52 मतों से विजयी घोषित किया गया।

चुनाव के दौरान कुल 1822 मतों में से 279 मत खारिज किए गए थे। बाद में हाई कोर्ट ने इन डाक मतों के पुनः सत्यापन का भी आदेश दिया। इस प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने मतपेटिकाओं और डाक मतों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए और दावा किया कि स्ट्रांग रूम में रखी मतपेटिकाओं की सील और ताले से छेड़छाड़ की गई। नाटकीय घटनाक्रम में पुनर्गणना के दौरान राजेगौड़ा को मिले 255 डाक मत अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव अधिकारी गौरव शेट्टी के अनुसार, जीवराज के वैध डाक मत 692 से घटकर 690 रह गए, जबकि राजेगौड़ा के मत 569 से घटकर 314 हो गए। इसके बाद अंतिम परिणाम में राजेगौड़ा 52 वोटों से हार गए।

इसी बीच, भाजपा प्रत्याशी जीवराज के खिलाफ चिकमंगलुरु थाने में डाक मतों से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अंतरिम राहत की गुहार लगाई। जस्टिस वी. श्रीशनंदा की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने केस रद करते हुए पुलिस को कड़ी चेतावनी दी कि वह राजनीतिक दबाव में काम न करे। अदालत ने यह भी पूछा कि यदि मतपेटिकाओं से छेड़छाड़ हुई थी तो यह बात पहले अदालत के संज्ञान में क्यों नहीं लाई गई। साथ ही, पीठ ने सवाल उठाया कि 2023 में पद पर रहे डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ केस क्यों दर्ज किया गया, जबकि मौजूदा चुनाव अधिकारी को इसमें शामिल नहीं किया गया।

कर्नाटक हाई कोर्ट

वोट चोरी नहीं, 'वोट डकैती' : सिद्दरमैया

मुख्यमंत्री डीके सिद्दरमैया ने प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डाक मतों में हेराफेरी कर जीवराज को जिताया गया। उन्होंने कहा कि इसे 'वोट चोरी' नहीं, बल्कि 'वोट डकैती' कहा जाना चाहिए। सिद्दरमैया ने आरोप लगाया कि पूरी गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई और रिटर्निंग आफिसर को परिणाम घोषित करने के बजाय मामला कोर्ट पर छोड़ना चाहिए था। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि इस तरह का मामला देश में कहीं और नहीं देखने को मिला है। हम इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इस मामले को देश की सबसे बड़ी चुनावी साजिश करार दिया।

असम विस चुनाव

भाजपा के वोट शेयर में 4.6 फीसद की वृद्धि से 22 सीटों का लाभ

पार्टी ने इस बार 82 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, 2021 में उसे 60 सीटें मिली थीं

- भाजपा व उसके सहयोगियों वाले राजग का 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर कब्जा
- भाजपा को 37.81 प्रतिशत वोट मिले, जो 2021 के 33.21 प्रतिशत से काफी अधिक

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम विधानसभा चुनाव के परिणामों ने राज्य की राजनीतिक दिशा को एक नया मोड़ दिया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा के वोट शेयर में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका सीधा लाभ उसे सीटों की संख्या में मिला। भाजपा ने इस बार 82 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है, जबकि 2021 में उसे 60 सीटें मिली थीं।

भाजपा और उसके सहयोगियों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने 126 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटों पर कब्जा किया है। यह गठबंधन का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। भाजपा को अकेले 37.81 प्रतिशत वोट मिले, जो 2021 के 33.21 प्रतिशत से काफी अधिक है। सहयोगी दलों में असम गण परिषद के वोट शेयर में गिरावट के बावजूद उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। वहीं, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटें जीतीं।

प्रतीकात्मक

126 में से केवल सात सीटों पर ही महिलाओं का कब्जा

असम में इस बार भी केवल सात महिलाएं जीत दर्ज कर पाई हैं, जो 2021 के आंकड़ों के बराबर है। कुल 59 महिला उम्मीदवारों में से चुनी गई इन विधायकों में राजग का दबदबा है। राजग)की छह महिलाएं सदन पहुंचेंगी, जिनमें भाजपा की चार और असम गण परिषद एवं बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की एक-एक विधायक शामिल हैं। सबसे प्रमुख जीत वित्त मंत्री अजंता नियोग की रही, जिन्होंने गोलाघाट से लगातार छठी बार जीत हासिल की। दूसरी ओर, कांग्रेस ने सर्वाधिक 14 महिलाएं मैदान में उतारी थीं, लेकिन केवल बेबी बेगम (धुबरी सीट से) ही जीत सकीं। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 50 प्रतिशत होने के बावजूद, महिला विधायकों की संख्या में 2011 (14 विधायक) के बाद से गिरावट देखी गई है।

कांग्रेस का वोट शेयर तो बढ़ा, मगर घट गई सीटें

विपक्ष के लिए ये चुनाव काफी निराशाजनक रहे। कांग्रेस का वोट शेयर पिछले चुनाव के 29.67 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 29.84 प्रतिशत तो हुआ, लेकिन उसकी सीटें 29 से घटकर महज 19 रह गईं। सबसे ज्यादा नुकसान बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआइयूडीएफ को हुआ है। एआइयूडीएफ का वोट शेयर 9.29 प्रतिशत से गिरकर 5.46 प्रतिशत रह गया और उसकी सीटें 16 से घटकर केवल दो पर सिमट गईं। अन्य दलों में, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को एक और रायजोर दल को दो सीटें मिली हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए 1.16 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं। इस बार 1.23 प्रतिशत मतदाताओं ने 'नोटा' का विकल्प चुना, जो पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा अधिक है। इन परिणामों ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में भाजपा की पकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई है।

42 साल पुराने डकैती और लूट के मामले में फरार डकैती और लूट के एक आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। मामला बिहार के शिवहर जिले का है।

चंडीगढ़ में विमान के भीतर यात्री के पावर बैंक में विस्फोट, कई यात्री घायल

हादसे के बाद धुएं से मचा हड़कंप, इमरजेंसी गेट खोलकर यात्रियों को स्लाइडर से निकाला गया

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब इंडिगो की हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची फ्लाइट 6ई-108 के केबिन में अचानक धुआं भर गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विमान में एक यात्री के पावर बैंक में आग लगने के कारण यह घटना हुई, जिससे कुछ ही देर में केबिन धुएं से भर गया और यात्रियों में दहशत फैल गई।

स्थिति को गंभीर देखकर विमान में इमरजेंसी घोषित की गई। फ्लाइट को बे नंबर-1 पर खड़ा किया गया और करीब 4:25 बजे इमरजेंसी गेट खोलकर यात्रियों को स्लाइडर के जरिए बाहर निकाला गया।

इस दौरान यात्रियों में जल्दी बाहर निकलने की होड़ मच गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई। इमरजेंसी स्लाइड से उतरते समय कुछ यात्रियों को चोटें आईं। जानकारी के अनुसार, पांच से छह यात्रियों के घायल होने की बात सामने आई, जिनमें कुछ बुजुर्ग यात्री भी शामिल थे। शुरुआती तौर पर पावर बैंक में विस्फोट को घटना की वजह माना जा रहा है।

फ्लाइट मंगलवार करीब 3:50 बजे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरी थी। विमान में 198 यात्री, दो छोटे बच्चे और छह क्रू सदस्य सवार थे। टैक्सीवे पर विमान के आगे बढ़ने के दौरान सीट नंबर 39सी पर बैठे यात्री ने क्रू को अपने पावर बैंक से धुआं और आग निकलने की सूचना दी। इसके बाद विमान में मौजूद एयर होस्टेस और क्रू मेंबर्स ने तुरंत स्थिति संभाली और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया। हालांकि, तब तक धुआं पूरे केबिन में फैल चुका था। एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही एयरफोर्स की फायर टेंडर गाड़ियां तुरंत विमान के पास पहुंचीं और एहतियातन विमान को चारों ओर से सुरक्षित घेर लिया गया। फिलहाल एयरपोर्ट अथारिटी और इंडिगो प्रबंधन इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जबकि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

इमरजेंसी स्लाइड से उतारा गया लोगों को नीचे। जागरण

धुआं भरने से फैली घबराहट, महिला यात्री के पैर में फ्रैक्चर

हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विमान के अंदर धुआं भरने से यात्रियों में घबराहट फैल गई। कई यात्री सीट छोड़कर तेजी से बाहर निकलने लगे। हालांकि, क्रू की सूझबूझ और समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। फ्लाइट में सफर कर रहे सौरभ ने बताया कि वह पत्नी, बेटे और बेटी के साथ गोवा घूमने गए थे। हैदराबाद से उन्होंने चंडीगढ़ की फ्लाइट ली थी। लैंड होने के बाद फ्लाइट में धुआं फैल गया। लोग चीखने लगे। इमरजेंसी स्लाइडर खोल दिए गए। नीचे उतरते समय उनकी पत्नी का ऋचा पैर मुड़ गया। बाद में एयरपोर्ट अथारिटी और इंडिगो स्टाफ उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। वहीं, कुछ अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आईं, जिन्हें एयरपोर्ट पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया।

पद्मश्री फुलबासन के अपहरण की कोशिश विफल, सीट बेल्ट के एक चालान ने बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, राजनांदगांव

- मुख्य आरोपित खुशबू साहू और उसके तीन साथी गिरफ्तार

पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध समाजसेवी फुलबासन यादव के मंगलवार को अपहरण की कोशिश की गई। हालांकि, पुलिस की सतर्कता ने इस बड़ी साजिश को विफल कर दिया। यातायात पुलिस द्वारा सीट बेल्ट न पहनने पर काटे गए एक मामूली चालान ने आरोपितों के चंगुल में फंसी फुलबासन यादव को बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित खुशबू साहू सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के अनुसार मंगलवार सुबह 10:30 बजे खुशबू साहू अपने तीन साथियों के साथ छत्तीसगढ़ के ग्राम सुकुलदैहान स्थित फुलबासन यादव के घर पहुंची। उसने उन्हें दिव्यांग महिला के साथ फोटो खिंचवाने का झांसा देकर अपने स्कार्पियो वाहन में बिठाया और फुलबासन के हाथ-पैर बांध दिए। जब फुलबासन ने विरोध किया तो उन्हें धमकाया और उनका मुंह बंद कर गाड़ी से आगे बढ़ गए।

जब आरोपित खैरागढ़ के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी चिखली पुलिस चौकी के पास यातायात निरीक्षक नवरतन कश्यप अपने जवानों के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे।

उन्होंने स्कार्पियो चालक को रुकवाया और सीट बेल्ट न पहनने पर चालान बनाया। चालक ने पैसे देने के लिए जब स्कार्पियो का पिछला दरवाजा खोला, तब फुलबासन ने खुशबू के पैर में पैर मारा और मदद के लिए चिल्लाईं।

पुलिस को भ्रमित करने के लिए खुशबू ने उन्हें मिर्गी का मरीज बताया, लेकिन पुलिस को संदेह हो गया। उन्हें नीचे उतारने पर पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया।

महापौर मधुसूदन यादव जब घटना के बाद फुलबासन से मिलने पहुंचे तो वह लिपटकर रोने लगीं। सोर्स इंटरनेट मीडिया

अपनी पहचान बनाने के लिए अपहरण की साजिश : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपितों से लगातार पूछताछ जारी है। पता चला है कि खुशबू साहू, स्व-सहायता समूह की महिलाओं के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए फुलबासन के माध्यम से स्वयं की ब्रांडिंग करना चाहती थी। हालांकि, पुलिस मामले में अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

मुट्ठी भर अनाज से पद्मश्री तक का सफर

फुलबासन का 10 साल की उम्र में उनका बाल विवाह कर दिया गया। ससुराल में भी संघर्ष कम नहीं था, घर चलाने के लिए उन्होंने मजदूरी की और मवेशी चराए। लेकिन इन अभावों ने उनके भीतर समाज को बदलने की एक चिंगारी पैदा कर दी। वर्ष 2001 में छोटे-छोटे स्व-सहायता समूह बनाकर महिलाओं को अल्प बचत से जोड़ा। हर घर से रोज एक मुट्ठी चावल और हफ्ते में दो रुपये बचाकर उन्होंने कोष जमा करना शुरू किया। वर्तमान में इनके पास लगभग दो लाख महिलाओं का समूह है, जो नारी समाजसेवा और सशक्तीकरण के साथ जल-पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती आदि कार्यों में जुटा हुआ है।

धमकी मिलने के बाद त्रिपुरा में भाजपा पार्षद ने की आत्महत्या

अगरतला, प्रेट्र: उत्तरी त्रिपुरा के धर्मनगर नगर परिषद के एक भाजपा पार्षद ने मंगलवार को आत्महत्या कर ली। आरोप है कि धर्मनगर उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद कुछ युवकों ने उन्हें धमकाया और अपमानित किया था। पार्षद राहुल किशोर राय भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी थे। उन्होंने धर्मनगर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार जहर चक्रबोर्ती की भारी जीत के एक दिन बाद यह कदम उठाया। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने युवा नेता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतक की पत्नी अनन्या भट्टाचार्य द्वारा लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। राहुल राय की पत्नी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति की मौत के लिए सात लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि घोषित होने के तुरंत बाद, दोपहर तीन बजे छह से सात युवकों ने चंद्रपुर स्थित हमारे घर पर हमला किया और मेरे पति को गालियां देना शुरू कर दिया।

आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले मान और राघव चड्ढा

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

- भाजपा में शामिल आप के सात सांसदों की सदस्यता रद करने की मांग
- राघव चड्ढा ने आप पर बदले की राजनीति का लगाया आरोप

पंजाब में दल-बदल की लड़ाई को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सात राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता तुरंत रद करने की मांग की। पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मान पंजाब के विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में हस्ताक्षरित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि पंजाब में केवल दो विधायक होने के बावजूद भाजपा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या में नाटकीय वृद्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था के उल्लंघन को दर्शाती है। वहीं, आप छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा, रजिंदर गुप्ता, अशोक मित्तल व संदीप पाठक ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने राज्य सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बदले की राजनीति कर रही है।

राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात के बाद बाहर आकर अन्य विधायकों के साथ प्रेस को संबोधित करते भगवंत मान। जागरण

राघव चड्ढा ने कहा कि आप के पास एक राज्य की पुलिस है, लेकिन भाजपा के पास 21 राज्यों की है।

भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सात सांसदों को 'इलेक्टेड नहीं, बल्कि सेलेक्टेड' बताते हुए कहा कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो केस दर्ज होगा ही। भाजपा में जाने से वह बच नहीं सकता। भाजपा की ढाल उन्हें दूसरे राज्यों में कानून के जाल से तो बचा सकती है, लेकिन पंजाब में नहीं।

राघव बोले, आप छोड़ते ही नेताओं को करार दिया जाता है भ्रष्टाचारी: राघव चड्ढा ने कहा कि जब तक नेता आप में रहते हैं, उन्हें संस्कारी बताया जाता है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही भ्रष्टाचारी करार दे दिया जाता है। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को देशद्रोही तक कहा गया। उद्योगपति रजिंदर गुप्ता की फैक्ट्री पर कार्रवाई कर दबाव बनाने की कोशिश की गई। संदीप पाठक के खिलाफ फर्जी एफआइआर दर्ज की गई है और एजेंसियों के जरिये डर का माहौल तैयार किया जा रहा है।

विक्रमशिला सेतु पर अस्थायी निर्माण से परिचालन शुरू करने की कवायद

जासं, भागलपुर : बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर तत्कालिक परिचालन की संभावनाएं खंगाली जाने लगी हैं, ताकि छोटी गाड़ियों का आवागमन शुरू कराया जा सके। मंगलवार को बार्डर रोड्स आर्गनाइजेशन (बीआरओ) की टीम भागलपुर पहुंची और अभियंताओं के साथ सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। उसपर किसी अस्थायी निर्माण से कैसे परिचालन शुरू किया जा सकता है, इसकी संभावना तलाशी गई। एनएच (साउथ) विंग बिहार के चीफ इंजीनियर संजय भारती ने बताया कि बीआरओ की टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच की है। अगले दो दिनों के भीतर यह निर्णय लिया जाएगा कि क्षतिग्रस्त हिस्से में अस्थायी व्यवस्था संभव है या नहीं।

वहीं विक्रमशिला सेतु के पिलर संख्या दो और तीन के बीच पोल संख्या 133 के पास रविवार की रात विक्रमशिला सेतु का 34 मीटर स्लैब टूटकर गंगा में समा गया था। इसका असर पोल संख्या 132 और 134 के पास के स्लैब पर भी पड़ा है।

बिहार के मुंगेर में 24 किमी लंबा जाम

- विक्रमशिला सेतु ठप होने का असर दिखा
- मुंगेर से घोरघट तक एनएच-80 पर लगे जाम में रातभर फंसे रहे हजारों वाहन

बिहार के तेलिया तालाब- बरियारपुर मार्ग पर वाहनों की लगी कतार। जागरण

जागरण संवाददाता, मुंगेर

विक्रमशिला सेतु पर परिचालन ठप होने का सीधा असर श्रीकृष्ण सेतु की ओर जाने वाले मुंगेर-घोरघट मार्ग पर दिखने लगा है। हालात ऐसे बने कि मुंगेर से घोरघट तक एनएच 80 पर करीब 24 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सोमवार की रात एक बजे से शुरू हुआ जाम मंगलवार सुबह नौ बजे तक सघन रहा। इस कारण हजारों वाहन फंसे रहे। जाम के बावजूद कहीं भी प्रशासनिक सक्रियता नजर नहीं आई। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखी और ना ही वाहनों को नियंत्रित करने की कोई ठोस व्यवस्था। जाम में छोटी-बड़ी गाड़ियों में फंसे लोगों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ी।

स्थानीय लोगों ने बताया कि कई जगहों पर लोग खुद ही ट्रैफिक संभालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वाहनों की भारी संख्या के आगे सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए। सुबह करीब नौ बजे के बाद किसी तरह धीरे-धीरे वाहनों को आगे बढ़ाया गया, तब जाकर स्थिति कुछ सामान्य हो सकी। विक्रमशिला सेतु पर परिचालन बंद होने के बाद भागलपुर, बांका और झारखंड की तरफ से मुंगेर होकर कोसी-सीमांचल और उत्तर बिहार की ओर जाने वाले, निर्माणाधीन मिर्जाचौकी-मुंगेर फोरलेन से ऋषिकुंड व लखीसराय से आने वाले वाहन एनएच 80 सफियाबाद होते हुए श्रीकृष्ण सेतु पर पहुंचते हैं।

अब हरियाणा में छात्रों में समाचार-पत्र पढ़ने की आदत के विकास के लिए पहल

संदीप श्योराण, जागरण • चरखी दादरी: स्कूलों में समाचार-पत्र पढ़ने की आदत को केवल अध्ययन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्थायी संस्कार के रूप में विकसित करने की दिशा में हरियाणा के शिक्षा विभाग ने पहल की है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों में नियमित समाचार-पत्र पठन से भाषा, तर्कशक्ति और समसामयिक समझ विकसित होती है, जो उन्हें जागरूक नागरिक बनने में सहायक बनाती है। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में यह माडल पहले से लागू है। अब हरियाणा में इसी उद्देश्य से स्कूलों में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से अखबार को पढ़ने, समझने और उस पर विचार करने की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग का मानना है कि तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश में विद्यार्थियों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक घटनाक्रम से जोड़ना आवश्यक है।

पुणे दुष्कर्म मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची की मौत का करण दम घुटना

- 65 वर्षीय आरोपित ने पीड़िता को चुप कराने के लिए मुंह में ठूंस दिया था कपड़ा
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर मिले हैं चोट के निशान

पुणे, प्रेट्र : पुणे में पिछले सप्ताह चार वर्षीय जिस लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दम घुटने से उसकी मौत होने का संकेत दिया है। पुलिस ने बताया कि 65 वर्षीय एक आरोपित ने पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। इससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, मजदूरी करने वाले आरोपित का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ 1998 और 2015 में छेड़छाड़ के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में वह दोनों मामलों में बरी हो गया था। पुणे जिले में भोर तहसील के नरसपुर में एक मई को आरोपित ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया था और उसे मार डाला था। इस घटना से बड़े पैमाने पर आक्रोश फैल गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत दम घुटने से हुई है। प्रथम दृष्टया, आरोपित ने पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे चुप कराया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपित बच्ची को खाने का लालच देकर बहला-फुसलाकर मवेशी बाड़े में ले गया, जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। बाद में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले को लेकर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग भी जाम कर दिया। इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को आश्वासन दिया कि सरकार आरोपित को मौत की सजा दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

पटरी पर नारी शक्ति की मिसाल, 34 साल से दौड़ रही लेडीज स्पेशल

मुंबई, एएनआइ : भारतीय रेल की दुनिया में एक ऐसी पहल, जिसने सफर को सिर्फ दूरी तय करने का जरिया नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास की पहचान बना दिया। मुंबई की लेडीज स्पेशल ट्रेन ने 34 साल पूरे कर लिए हैं। पांच मई 1992 को शुरू हुई यह सेवा आज भी मुंबई की लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और सुविधा का प्रतीक बनी हुई है। 90 के दशक में जब शहर तेजी से बढ़ रहा था और महिलाओं की कार्यक्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही थी, तब भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेनों में सफर उनके लिए बड़ी चुनौती था। इसी जरूरत को समझते हुए लेडीज स्पेशल की शुरुआत हुई। पहले चर्चगेट से बोरीवली और फिर विरार तक इसका विस्तार हुआ।

आज यह सेवा सिर्फ ट्रेन नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित दुनिया है। जहां वे बिना डर, बिना धक्का-मुक्की के सफर कर सकती हैं। यहां सिर्फ सीट नहीं मिलती, बल्कि एक अपनापन भी मिलता है।

बरेली के जिम में डाक्टर से दुष्कर्म, एनर्जी ड्रिंक में नशा देता था संचालक

- बेसुध कर दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर मांगी 50 लाख रुपये की रंगदारी
- दो संप्रदायों का मामला, मुख्य आरोपित अकरम व उसका भाई गिरफ्तार

बरेली पुलिस की गिरफ्त में महिला डाक्टर से दुष्कर्म का आरोपित अकरम बेग साथ में उसका भाई आलम। सौजन्य : पुलिस

जागरण संवाददाता, बरेली

अल्टीमेट फिटनेस क्लब जिम में महिला डाक्टर को एनर्जी ड्रिंक में नशा देकर हैवानियत की गई। जिम संचालक अकरम ने उन्हें बेसुध कर दुष्कर्म किया, वीडियो बना ली। इसके बाद ब्लैकमेल करने लगा कि 50 लाख नहीं देने पर वीडियो इंटरनेट पर बेच दिए जाएंगे। अकरम व षड्यंत्र में शामिल भाई आलम सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपितों से बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद होने पर पुलिस का माथा ठनका। आशंका है कि अकरम जिम में आने वाली अन्य महिला प्रशिक्षुओं के लिए भी इन दवाओं का दुरुपयोग करता होगा। प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा रही है। हिंदू महिला डाक्टर ने दो साल पहले अल्टीमेट फिटनेस क्लब जिम की सदस्यता ली थी। उन्होंने बताया कि जिम संचालक अकरम बेग ट्रेनर भी था, इसलिए परिचय हो गया। वह फिटनेस के लिए प्रतिदिन प्री वर्कआउट ड्रिंक बनाकर देता था। धीरे-धीरे उसने एनर्जी ड्रिंक बताकर उसमें नशीली गोलियां मिलानी शुरू कर दीं।

बीएमसी जन्म प्रमाणपत्र घोटाले की जांच करेगी एसआइटी

राज्य ब्यूरो, जागण • मुंबई : देश की सबसे धनी मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में एक चौंकाने वाला 'महाघोटाला' सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर 87,347 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया के प्रयासों और शिकायतों के बाद मुंबई की महापौर रितु तावड़े ने इन सभी संदिग्ध प्रमाणपत्रों को तत्काल रद करने का आदेश दिया है। पूरे मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय एसआइटी का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लखमी गौतम करेंगे, जिसमें अपराध शाखा और विशेष शाखा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। एसआइटी इस बात की जांच करेगी कि कैसे बीएमसी के भीतर एक समानांतर प्रणाली चलाकर इन प्रमाणपत्रों को अवैध रूप से जारी किया गया।

बिहार सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी रहेंगे मंच पर, एनडीए के सभी घटक दल पुराने चेहरे को देंगे अवसर, कुछ नए को भी मिलेगी जगह

मोदी, नवीन, शाह की मौजदूगी में होगा मंत्रिमंडल विस्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण भले ही सादगी से हुआ, लेकिन गुरुवार को उनके मंत्रिमंडल का विस्तार भव्य समारोह में होगा। समारोह का आयोजन पटना स्थित गांधी मैदान में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सरावगी ने बताया कि बंगाल, असम और पुडुचेरी में पार्टी की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार आ रहे हैं।

समारोह में लोजपा (रा) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सहित बिहार के अन्य केंद्रीय मंत्री और एनडीए के नेता पहुंचेंगे।

विधानसभा सदस्य संख्या के लिहाज से राज्य में मुख्यमंत्री सहित 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है। इस समय मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा जदयू कोटे के दो उप मुख्यमंत्री-विजय कुमार चौधरी एवं बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं। इस तरह 33 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन, गुरुवार के विस्तार के बाद मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 30 तक पहुंच सकती है।

सम्राट चौधरी। फाइल

अब लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा मुख्यमंत्री आवास

पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास (01, अणे मार्ग) अब लोक सेवक आवास के रूप में जाना जाएगा। यह आवास सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। मालूम हो कि हाल ही में राजभवन का नाम लोक भवन किया गया था। उसी तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास के नाम को भी परिवर्तित किया गया है।

भोजशाला के प्राचीन पत्थरों पर अंकित हैं कई मंत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर

- एएसआइ ने हाई कोर्ट की सुनवाई में प्रस्तुत किए सर्वे के तर्क
- कहा- भोजकाल में 10वीं-11वीं सदी के बीच हुआ था निर्माण

धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में प्राचीन पत्थरों पर ॐ नमः शिवाय समेत कई मंत्र अंकित पाए गए। गणेश, ब्रह्मा, नृसिंह, भैरव सहित कई देवी-देवताओं की आकृतियां मिलीं। धार्मिक और स्थापत्य महत्व को दर्शातीं 94 कलाकृतियां भी पाई गईं। ये सिद्ध करते हैं कि भोजशाला प्राचीन मंदिर ही थी। इसके साथ ही कई पत्थरों पर अंकित संस्कृत-प्राकृत अक्षरों को मिटाने के साक्ष्य भी मिले हैं। उन पर अरबी-फारसी शब्द स्याही से लिखे होने से छेड़छाड़ के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

ये तर्क मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में मंगलवार को भोजशाला विवाद की सुनवाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की ओर से रखे गए। एएसआइ की ओर से भोजशाला परिसर के सर्वे का विवरण बताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन ने यह भी कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से किए गए सर्वे से पता चला है कि भोजशाला का निर्माण 10वीं-11वीं सदी के बीच परमार राजा भोज के काल में किया गया था। यहां पाई गईं मिट्टी की ईंटों से बनीं काफी चौड़ी दीवारों की बनावट वैसी ही पाई गई, जैसा उल्लेख राजा भोज की पुस्तकों में मिलता है। मंगलवार को एएसआइ के तर्क पूरे हो गए। बुधवार को मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह कोर्ट में पक्ष रखेंगे।

भोजशाला परिसर। फाइल

एएसआइ के अधिवक्ता सुनील जैन ने प्राचीन साहित्य का उल्लेख करते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि खिलजी शासन के दौरान अब्दुल शाह चंगेज ने फौज के साथ मालवा की राजधानी धार में प्रवेश किया था और ताकत के बल पर कई मंदिरों को नमाज पढ़ने की जगह के रूप में परिवर्तित कर दिया था।

एएसआइ के अनुसार, सर्वे में भोजशाला में संस्कृत और प्राकृत भाषा में 150 से अधिक शब्द और शिलालेख मिले। इनमें प्राचीन लेखन स्पष्ट दिखाई देता है। भोजशाला परिसर में ॐ नमः शिवाय और ॐ सरस्वतैयः नमः जैसे मंत्र पत्थरों पर उकेरे हुए पाए गए। गणेश, ब्रह्मा, नृसिंह, भैरव सहित कई देव आकृतियां मिलीं।

4 पाकिस्तानी कैदियों को भारत सरकार ने रिहा कर वतन वापस भेज दिया। मंगलवार को उन्हें अटारी-वाघा सीमा के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। सभी कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।

न्यूज गैलरी

शराब घोटाले में निलंबित आइएएस को अग्रिम जमानत

बिलासपुर: निलंबित आइएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को झारखंड शराब घोटाला मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस पीपी साहू की बेंच ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की दो साल्वेंट (आर्थिक स्थिति या हैसियत) जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने टुटेजा को जांच में पूर्ण सहयोग करने और किसी भी गवाह को प्रभावित न करने के निर्देश दिए हैं। यदि टुटेजा जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो जांच एजेंसी को उनकी जमानत निरस्त कराने का अधिकार होगा। (नईदुनिया)

टीसीएस मतांतरण में चार कर्मी न्यायिक हिरासत में भेजे गए

नासिक : नासिक स्थित एक अदालत ने मंगलवार को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चार कर्मचारियों को पुरुष सहकर्मी के मतांतरण के मामले में 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। चारों आरोपित रजा रफीक मेमन, तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख और शाह रुख हुसैन शौकत कुरैशी पर टीसीएस की स्थानीय इकाई में कुछ महिला सहकर्मियों के यौन उत्पीड़न का भी आरोप है। विशेष जांच दल (एसआइटी) ने आरोपितों को 23 अप्रैल को हिरासत में लिया था। इससे पहले उन्हें पांच मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया था। मंगलवार को हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस वी. लाड के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की। (प्रेट्र)

बहन की देवरानी को जलाकर मारने वाले भाई को सजा ए मौत

मथुरा : बहन की देवरानी की ज्वलनशील पदार्थ डालकर हत्या करने वाले रिश्ते के भाई को जिला जज की अदालत ने मंगलवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 1.30 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी बहन की देवरानी से प्यार करता था। बातचीत बंद होने से नाराज था। हत्या से पहले उसने दुष्कर्म का प्रयास भी किया। दोषी पलवल (हरियाणा) के उमेश को 2016 में हत्या के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। घटना के समय पर वह जमानत पर था। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि दोषी पूर्व में भी इसी तरह के अपराध में संलिप्त रहा। आचरण में कोई सुधार नहीं आया। अपराधियों में कानून का भय पैदा करने और समाज में ऐसे अमानवीय अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह संदेश देने के लिए फांसी की सजा आवश्यक है। (जासं)

नारायण साईं की सजा को निलंबित करने से इन्कार

अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम के बेटे नारायण साईं द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने 2001 के दुष्कर्म मामले में अपनी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ साईं की अपील हाई कोर्ट में लंबित है। सोमवार को पारित एक आदेश में न्यायमूर्ति इलेश वोरा और आरटी वच्छानी की खंडपीठ ने साईं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हमारे लिए प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है कि आवेदक-दोषी को (अपीलीय न्यायालय से) बरी होने का उचित मौका है। इसलिए, गुण-दोष के आधार पर हमें सजा के निलंबन और जमानत देने के संबंध में राहत प्रदान करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं मिलता है। (प्रेट्र)

डूबे क्रूज को जांच के पहले किया नष्ट, साक्ष्य मिटाने का आरोप

सुरक्षित बचे पर्यटक की आपत्ति के बाद प्रशासन का निर्णय सवालों के घेरे में

क्रूज दुर्घटना मामले में जिला न्यायालय ने एफआइआर दर्ज करने के दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर

बरगी बांध में क्रूज हादसे की जांच पूरी होने के पहले ही उसे नष्ट किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। घटना के 40 घंटे के भीतर ही क्रूज को टुकड़े-टुकड़े कर देने से नया विवाद भी खड़ा हो गया है। इस दुर्घटना में सुरक्षित बचे पर्यटक और पेशे से अधिवक्ता रोशन आनंद का आरोप है कि जांच पूरी होने से पहले दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को नष्ट कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। क्रूज की जांच के लिए दो बिंदु महत्वपूर्ण थे- इंजन लाइन व बाडी लाइन। क्रूज नष्ट किए जाने से इन दोनों बिंदुओं पर होने वाली जांच प्रभावित होगी। कोई ठोस साक्ष्य मिलने पर संदेह है। रोशन आनंद ने इसकी शिकायत जल्द ही प्रशासन व पुलिस से करने की बात कही है। इस बीच, क्रूज दुर्घटना के मामले में जिला न्यायालय ने जिम्मेदार लोगों पर एफआइआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

बरगी बांध से निकाले गए क्रूज को तोड़ते बचाव दल के सदस्य। फाइल

बांध से बाहर निकालने के क्रम में क्रूज क्षतिग्रस्त हुआ। क्रूज में लापता लोगों के फंसे होने की आशंका थी। क्रूज तोड़कर साक्ष्य मिटाने के आरोप निराधार हैं। - राघवेंद्र सिंह, कलेक्टर, जबलपुर

'पायलट द्वारा पर्यटकों को बचाने की कोशिश न करना गंभीर'

हादसे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मंगलवार को एफआइआर दर्ज करने का आदेश जारी कर कहा कि कोर्ट के संज्ञान में ये तथ्य आए हैं कि चालक (पायलट) द्वारा क्रूज लापरवाहीपूर्वक चलाया गया। क्रूज की गतिविधियों से परिचित होने पर भी पायलट पर्यटकों को डूबता छोड़कर सकुशल बच निकला। पायलट द्वारा उन्हें बचाने का कोई प्रयास न किया जाना अपराध है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में क्रूज या नाव संचालित करने वाला कोई भी व्यक्ति अनहोनी होने पर लोगों को डूबता हुआ छोड़ेगा और इसकी पुनरावृत्ति होगी।

पर्यटन विभाग के सचिव इलैया राजा टी. ने बताया कि क्रूज पलटने के बाद रेस्क्यू आपरेशन चलाया गया था। क्रूज का बड़ा हिस्सा टूट गया था। क्रेन से खींचकर बाहर निकाला गया। राहत दल ने उसके संबंध में सभी निर्णय लिए। बाद में नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। बता दें कि यह घटना 30 अप्रैल को शाम के वक्त हुई थी। एक मई को क्रूज को खींचकर तट तक लाया गया।

डोला से पूछताछ कर बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करना चाहती है क्राइम ब्रांच

मुंबई, आइएएनएस : दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम डोला से पूछताछ कर मुंबई क्राइम ब्रांच बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश करना चाहती है। डोला की हिरासत के लिए उसने एक विशेष एनडीपीएस अदालत में आवेदन किया है। डोला फिलहाल आठ मई तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में है, जहां उससे ड्रग्स से जुड़े मामलों में पूछताछ की जा रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच उसे तभी हिरासत में ले पाएगी, जब अदालत मंजूरी देगी।

इस आवेदन के जरिये क्राइम ब्रांच ने अदालत से प्रोडक्शन वारंट जारी करने का अनुरोध किया है, जिससे एनसीबी की रिमांड समाप्त होने के बाद डोला को हिरासत में लिया जा सके। कानूनी प्रोटोकाल के अनुसार, क्राइम ब्रांच को पहले अदालत को यह बताना होता है कि आरोपित की हिरासत क्यों आवश्यक है। यदि अदालत यह मानती है कि अन्य मामलों के संबंध में पूछताछ आवश्यक है तो वह प्रोडक्शन वारंट जारी करती है। इसके बाद संबंधित एजेंसी आरोपित को अपनी हिरासत में ले सकती है। क्राइम ब्रांच डोला को कई मामलों में लगातार हिरासत में लेने की कोशिश करेगी, जिनमें सांगली ड्रग्स मामला, मैसूरु ड्रग्स मामला और तेलंगाना ड्रग्स मामला शामिल है। डोला कई बड़े ड्रग्स तस्करी नेटवर्क में एक अहम व्यक्ति रहा है। जांच में सांगली, मैसूरु और तेलंगाना में सामने आए ड्रग्स निर्माण मामलों में उसकी संलिप्तता का पता चला है।

लैंबार्गिनी हादसा : कारोबारी का बेटा ही चला रहा था कार, चार्जशीट पेश

- कानपुर में आठ फरवरी को आटो और बुलेट को टक्कर मार फुटपाथ पर चढ़ गई थी कार
- सीसीटीवी फुटेज के साथ ही 10 गवाहों को आधार बना दाखिल की पुलिस ने चार्जशीट

ग्वालटोली थाने में हादसे के बाद लाई गई थी तंबाकू कारोबारी की लैंबार्गिनी कार, जिसे रिलीज किया जा चुका है। जागरण आर्काइव

जागरण संवाददाता, कानपुर

लैंबार्गिनी रिवोल्ट कार हादसे में पुलिस ने बंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के खिलाफ 200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें आसपास के चार सीसीटीवी फुटेज व 10 गवाहों के बयान को आधार बनाया है। पुलिस ने माना है कि हादसे के समय शिवम ही लैंबार्गिनी कार चला रहा था। उस वक्त उसके साथ अन्य कोई नहीं था। हालांकि, हादसे में घायल तौसीफ के पैर में फ्रैक्चर नहीं मिलने के कारण पुलिस ने मुकदमे से बीएनएस की धारा 125बी (लापरवाही से दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, जिससे गंभीर चोट पहुंचे) हटा दी है। इससे आरोपित को राहत मिलने की उम्मीद है।

आठ फरवरी को शिवम की कार सड़क किनारे खड़े आटो व बुलेट को टक्कर मारते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई थी। हादसे में तीन लोग घायल हुए थे। इसके बाद लीपापोती के प्रयास शुरू हो गए। स्वजन और बाउंसरों ने बताया कि कार शिवम नहीं, उसका चालक चला रहा था। नौ फरवरी को मुकदमे के बाद शिवम के चालक मोहन ने उसको बचाने को कोर्ट में आत्मसमर्पण के लिए प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि कार वह चला रहा था। उसके इस तर्क को पुलिस ने खारिज कर दिया था। पुलिस की जांच व सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि हो रही है कि घटना के समय लैंबार्गिनी शिवम ही चला रहा था। ऐसे में चालक मोहन झूठा साबित हो रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने उसे बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया।

तीन लाख के बदले एक करोड़ वसूलने वाले सूदखोरों से मिला छुटकारा

राज्य ब्यूरो, जागरण • अहमदाबाद

- एसपी ने पांच घंटे में वापस कराया महिला का 40 तोला सोना
- पुलिस ने स्वयं ताला तोड़कर पीड़ित को सौंपा उसका मकान

गुजरात के सुरेंद्रनगर में तीन लाख रुपये उधार लेकर पूजाबेन परमार और उसके पति अनिल भाई सूदखोरों के चक्कर में ऐसे फंसे कि 18 लाख रुपये और 40 तोला सोना देकर भी ब्याजखोरों के चंगुल से मुक्त नहीं हो सके। ब्याजखोर अभी भी इस परिवार से 18 से 20 लाख रुपये मांग रहे थे।

पीड़ित परिवार जब अपनी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख डेलू के पास पहुंचा तो पांच घंटे में 49 तोला सोने के गहने पूजा के हाथ में सौंप दिए गए। अपने गहने वापस पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तीन साल से परेशान इस महिला ने बताया कि अब वह अपने भाई के विवाह में इन गहनों को पहनकर जा सकेगी। कर्ज के चक्कर में ही थानगढ़ में अपना एक पुश्तैनी मकान खोकर यह परिवार मुंबई में बस गया था। इस मकान पर सूदखोरों ने कब्जा जमा लिया था। पुलिस ने स्वयं मकान का ताला तोड़कर उसे यह घर सौंपा। सुरेंद्रनगर के ही थानगढ़ कस्बे के सनी रमेश भाई कणसागरा ने तीन लोगों से पांच से सात लाख रुपये उधार लिए थे। ब्याज के साथ रुपये लौटा देने के बावजूद सूदखोरों ने उस पर लाखों रुपये का बकाया बताकर मकान छीन लिया।

दिव्यांग दंपती को कर्जमुक्त कर दिलाया मकान

सुरेंद्रनगर के दिव्यांग सुरेश पटेल व पत्नी भावना पटेल ने छह लाख 20 हजार का लोन लिया था। इसके लिए अपना 15 लाख का मकान गिरवी रखा था। ब्याजखोर इस परिवार से इनका मकान हड़पना चाहता था। इस दंपती ने जब पुलिस अधीक्षक प्रेमसुख के समक्ष अपनी व्यथा सुनाई तो पुलिस ने इस परिवार को मकान के दस्तावेज वापस दिलवाए।

एसएससी परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार

जासं,देहरादून: महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में संचालित परीक्षा केंद्र महादेव डिजिटल लैब में नकल प्रकरण के मुख्य सरगना को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। नकल गिरोह के दो सदस्यों को एसटीएफ पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि गिरोह का सरगना शुभम भटनागर निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश तब से फरार चल रहा था। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि 13 फरवरी को एसएससी की ओर से महादेवी कन्या पाठशाला में महादेव डिजिटल लैब में मल्टीटास्किंग (नान टेक्निकल) स्टाफ और हवलदार की आनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान रिमोट एक्सेस संसाधनों का उपयोग कर परीक्षा में नकल कराए जाने के संबंध में 14 फरवरी को मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि परीक्षा लैब के पास बने यूपीएस रूम में भूमिगत चैंबर तैयार करके रिमोट एक्सेस के माध्यम से इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग कर अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा था।

सीबीआइ के डीएसपी व पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज

- डीएसपी पहले ही कंपनियों से पांच करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के मामले का कर रहे हैं सामना

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने अपने ही पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित का एक नया केस दर्ज किया है। डीएसपी के खिलाफ बैंकिंग, सिक्योरिटीज और फ्राड ब्रांच (बीएसएफबी) में पोस्टिंग के दौरान रिश्वतखोरी के एक मामले में पहले से ही जांच चल रही है। बबैंकिंग, सिक्योरिटीज और फ्राड ब्रांच (बीएसएफबी) ही बड़े बैंक धोखाधड़ी केसों की जांच करती है। इसी शाखा ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की है।

सीबीआइ ने डीएसपी बृजमोहन मीणा और उनकी पत्नी सुनीता के खिलाफ 2021-24 के दौरान 98.33 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से 87 प्रतिशत अधिक है। डीएसपी बृजमोहन मीणा ने सितंबर 2021 में डीएसपी के रूप में मुंबई स्थित बीएसएफबी शाखा में पदभार संभाला था और दिसंबर 2024 के आखिर तक वहां तैनात रहे। इसी दौरान आय से

अधिक यह संपत्ति जुटाई गई। उन्होंने बताया कि अधिकारी और उनकी पत्नी ने इस संपत्ति के बारे में जांच एजेंसी को संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रविधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि डीएसपी पहले से ही 2024 के एक मामले में जांच का सामना कर रहे थे, जिसमें उन पर जांच से गुजर रही कंपनियों और व्यक्तियों से कथित तौर पर पांच करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था।

दुष्कर्म के दोषियों को पैरोल न मिले, ऐसा कानून लाएगी महाराष्ट्र सरकार

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई : महाराष्ट्र में ऐसा कानून लाने की तैयारी हो रही है, जिसमें यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के दोषियों को सजा के दौरान पैरोल नहीं मिल सकेगा। ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधि एवं न्याय विभाग को दिया है। मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दो दिन पहले पुणे के नसरापुर गांव में एक चार साल की बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना पर भी चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने सुझाव दिया कि यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों में सजा पाए अपराधियों को पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरोपों में पैरोल या जमानत पर बाहर आए अपराधी फिर से ऐसे ही अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं। इसलिए, इन कानूनों को और कड़ा बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने विधि एवं कानून विभाग को ऐसे कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश भी दिए। उनके पहले कार्यकाल में भी इस प्रकार का कानून बनाया गया था।

हत्या के 42 साल बाद दो अभियुक्त दोषी करार

विधि संवाददाता, जागरण • लखनऊ

- ट्रायल कोर्ट ने आत्मरक्षा का लाभ देकर चारों आरोपितों को किया था बरी
- दो अभियुक्तों की सुनवाई के दौरान मौत, दो को 11 मई को सुनाई जाएगी सजा

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में 42 वर्ष बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। मामले में कुल चार अभियुक्त थे, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने आत्मरक्षा का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। अपील लंबित रहने के दौरान दो अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। अब शेष दो अभियुक्तों को आपराधिक मानव वध के अपराध में दोषी मानते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 मई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया गया है। यह फैसला न्यायमूर्ति रजनीश कुमार और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार करते हुए सुनाया।

घटना 15 जून 1984 की उन्नाव जनपद के माखी थाना क्षेत्र की है। जमुना प्रसाद अपने घर की छत पर पानी निकासी के लिए नाली बना रहे थे। इसी दौरान अभियुक्त तुलसी राम, लक्ष्मी नारायण, जगत पाल और हरनाम ने इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने पर आरोपितों ने जमुना प्रसाद और उनके भाई अमृत लाल पर लाठी और भाले से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल जमुना प्रसाद की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

वर्ष 1986 में विशेष सत्र न्यायाधीश, उन्नाव ने यह कहते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया था कि उन्होंने आत्मरक्षा में हमला किया था। हालांकि हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि पानी निकासी जैसे मामूली विवाद में जान लेना आत्मरक्षा की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताते हुए दोषसिद्धि दर्ज की।

कोलकाता के डीसीपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर (डीसीपी) शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ईडी को आशंका है कि वह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं। यह कार्रवाई अपराधी बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में की गई है। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, बिस्वजीत पोद्दार द्वारा संचालित कथित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत शांतनु को कई बार पूछताछ के लिए तलब किया गया था। हालांकि, वह अब तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।

शांतनु सिन्हा बिस्वास

ईडी को आशंका-देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकते हैं सिन्हा

सूत्रों के मुताबिक, दक्षिण कोलकाता निवासी सोना पप्पू पर जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूली और आर्म्स एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। इन आरोपों के आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग की जांच शुरू की थी। जांच के सिलसिले में ईडी ने हाल ही में फर्न रोड स्थित शांतनु बिस्वास के आवास पर छापेमारी भी की थी। छापे के बाद से वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं।

इसके बाद एजेंसी ने उन्हें और उनके दो बेटों-सायंतन और मनीष-को सीजीओ काम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन तय तारीख पर कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे पहले ईडी ने रेत तस्करी से जुड़े एक अन्य मामले में भी शांतनु को तलब किया था। इस बार भी वह स्वयं उपस्थित नहीं हुए, उनकी ओर से वकील ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में शांतनु से पूछताछ जरूरी है।

आंगन में बांग्ला कुलांचे भरती तो चौखट पार करते ही घुलता है अवधी का भी रस

जागरण विशेष पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आकर लखीमपुर में बसे लोग दोनों संस्कृतियों के बने हुए हैं संवाहक

आनंद त्रिपाठी • जागरण

लखीमपुर: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले के रविंद्रनगर गांव के प्रधान मिथुन दो-चार लोगों के साथ दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं। रास्ते में मिलने वालों से सलाम-दुआ होती है। की खोबोर दादा, केमोन आछेन (क्या हाल हैं दादा, कैसे हैं)। जवाब मिलता है, भालो... खूब भालो। बांग्ला में एक-दो वाक्यों का संक्षिप्त वार्तालाप। आगे दूसरे गांव के लोग भी मिलते हैं, उनसे उसी आत्मीयता में अवधी में बात होती है। राह गुजरते कुछ किशोर दिखते हैं मोबाइल में रमे हुए। पंजाबी गाने चल रहे हैं। भाषाओं का यह सुंदर मिलाप गांव में हर ओर दिखता है। हिंदी से बात होते हुए संवाद बांग्ला का रुख कर लेता है और फिर हिंदी-अवधी पर लौट आता है। रविंद्रनगर में सांस्कृतिक दोआब का यह आयाम हर स्तर पर मिलेगा, चाहे भाषा हो, परिधान हो या फिर खानपान। पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित होकर यहां बसे हिंदू बांग्ला के साथ अवधी संस्कृति को आत्मसात कर मिसाल पेश कर रहे हैं।

यहां के शंभुनाथ मंडल से जब बात होती है तो वह बताते हैं कि जब उनके पिता धीरेंद्र नाथ पलायन कर यहां आए थे तो भाषा को लेकर बहुत समस्या थी। इसलिए बुजुर्गों ने बच्चों को स्थानीय भाषा का ज्ञान देने का निर्णय लिया, पर इसका भी ध्यान रखा गया कि हमारी मूल संस्कृति का ह्रास न हो। उद्देश्य था कि नई पीढ़ी जड़ों से जुड़े रहते हुए लोकाचार को भी समझ सके। इस तरह से हम दो संस्कृतियों के संवाहक बन गए।

किसी ने 50 तो किसी ने सौ रुपये देकर शुरू किया सामुदायिक स्कूल: शंभुनाथ कहते हैं जब उनके पूर्वज यहां आए थे तो शुरुआत में शिक्षा को लेकर भी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दरअसल, विस्थापन से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो गई थी। ऐसे में गांव के लोगों ने एक एक सामुदायिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। मेहनत-मजदूरी कर जोड़े गए रुपयों में से सबने थोड़ी-थोड़ी आर्थिक मदद की। किसी ने 50 तो किसी ने सौ रुपये का योगदान दिया। जिसके पास रुपये नहीं थे, उन्होंने अनाज दिया और इस तरह से एक स्कूल की नींव पड़ी, जिसका नामकरण संजय गांधी के नाम पर किया गया। यहां हिंदी के साथ बांग्ला में भी पढ़ाई होती है।

शंभुनाथ मंडल

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

घर के दलान में बैठकर चर्चा करतीं महिलाएं • जागरण

गांव ने तैयार किए कई अधिकारी

उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक तपन कुमार बिश्वास बताते हैं कि इस गांव से कई अधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर व शिक्षक बने हैं। इनमें से प्रभात राय आइएफएस (इंडियन फारेस्ट सर्विस) में हैं। गौतम घोष पीसीएस अधिकारी हैं। चितरंजन बिश्वास पेशे से डाक्टर हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हेल्थ केयर टीम के हेड भी रह चुके हैं। उज्जवल बोस इंजीनियर हैं। इसके अलावा कई शिक्षक-प्रोफेसर इस गांव से निकलकर समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

तपन कुमार बिश्वास

कक्षा पांच से बांग्ला भाषा की पढ़ाई

संजय गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य शंकर ढाली बताते हैं कि स्कूल कक्षा आठ तक मान्यता प्राप्त है। रविंद्र नगर के अलावा कई अन्य गांवों के बच्चे यहां पढ़ने आते हैं, जिनकी संख्या करीब एक हजार है। वह कहते हैं कि हमारा सोच है कि जैसे हमारे बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, उसी तरह अन्य बच्चों को बांग्ला भाषा का ज्ञान हो, इसलिए कक्षा पांच से बांग्ला पढ़ाई जाती है। नए सत्र से इस विषय को कक्षा तीन से लागू करने की तैयारी है।

शंकर ढाली

नई पीढ़ी धोती-कुर्ता नहीं पहनती, पर अपनी संस्कृति के प्रति है आस्थावान

गांव के ही युवा मिंटू सरकार से दो संस्कृतियों की धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने को लेकर जब बात होती है तो वह बताते हैं कि नई पीढ़ी अब धोती-कुर्ता नहीं पहनती। जींस-टी शर्ट पहनती है, पर अपनी संस्कृति के प्रति पूर्ण आस्थावान है। हर उत्सव वैसे ही मनाए जाते हैं, जैसे बांग्लादेश में मनाते थे और इसमें सबसे बड़े भागीदारी युवाओं की ही होती है। वह वहुत ही गौरवांवित होकर कहते हैं कि जीवन-यापन की आपाधापी में लगे ग्रामीणों को संभवतः इस बात का भान भी नहीं है कि सांस्कृतिक संकरण से गुजरते हुए धीरे-धीरे उन्होंने एक नई संस्कृति का सृजन किया है। यही वजह है कि एक ही गांव में, एक ही घर में बंगाली धोती से लेकर जींस-टीशर्ट जैसे परिधान खूंटी पर टंगे होते हैं। हालांकि, रान्नाघर (रसोई) में अब भी बंगाली शुचिता बरकरार है। शुक्तो से लेकर चरचरी तक कई बंगाली व्यंजन आज भी घर-घर में बनते हैं और बच्चे इन्हें चाव से खाते भी हैं। प्रोसेस्ड फूड कल्चर के बढ़ते अतिरेक के बावजूद उनके मन में बंगाली व्यंजनों को लेकर बहुत लगाव है।

मिंटू सरकार

हरियाणा में खड़े ट्रक से टकराई स्कार्पियो, चार पुलिसकर्मियों समेत पांच की मौत

जागरण संवाददाता, नूंह

हरियाणा में कुंडली मानेसर-पलवल (केएमपी) मार्ग पर खड़े ट्रक से पीछे से तेज गति से आ रही स्कार्पियो कार टकरा गई। हादसे में स्कार्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार उत्तर प्रदेश पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर, दो सिपाही व चालक की मौके पर ही मौत हो गई। चारों पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के उरई थाने में तैनात थे। स्कार्पियो चला रहे अमरीक सिंह पंजाब के संगरूर जिले के जोगिया पट्टी के रहने वाले थे। अमरीक के भाई के अपहरण के मामले में उरई पुलिस की टीम जांच के लिए जींद जिले में जा रही थी। मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे धुलावट टोल प्लाजा के समीप एक चालक अपने ट्रक को केएमपी मार्ग पर खड़ा करके पास ही बने खोके से कुछ सामान लेने के लिए गया था। घटना के बाद चालक अपने ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया।

चालक को झपकी आने से टोल बैरियर तोड़ ट्रक में घुसी बस, 26 घायल

जागरण संवाददाता, बदायूं

गंगा एक्सप्रेसवे पर लापरवाह बस चालक ने 65 यात्रियों की जिंदगी संकट में डाल दी। मंगलवार तड़के चालक को झपकी आने से चंदोई टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए बस ट्रक में जा घुसी। हादसे में 26 यात्री घायल हो गए, इनमें 18 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का निकटवर्ती संभल के जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। हादसे की विस्तृत जांच बैठाई गई, जिसके आधार पर चालक के विरुद्ध कार्रवाई तय होगी। लुधियाना (पंजाब) से यात्रियों को लेकर उन्नाव जा रही डबल डेकर स्लीपर बस सुबह चार बजे टोल प्लाजा के पास पहुंची। बस को अमरोहा निवासी दानिश चला रहा था।

टोलकर्मियों के अनुसार, 50 मीटर दूर से ही दिख गया कि बस अनियंत्रित आ रही है। वे संभल पाते, इससे पहले बस बैरियर तोड़कर टोल पार हो गई। इसके बाद बस 100 मीटर दूर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी।

दैनिक जागरण
अनुशासन उन्नति का आधार है

ममता का हठ

पश्चिम बंगाल में खुद अपना भी चुनाव हारने के साथ ही बुरी पराजय का सामना करने के बाद ममता बनर्जी का यह कहना राजनीतिक हठधर्मी ही है कि वे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं देंगी। ऐसा कहकर वे अपनी अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचय देने के साथ ही अपने उस अराजक राजनीतिक व्यवहार को भी रेखांकित कर रही हैं, जिसके चलते उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। वे इसकी जानबूझकर अनदेखी कर रही हैं कि उनके साथ-साथ पराजय का सामना करने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपनी हार सहजता से स्वीकार कर ली और केरलम के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तो ऐसा करने के साथ ही अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी एक तरह से बालहठ ही नहीं दिखा रही हैं, बल्कि राजनीतिक अपरिपक्वता का भी परिचय दे रही हैं। राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाली ममता बनर्जी इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकतीं कि यदि वे इस्तीफा नहीं देतीं तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं। यदि उनके हठ के कारण इसकी नौबत आई तो इससे उनकी फजीहत ही होगी। रह-रहकर संविधान की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी जिस तरह इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, उसकी मिसाल मिलना कठिन है।

इस्तीफा न देने की जिद करके ममता बनर्जी अपने समर्थकों को यह संदेश देने की नाकाम कोशिश कर रही हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन इस तरह से वे न तो लोगों की सहानुभूति अर्जित कर सकती हैं और न ही अपने खोए हुए जनाधार को वापस पा सकती हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि लोग सब कुछ तो भूल जाते हैं, लेकिन किसी का अहंकार आसानी से नहीं भूलते। यदि ममता बनर्जी अपनी खोए हुए जनाधार को फिर से पाना चाहती हैं तो उन्हें जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। उनका तर्क है कि वे हारी नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है। साफ है कि वे यह समझने-मानने को तैयार नहीं कि उनकी पराजय का कारण उनका कुशासन और उसके चलते जनता की उनसे गहरी नाराजगी रही। यह बताने की जरूरत नहीं कि तृणमूल कांग्रेस कोई 10-15 सीटों के अंतर से बहुमत से दूर नहीं रही। वह 294 सीटों वाली विधानसभा में सौ सीटों तक भी नहीं पहुंच सकी। ममता बनर्जी खुद को हराए जाने का आरोप उछाल कर वही लाइन ले रही हैं, जो राहुल गांधी ने एक लंबे समय से पकड़ रखी है और जिसके तहत चुनाव की चोरी का राग अलापते रहते हैं। गत दिवस उन्होंने यही राग अलापते हुए कहा कि असम और बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव की चोरी की। प्रश्न यह है कि आखिर केरलम के बारे में उनकी क्या राय है, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जीत हासिल की है?

बख्शे न जाएं दोषी

बिहार सरकार जिस प्रकार अपराध के विरुद्ध सख्त हुई है, पुल-पुलियों के रख रखाव के मामले में भी उसी शिद्दत के साथ गंभीर होने की जरूरत है। पिछले वर्ष बड़ी संख्या में विशेषकर पुलियों के ध्वस्त होने से राज्य सरकार की किरकिरी हुई थी। हालांकि ये ऐसी छोटी-छोटी पुलिया थी, जिनका निर्माण ज्यादातर स्थानीय ठेकेदारों द्वारा किया गया था। पूर्व के शासनकाल में बनी पुलियों की खामी का ठीकरा वर्तमान सरकार पर फूटा। हालांकि यह जरूरी था कि पुलियों का रख रखाव वर्तमान सरकार करे। नीतीश सरकार में पुल-पुलियों के रख रखाव के लिए हेल्थ कार्ड की योजना बनाई गई थी। विशेषज्ञों की टीम पुलों की भौतिक स्थिति की जानकारी हेल्थ कार्ड में दर्ज करेगी। इसी आधार पर उनकी मरम्मत की योजना बनाकर काम होना था। इस प्रक्रिया को पूरी तरह सक्रिय कर देने के जरूरत है। भागलपुर में रविवार की रात 25 साल पुराने विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा देखते-देखते गंगा में समा गया। पिछले आठ वर्षों से इसके रख रखाव में शिथिलता बरती जा रही थी। संबद्ध विभाग एक दूसरे को आरोपित कर रहे, लेकिन नुकसान तो आम जनता का हुआ। एनएच के कार्यपालक अभियंता को निलंबित किया गया है। घटना की जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पुल को तीन महीने में सुचारू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यथाशीघ्र इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।

पुल-पुलियों के रख रखाव के लिए हेल्थ कार्ड की योजना को क्रियान्वित करने की जरूरत है

आतंक के विरुद्ध और मजबूत हो मुहिम

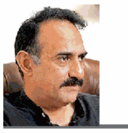

राजा मुनीब

जब तक पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचों को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक वह भारत के लिए खतरा बना रहेगा

पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले को साल भर बीत गया है और इस हमले के जवाब में आपरेशन सिंदूर का भी एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। एनआइए की जांच में यही सामने आया था कि पहलगाम हमले की जड़ें पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी गुटों से जुड़ी थीं और इस हमले में भी वैसे ही तौर-तरीके अपनाए गए, जैसे मुंबई आतंकी हमले और पुलवामा हमले के दौरान आजमाए गए थे। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब छह-सात मई की रात को आपरेशन सिंदूर से दिया था। इसका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था-भारत को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठनों को उनकी करतूतों का सबक सिखाना और यह बताना था कि पाकिस्तान का हर एक आतंकी ढांचा भारत की मारक क्षमता के दायरे में है। आपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया के सामने उजागर करने के लिए कूटनीतिक अभियान के तहत प्रमुख देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इस एक वर्ष के बीच वैश्विक परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। इसके बावजूद, स्पष्ट है कि आतंकवाद की निंदा के मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई खास मतभेद नहीं है।

पहलगाम हमले के बाद जारी बयानों में भी यही झलका था कि नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है, फिर भी यह वैचारिक स्पष्टता उन आतंकी ढांचों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई में तब्दील नहीं हो पाई है, जो ऐसे हमलों को बढ़ावा देते हैं। खासतौर से तब यह और अखरता है, जब ऐसे ढांचों का पूरा तंत्र पाकिस्तान में स्पष्टता से दिखाई देता हो और वे कार्रवाई से बचे रह जाएं। पहलगाम आतंकी हमले के सिलसिले में जिन नेटवर्कों की पहचान की गई, वे उसी ढांचे का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तानी इलाकों में एक सुसंगठित सहायता तंत्र के दायरे में संचालित होते हैं। इसमें प्रशिक्षण सुविधाएं, वित्तीय सहायता, भर्ती के रास्ते और वैचारिक समर्थन जैसे पहलू शामिल हैं। पिछले कई वर्षों में विभिन्न जांचों में इन तत्वों को बार-बार प्रमाणित किया गया है। इसके बावजूद अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में पाकिस्तान पर इस बात के लिए निरंतर दबाव बनाने को लेकर व्यापक रूप से परहेज ही किया गया है कि वह इन नेटवर्कों को चिह्नित कर उन्हें ध्वस्त करे। ऐसे ढांचों को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई के मोर्चे पर अंतर की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है और उसमें एक चिरपरिचित रुझान भी नजर आता है। प्रत्येक बड़े आतंकी हमले के बाद कड़ी कूटनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। उसके बाद साक्ष्य साझा करने के साथ एकजुटता प्रदर्शित की जाती है। हालांकि, ऐसी प्रतिक्रियाएं किसी स्थायी समाधान का निमित्त नहीं बन पातीं, जिनसे भावी आतंकी हमलों पर अंकुश लग सके। इसका यही परिणाम होता है कि किसी हमले को अंजाम देने के बाद वही आतंकी ढांचे नई पहचान के साथ नए सिरे से फिर सक्रिय हो जाते हैं।

आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में ध्वस्त किया गया आतंकी ठिकाना। फाइल

शक्तिशाली देशों के आचरण में आतंकवाद को लेकर विसंगति उनके व्यवहार में भी झलकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम हमले की कड़े शब्दों में निंदा की थी, पर अब उनका नजरिया बदला हुआ एवं अस्थिर है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सहित वहां के नेतृत्व के साथ उनकी हालिया करीबी उसी वैचारिक बदलाव को दर्शाती है, जहां आतंक से निपटने की जवाबदेही तय करने के बजाय निजी हितों को प्राथमिकता दी जाती है। आतंकी नेटवर्कों के साथ पाकिस्तान के पुख्ता संबंधों के बावजूद उसे कूटनीतिक समर्थन देकर अमेरिका अब उन्हीं प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगा है, जिसकी वह खुद निंदा करता आया है। यह रवैया भी किसी एक देश तक ही सीमित नहीं है। तमाम अंतरराष्ट्रीय किरदार ऐसा ही दोहरा रवैया दिखाते हैं। एक ओर तो वे आतंक को वैश्विक खतरे के रूप में मान्यता देते हुए पीड़ितों का समर्थन करते हैं तो दूसरी ओर भू-राजनीतिक पहलुओं को देखते हुए पाकिस्तान पर किसी भी सीधी कार्रवाई से न केवल संकोच करते हैं, बल्कि उस पर दबाव बनाना भी उचित नहीं समझते।

आधिकारिक रुख के साथ-साथ मानवाधिकार संगठनों और नीतिगत विश्लेषकों के बीच भी एक समानांतर विमर्श जारी है। हालांकि यह मुख्यतः शासन और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे विषयों पर केंद्रित होता है, लेकिन यह अक्सर राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के मुख्य मुद्दे से ध्यान भटका देता है। यह स्थिति विमर्श को न केवल जटिल बनाती है, बल्कि जवाबदेही की मूल समस्या के समाधान में कोई योगदान भी नहीं देती। इस तरह देखा जाए तो पहलगाम हमला आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया में व्याप्त एक ढांचागत समस्या को दर्शाता है। हिंसक आतंकी घटनाओं को चिह्नित करने और उनके प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के स्तर पर तो स्पष्टता दिखाई देती है, लेकिन जब उस हिंसा के स्रोत के रूप में पाकिस्तान जैसे देश सामने आते हैं, तब अंतरराष्ट्रीय समुदाय में एक हिचकिचाहट पैदा हो जाती है। यह हिचकिचाहट पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्कों को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और अपना संचालन जारी रखने का अवसर एवं गुंजाइश प्रदान करती है।

भारत का लंबे अर्से से यही रुख रहा है कि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई केवल तात्कालिक प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए वित्तीय स्रोतों पर अंकुश, परिचालन संबंधी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने और वैचारिक समर्थन तंत्र को चुनौती देने वाले समग्र एवं निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। आपरेशन सिंदूर की संकल्पना यही थी कि इसमें केवल हमलावरों को उनकी करनी का सबक ही नहीं सिखाना, बल्कि उनकी जड़ों पर प्रहार करना था। अब जब पहलगाम हमले को साल भर बीत गया है, तब आतंक के विरुद्ध वैश्विक सैद्धांतिक रुख भले ही यथावत कायम हो, लेकिन व्यावहारिकता की कसौटी पर वह खरा नहीं उतर पाता, क्योंकि तमाम साक्ष्यों के बावजूद पाकिस्तानी आतंकी ढांचा जस का तस कायम है। जब तक ऐसे ढांचों को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक पहलगाम जैसे आतंकी हमलों का खतरा बना रहेगा। समाधान केवल समस्या को पहचानने में नहीं, बल्कि उसका निदान करने से ही संभव है।

(लेखक सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल

राजीव सचान

अब यह फ्राड नहीं चलेगा कि मुस्लिम गोलबंदी तो सेक्युलर राजनीति हैं, मगर हिंदुओं को गोलबंद करना सांप्रदायिक

पांच राज्यों के चुनावों में से राहुल गांधी को असम और बंगाल के चुनाव नतीजे स्वीकार नहीं हैं। उनके शब्दों में, 'असम और पश्चिम बंगाल ऐसे स्पष्ट उदाहरण हैं, जहां भाजपा ने चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चुराया है। हम ममता बनर्जी से सहमत हैं कि बंगाल में सौ से ज्यादा सीटें चुराई गईं। हमने पहले भी मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और 2024 के लोकसभा चुनाव में यह तरीका देखा है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी-अब और चारा ही क्या है।' आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। केरलम के बारे में तो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि यहां कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे ने जीत हासिल की है। चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने तमिलनाडु में शानदार जीत हासिल करने वाले टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय को बधाई दी तो पराजय का सामना करने वाले स्टालिन से भी बात की। ज्ञात हो स्टालिन ने चुनाव नतीजों को सहजता से स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से भी बात की और अपनी एक्स पोस्ट में कांग्रेस के उन लोगों को संभलने की सलाह दी, जो टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे। यह वही राहुल गांधी हैं, जिन्होंने बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के ठीक पहले ममता को निशाने पर लेते हुए कहा था कि बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर टीएमसी में कोई न कोई रिश्तेदारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं मिलने वाला। ममता पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों और अपनी पार्टी के लोगों के लिए करती हैं और जनता की कोई भी मदद नहीं करतीं। उन्होंने यह भी कहा था, बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, टीएमसी का गुंडाराज चल रहा है।

आखिर राहुल अपनी ही बातों को इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं? राहुल ने बंगाल में प्रचार के दौरान ही ममता को लेकर यह भी कहा था कि बंगाल में बढ़ते ध्रुवीकरण की वजह से ही भाजपा को मौका मिला। इससे इन्कार नहीं कि बंगाल में भाजपा की जीत के कई कारणों में से एक मतदाताओं का ध्रुवीकरण भी रहा। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के पर्याप्त कारण हैं कि भाजपा के पक्ष में बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता गोलबंद हुए और इसलिए भी उसे बंपर जीत मिली, पर ऐसा केवल इसलिए नहीं हुआ कि भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल सरीखे दल कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोटों को गोलबंद करने का काम करते हैं। वास्तव में यह काम खुद को सेक्युलर बताने वाले अधिकतर दल करते हैं। कांग्रेस देश भर में यही करती है और बंगाल में ममता भी यही कर रही थीं और इतना खुलकर कर रही थीं कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण में बदल गया।

भारी पड़ी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। फाइल

आम तौर पर मुस्लिम किसी दल के पक्ष में थोक वोट करते हैं और जबसे भाजपा का उभार हुआ है, तबसे वे खास तौर पर उस दल के पक्ष में वोट करते हैं, जो उसे हरा सकने में सक्षम दिखता है। इसके चलते कथित सेक्युलर दल उनकी गोलबंदी में अतिरिक्त परिश्रम करने लगे। वे उनके सामने भाजपा का हौवा खड़ा करते और उनका काम आसान हो जाता। मुस्लिम वोटों की इस गोलबंदी को ध्रुवीकरण के बजाय सेक्युलर राजनीति की संज्ञा दी जाने लगी। इस फर्जी सेक्युलर राजनीति के चलते एक समय ऐसा आया कि भाजपा विरोधी दलों के लिए मुस्लिम वोट एक तरह के वीटो पावर बन गए। जब भाजपा ने मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के जवाब में हिंदू वोटों को गोलबंदी करनी शुरू की तो उसके विरोधियों ने उस पर ध्रुवीकरण की सांप्रदायिक राजनीति करने ठप्पा लगाना शुरू किया। भाजपा ने इसकी परवाह न करते हुए सेक्युलरिज्म को छद्म सेक्युलरिज्म की संज्ञा दी और वह उस पर इसलिए बुरी तरह चिपक गया, क्योंकि यही सच था।

निःसंदेह बंगाल में मुस्लिम वोटों के बंटवारे के कारण भी टीएमसी को नुकसान हुआ, लेकिन यदि ममता मुस्लिम समुदाय का इतना खुला तुष्टीकरण नहीं करतीं तो हिंदू भाजपा के पक्ष में खुलकर गोलबंद नहीं होते। ममता केवल इसलिए नहीं हारीं, क्योंकि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया और अधिसंख्य हिंदू वोट भाजपा के खाते में चले गए। वे इसलिए भी हारीं, क्योंकि उनका शासन पक्षपात और उनके नेताओं के भ्रष्टाचार संग उनकी गुंडागर्दी का पर्याय बन गया था। महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी राज्य में महिला असुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना। ममता को घुसपैठियों की अनदेखी और मुस्लिमपरस्ती की भी कीमत चुकानी पड़ी। यही कीमत असम में कांग्रेस ने चुकाई। इस पर गौर करें कि असम में एक समय कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ने वाले बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को आज की मुस्लिम लीग बता दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब यह फ्राड बंद होना चाहिए कि मुसलमानों की गोलबंदी तो सेक्युलर राजनीति है और उसके जवाब में हिंदुओं को एकजुट करना सांप्रदायिक राजनीति। मुस्लिम वोटों ने असम और बंगाल में भी अपना वीटो पवार खो दिया और यह मिथ्या धारणा ध्वस्त हो गई कि उनके वोट किसी दल की चुनावी नैया पार लगा सकते हैं, क्योंकि उनका ध्रुवीकरण रिवर्स ध्रुवीकरण करता है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

त्रिविध ताप

संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है, जो दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। दुखों की भी प्रकृति होती है। दुख शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो सकता है। दुखों से मुक्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है, अपितु दुखों को पढ़ना, समझना, उनका विवेचन करना, उन्हें आत्मसात करना तथा उनके द्वारा अपने को तपाना जीवन का उद्देश्य है। अध्यात्म में दुखों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे 'त्रिविध ताप' की संज्ञा दी गई है। इन तीन तापों को आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक कहा गया है।

आध्यात्मिक ताप वह कष्ट है जो स्वयं के भीतर से उत्पन्न होता है। इसमें मानसिक अशांति, भ्रम, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि सम्मिलित हैं। मनुष्य का मन जब अस्थिर होता है, तब वह स्वयं अपने लिए दुख का कारण बन जाता है। यह ताप सबसे सूक्ष्म और गहरा है, क्योंकि इसका स्रोत बाहरी नहीं, अपितु आंतरिक होता है। आत्म-अज्ञान ही इसका मूल कारण माना गया है। आधिभौतिक ताप बाहरी भौतिक जगत से उत्पन्न होता है। इसमें अन्य प्राणियों, मनुष्यों, पशु-पक्षियों अथवा वस्तुओं से मिलने वाले कष्ट सम्मिलित हैं। जैसे दुर्घटनाएं, हिंसा, शत्रुता, या सामाजिक संघर्ष। यह ताप मनुष्य के पारस्परिक संबंधों और भौतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। आधिदैविक ताप उन कष्टों को संदर्भित करता है जो दैवीय या प्राकृतिक शक्तियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी आदि। ये वे स्थितियां हैं, जिन पर मनुष्य का सीधा नियंत्रण नहीं होता और जिनका अनुभव उसे प्रकृति या दैविक व्यवस्था के अधीन होकर करना पड़ता है। त्रिविध ताप में केवल कष्टों का वर्गीकरण नहीं, बल्कि जीवन को समझने का सहज मार्ग भी निहित है। भारतीय चिंतन के अनुसार ज्ञान, साधना और आत्मबोध के माध्यम से इन तापों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

ट्विंकल तोमर सिंह

'वैश्विक जल दिवालियापन' का खतरा

सुधीर कुमार

'जल दिवालियापन' एक ऐसी स्थिति हैं, जहां पानी का उपभोग जल धारण क्षमताओं से कहीं अधिक हो रहा हैं

संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया 'जल दिवालियापन' के कगार पर पहुंच चुकी है। यह एक ऐसी स्थिति है, जहां पानी का उपभोग जल धारण क्षमताओं से कहीं अधिक हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप न केवल जलस्रोत सूखते जा रहे हैं, बल्कि 'डे-जीरो' परिघटना, प्रवासन और सामाजिक अशांति उत्पन्न होने का खतरा भी मंडराने लगा है।

पानी मानवता के हरेक दिन के गुजारे के लिए अनिवार्य तत्व है। हालांकि कभी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास और निःशुल्क उपलब्ध पानी की निर्ममता से की गई बर्बादी के कारण पानी की उपलब्धता, उपभोग और उसके पुनर्भरण के बीच असंतुलन व्याप्त हो गया। वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ी की पानी की आवश्यकता पर मंडराते संकट का यह एक सर्वप्रमुख कारण है। जलवायु परिवर्तन, भूजल के दोहन, जल संचयन में शिथिलता, प्रदूषण के कारण न केवल नदियां, झीलें और अन्य जलस्रोत सूखते जा रहे हैं, बल्कि उसकी जलधारण क्षमता भी घटती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, साल 1990 के दशक की शुरुआत से अब तक दुनिया की आधे से अधिक बड़ी झीलों का जलस्तर घट चुका है, जबकि साल 1970 के बाद से लगभग 35 प्रतिशत प्राकृतिक आर्द्रभूमियां समाप्त हो चुकी हैं। स्वच्छ पानी की कमी पूरी दुनिया में मानवता के लिए एक बड़ा पर्यावरणीय संकट बन चुका है। दुनियाभर में तकरीबन दो अरब लोग स्वच्छ एवं सुरक्षित जल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, दुनिया की लगभग तीन-चौथाई आबादी ऐसे देशों में रहती है, जिन्हें जल-असुरक्षित या गंभीर रूप से जल-असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है।

वहीं लगभग चार अरब लोग हर साल कम से कम एक महीने के लिए गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। पानी की उपलब्धता प्रभावित होने से मानव जीवन के साथ-साथ स्वास्थ्य और आजीविका पर भी संकट मंडराने लगता है। पानी की कमी और सूखे का आर्थिक प्रभाव भी व्यापक है। इस संकट के कारण हर वर्ष 307 अरब डालर की आर्थिक चपत लगती है। पेयजल संकट से भारत भी अछूता नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल की कमी हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में इस वर्ष के दिसंबर में प्रस्तावित है। पानी की कमी एक ऐसा संकट है, जिससे मानव के साथ-साथ वन्यजीव और वनस्पति भी प्रभावित होता है। हालांकि इससे निपटने के लिए मानव को ही प्रयत्न करने होंगे। अतः आवश्यक है कि सम्मेलनों के आयोजन के साथ-साथ पानी की बर्बादी को रोकने और वर्षा जल संचयन की आदत को परंपरा बनाया जाए।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

अपेक्षित प्रभाव भी दिखाएं परिणाम

'राष्ट्रीय राजनीति को बदलने वाले नतीजे' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राहुल वर्मा ने हालिया चुनाव परिणामों को भारतीय राजनीति के नए मोड़ के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां गठबंधन की वापसी, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और मतदाता के बदले रुझान को रेखांकित किया गया है। यह विश्लेषण महत्वपूर्ण है, परंतु इससे आगे बढ़कर कुछ बुनियादी प्रश्नों पर भी विचार आवश्यक है। चुनाव परिणाम केवल सत्ता के समीकरण नहीं बदलते, बल्कि वे शासन की दिशा और प्राथमिकताओं का भी संकेत देते हैं। फिर भी, बहस अक्सर यहीं थम जाती है कि किसे कितनी सीटें मिलीं। असली मुद्दा यह है कि क्या इन बदलावों से आम नागरिक के जीवन में ठोस सुधार होगा? एक ओर विकास के बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर रोजगार, ट्रैफिक और बुनियादी सेवाओं की चुनौतियां कायम रहती हैं। यह अंतर बताता है कि राजनीतिक विमर्श और जमीनी सच्चाई के बीच खाई अभी भी गहरी है। एक और पहलू जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, वह है स्थानीय नेतृत्व की जवाबदेही। राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाना आसान है, लेकिन वार्ड और नगर स्तर पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना कठिन है। जब तक नीतियों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा और स्थानीय निकायों को वास्तविक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक परिवर्तन अधूरा रहेगा। समाधान के तौर पर राजनीतिक दलों को घोषणापत्रों को केवल वादों का दस्तावेज न बनाकर, उन्हें समयबद्ध कार्ययोजना में बदलना होगा। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, डाटा-आधारित नीति निर्माण और पारदर्शिता को अनिवार्य करना होगा। लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है, जब चुनाव नतीजे केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि शासन की गुणवत्ता में भी बदलाव लाएं। परिणाम तभी सार्थक होंगे, जब वे अपेक्षित प्रभाव भी दिखाएं।

awanishg30@gmail.com

बाय बाय तुष्टीकरण

भारतीय राजनीति में तुष्टिकरण की नीति कोई नई नहीं है, लेकिन जब यह अपनी सीमाएं लांघ जाती है तो उसका परिणाम सत्ता के क्षरण के रूप में सामने आता है। ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा दिया, वह मूलतः उसी ढांचे की उग्र अभिव्यक्ति थी जिसे कांग्रेस ने दशकों पहले स्थापित किया था-एक विशेष वोटबैंक को केंद्र में रखकर सत्ता की रणनीति बनाना। कांग्रेस ने लंबे समय तक इस नीति को ''संतुलन'' के आवरण में चलाया, लेकिन तृणमूल ने इसे खुलकर अपनाया। नतीजा यह हुआ कि तुष्टीकरण एक रणनीति न रहकर पहचान बन गया। जब राजनीति पहचान पर टिक जाती है, तो प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी होती है। बंगाल में यही देखने को मिला-जहां एक समय सर्वग्राही दिखने वाली तृणमूल कांग्रेस धीरे-धीरे एक सीमित वर्ग तक सिमटती चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के विधानसभा चुनावों में यह स्पष्ट संकेत मिला कि बहुसंख्यक मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अपने राजनीतिक विकल्प बदल रहा है। भाजपा का बंगाल में तेज उभार केवल संगठनात्मक विस्तार का परिणाम नहीं था, बल्कि उस असंतोष का राजनीतिक रूपांतरण था जो वर्षों से पनप रहा था। यह वही स्थिति थी, जब मतदाता केवल सरकार नहीं बदलता, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई रेखा खींच देता है। यही पैटर्न उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने भी लंबे समय तक एक विशेष वोटबैंक पर आधारित राजनीति को प्राथमिकता दी। 2012 से 2017 के बीच के शासनकाल में कानून-व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव और प्रशासनिक पक्षपात के आरोपों ने एक बड़ी आबादी के भीतर असंतोष पैदा किया। इसका परिणाम 2017 में सामने आया, जब भाजपा ने अभूतपूर्व बहुमत हासिल किया। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि संदेश था कि मतदाता तुष्टीकरण की राजनीति को अस्वीकार कर रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति तात्कालिक लाभ तो दे सकती है, दीर्घकाल में यह आत्मघाती सिद्ध होती है।

सुशील कुमार बतरा, मेरठ

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

20 अरब डालर (लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये) भारत में निवेश करेगा न्यूजीलैंड दोनों देशों में हुए एफटीए के तहत अगले पंद्रह वर्षों में।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए

भारत की बदलती व्यापार नीति

भारत-न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) केवल टैरिफ में किया गया कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक खंडित होती वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ एक रक्षात्मक ढांचे का निर्माण है। जैसा कि पीयूष गोयल ने आधिकारिक तौर पर कहा कि यह संधि "विकसित दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव में एक निर्णायक मील का पत्थर है।" यह समझौता इस बात का भी संकेत है कि भारत वैश्विक एकीकरण की अपनी शर्तों को मौलिक रूप से फिर से लिख रहा है

डा. स्नेहा भगत
शोधार्थी, जेएनयू

बीते सप्ताह भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) हुआ। इसके लिए भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टाड मैक्ले ने संधि पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता, जो महज 13 महीनों की त्वरित वार्ताओं का परिणाम है, केवल टैरिफ में किया गया कोई सामान्य बदलाव नहीं है, बल्कि यह एक खंडित होती वैश्विक व्यवस्था के खिलाफ एक रक्षात्मक ढांचे का निर्माण है। जैसा कि पीयूष गोयल ने आधिकारिक तौर पर कहा कि यह संधि "विकसित दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव में एक निर्णायक मील का पत्थर है।" हालांकि यह मील का पत्थर केवल कूटनीतिक नहीं है, बल्कि नई दिल्ली की आर्थिक नीति में एक निश्चित बदलाव को भी दर्शाता है। अगले पंद्रह वर्षों में 20 अरब डालर (लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये) की बाध्यकारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) प्रतिबद्धता पर आधारित यह समझौता इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक एकीकरण की अपनी शर्तों को मौलिक रूप से फिर से लिख रहा है। भारत उस पारंपरिक उदार व्यापार सहमति को त्याग रहा है, जिसमें केवल कुछ निर्यात फायदे के लिए टैरिफ कम करने पर जोर दिया जाता था। इसके बजाय भारत अब एक अत्यधिक सोचा-समझा और रक्षात्मक आर्थिक रुख अपना रहा है।

इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच संबंधों की उस ऐतिहासिक सुस्ती को देखना होगा, जो पहले हावी थी। दशकों तक भारत-यूजीलैंड समानांतर पटरियों पर चलते रहे। व्यापार का आकार स्थिर रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह कृषि थी। न्यूजीलैंड, जो फोंटेरा जैसी बड़ी कंपनियों के नेतृत्व में एक वैश्विक डेरी और कृषि महाशक्ति है, हमेशा से भारत के बड़े बाजार तक पहुंच की मांग करता रहा। वहीं भारत, जिसे अपने लाखों छोटे किसानों और विशाल सहकारी डेरी क्षेत्र (जैसे अमूल) की आजीविका की रक्षा करनी थी, इसका दृढ़ता से विरोध करता रहा। इन दोनों देशों ने जिस तरह दशकों पुराने इस गतिरोध को मात्र 13 महीनों में सुलझा लिया, वह दर्शाता है कि वर्तमान में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कितनी तीव्र रणनीतिक आवश्यकताएं और दबाव काम कर रहे हैं।

समकालीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत अपनी प्राथमिक भू-राजनीतिक संपत्ति जैसे-विशाल जनसांख्यिकीय पैमाना और घरेलू मांग का उपयोग कर रहा है। केवल आयातित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने के बजाय नई दिल्ली इस पहुंच को 'संप्रभुता के प्रीमियम' के रूप में मान रही है। दीर्घकालिक पूंजी निवेश की यह स्पष्ट मांग एक ऐसी रणनीति को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य केवल वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भाग लेना नहीं है, बल्कि विदेशी पूंजी, तकनीक और औद्योगिक क्षमता को भारतीय क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करना है। यह माडल शून्य से नहीं उभरा है। यह उस अभूतपूर्व ढांचे को दर्शाता है, जो हाल में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)- जिसमें स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं, के साथ स्थापित किया गया था। उस ऐतिहासिक सौदे में भारत ने चरणबद्ध टैरिफ कटौती के बदले 100 अरब डालर के एफडीआइ की प्रतिबद्धता पर सफलतापूर्वक बातचीत की थी। न्यूजीलैंड के साथ इस "पूंजी-के-बदले-पहुंच" माडल को सफलतापूर्वक दोहराकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि ईएफटीए सौदा कोई अपवाद नहीं था, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने की एक नई आधार रेखा है।

पूंजी के स्थानीयकरण पर यह जोर पिछले कुछ वर्षों में भारत की व्यापक भू-राजनीतिक दिशा को समझने के लिए आवश्यक संदर्भ प्रदान करता है। जब 2019 के अंत में नई दिल्ली औपचारिक रूप से चीन की क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) पहल से हट गई थी, तो पश्चिमी विश्लेषकों ने इस निर्णय को गलत तरीके से 'संरक्षणवाद' के रूप में वर्गीकृत किया था। आलोचकों ने तर्क दिया कि भारत घरेलू राजनीतिक दबावों के कारण पीछे हट रहा है। हालांकि इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया, ईएफटीए और अब न्यूजीलैंड के साथ तेजी से हुए द्विपक्षीय समझौतों ने इस अलगाववादी आलोचना को पूरी तरह अमान्य कर दिया है। भारत का आरसीईपी से हटना एक ऐसे ढांचे की जानबूझकर की गई अस्वीकृति थी, जो अपने साथ गंभीर सुरक्षा खतरे लेकर आ रहा था। मुख्य रूप से राज्य-सब्सिडी वाले विनिर्माण केंद्रों (चीन) से औद्योगिक डंपिंग का खतरा। बड़े, बहुपक्षीय मेगा-ब्लाक अक्सर एक ही क्षेत्रीय महाशक्ति पर निर्भरता थोपते हैं। भारत ने सही आकलन किया कि चीन के दबदबे वाली आपूर्ति श्रृंखला में शामिल होने से उसके सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भारी नुकसान होगा। उस ढांचे से बाहर निकलकर भारत ने एक अत्यधिक सधी हुई कूटनीतिक रणनीति शुरू की।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार संधि के पीछे केवल आर्थिक हित नहीं, बल्कि साझा रणनीतिक अनिवार्यताएं भी काम कर रही हैं। ऐतिहासिक रूप से अपने कृषि और वानिकी निर्यात को खपाने के लिए बीजिंग पर निर्भर रहने वाला न्यूजीलैंड वर्तमान में एक ही प्रमुख बाजार पर अत्यधिक निर्यात निर्भरता का सामना कर रहा है। 2008 में चीन के साथ अपने स्वयं के एफटीए के बाद न्यूजीलैंड की आर्थिक समृद्धि चीनी घरेलू मांग के साथ गहराई से जुड़ गई। आज दक्षिण चीन सागर और व्यापक प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच यह आर्थिक निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी में बदल गई है। इसके कारण न्यूजीलैंड को अपनी आर्थिक निर्भरता में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत को अपने औद्योगिक रूपांतरण को गति देने के लिए इंडो-पैसिफिक मूल्य श्रृंखलाओं में गहरे एकीकरण की आवश्यकता है, लेकिन उसे वाशिंगटन या बीजिंग द्वारा तय किए गए तकनीकी या आर्थिक प्रभुत्व के आगे झुके बिना ऐसा करना है। भारत को 'मेक इन इंडिया' जैसी घरेलू पहलों को बढ़ावा देने और अपनी बढ़ती युवा आबादी के लिए रोजगार सृजित करने हेतु पूंजी, तकनीकी जानकारी और एकीकृत आपूर्ति नेटवर्क की आवश्यकता है। नतीजतन यह समझौता 'क्षैतिज एकीकरण' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महाशक्तियों के साथ ऊर्ध्वाधर संबंधों पर निर्भर रहने के बजाय मध्यम और उभरती शक्तियां अपनी व्यापारिक समीकरण बदल रही हैं। वे पूंजी और माल के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ रही हैं। भारत के लिए ये द्विपक्षीय समझौते रणनीतिक झटकों को सहने वाले के रूप में कार्य करते हैं।

इसके अलावा इस विशाल एफडीआइ प्रतिबद्धता को हासिल करने में भारत की सफलता और साथ ही अपने अत्यधिक संवेदनशील कृषि एवं डेरी क्षेत्रों को सुरक्षित रखना एक परिपक्व और गहरी व्यावहारिक विदेश नीति को उजागर करता है। भारतीय वार्ताकारों ने वेलिंगटन को सफलतापूर्वक आश्वस्त किया कि भारतीय सेवा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में प्रवेश का रणनीतिक मूल्य पारंपरिक डेरी पहुंच की जिद से कहीं अधिक है। यह इस समझ को दर्शाता है कि एक ऐसे युग में जहां लकवाग्रस्त विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, वहां व्यापार के नियम बहुपक्षीय सद्भावना के बजाय 'लीवरेज' (दबाव बनाने की क्षमता) द्वारा तय किए जाते हैं। मुक्त व्यापार समझौतों के प्रति भारत का वर्तमान दृष्टिकोण यह साबित करता है कि 21वीं सदी में संप्रभुता के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के आकार को केवल प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे सक्रिय रूप से आकार देने की आवश्यकता है। इन द्विपक्षीय संधियों के नेटवर्क के माध्यम से नई दिल्ली स्वयं को अपने भागीदारों की रणनीतिक गणनाओं में गहराई से स्थापित कर रहा है। यह सुनिश्चित कर रहा है कि जैसे-जैसे उदार व्यापार व्यवस्था कमजोर हो रही है, भारत एक निर्भर उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि इंडो-पैसिफिक वास्तुकला में एक अपरिहार्य, भारी पूंजीकृत धुरी के रूप में उभरे।

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए केवल औपचारिक करार नहीं, बल्कि भारत की संतुलित शक्ति, रणनीतिक परिपक्वता और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण भी है। फाइल

एफटीए का लाभ उठाने की चुनौती

प्रो. आरके जैन "अरिजीत"

भारत-न्यूजीलैंड एफटीए से भारतीय निर्यात को सभी 8,284 टैरिफ लाइनों पर 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच मिलना अभूतपूर्व है। वहीं न्यूजीलैंड के लगभग 95 प्रतिशत निर्यात मूल्य पर शुल्क में कमी या समाप्ति की राह भी बनी है। भारतीय टेक्सटाइल, परिधान, चमड़ा, जूता और इंजीनियरिंग उत्पाद अब शून्य शुल्क के साथ न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश करेंगे, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कई गुना सशक्त होगी। पहले जो औसत 2.2 प्रतिशत शुल्क एक अदृश्य अवरोध की तरह सामने आता था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अनुमानित 20 बिलियन डालर का निवेश आने वाले वर्षों में रोजगार, नवाचार और तकनीकी प्रगति को गति दे सकता है।

सफलता की असली कसौटी कागजी समझौतों में नहीं, बल्कि उनके ठोस क्रियान्वयन में परिलक्षित होती है। अपेक्षित है कि संसदीय अनुमोदन के बाद यह समझौता 2026 के अंत तक प्रभावी हो जाएगा, किंतु इसके वास्तविक लाभ तभी सामने आएंगे जब भारत अपनी लाजिस्टिक्स व्यवस्था, गुणवत्ता मानकों और वैश्विक विपणन रणनीतियों को सुदृढ़ बनाएगा। तकनीकी हस्तांतरण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों और उद्योगों तक ठोस लाभ पहुंचाना अनिवार्य होगा। वैश्विक व्यापार की तीव्र प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितताओं के बीच यह समझौता भारत को स्थिरता और विस्तार, दोनों का सशक्त आधार प्रदान कर सकता है। (शिक्षाविद्)

खरी-खरी

चुनाव बाद नेताजी

डा. प्रदीप मिश्र

चुनाव के दौरान जो उम्मीदवार सर्वसुलभ होता है, हारने के बाद उससे मिलना कठिन हो जाता है। चुनावी हार उसके जिगर में गहरे जख्म दे जाती है। अब जिगर के जख्म चौराहे पर कोई कैसे दिखाए? इसलिए वह अज्ञातवास में चला जाता है। किसी नजदीकी से पूछो, 'नेताजी कहां हैं?' तो जवाब में वह सिर्फ मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट बताती है, 'अभी कुछ दिन वे अपने मुख का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे।'

अचानक संदेश मिला कि नेताजी मुझे याद कर रहे हैं। उन्हें मेरी याद आनी ही थी। क्या है कि मैं नेताओं की तेल मालिश में निष्णात हूं। अच्छे-अच्छे नेता पिटने और चुनाव हारने के बाद मुझे याद करते हैं। अंतःपुर में पहुंचने पर मैंने देखा, वे बहुत तकलीफ में थे। मैंने उनकी मालिश शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें काफी आराम मिला। वे मुझ पर प्रसन्न थे। मूड अच्छा देख मैंने पूछा, 'कैसे हुआ ये? हमें तो पूरा भरोसा था आपकी जीत का। पैसे बांटने में कोई कमी रह गई क्या?'

'हम जब कमाने में कोई कमी नहीं रखते तो बांटने में कैसे रखेंगे? कंबल, बिरयानी, शराब, साड़ी... कुछ भी बांटने में कोई कमी नहीं की थी।' नेताजी दुखी थे। मैंने उनकी नस दबाते हुए पूछा, 'गुंडों की तो आपके पास चतुरंगणी सेना थी। इनके सेवाभाव में कोई कमी आई क्या?' 'मैं अपने पर शक कर सकता हूं, पर गुंडों की निष्ठा पर सपने में भी शंका नहीं कर सकता। गुंडे मेरा आत्मा हैं।' नेताजी बोले। मैंने पूछा, 'फिर क्या आपके आत्मा छापा-वोट, वोटर-जाम जैसे कार्य संपन्न कराने में असफल रहे? आखिर समस्या क्या थी?'

'समस्या न धन-वितरण में थी, न बल प्रयोग में। असल समस्या मेरी प्रतिकूल ग्रह-दशाएं थीं। चुनावों में ग्रह-नक्षत्र ही तारते हैं, और वही मारते हैं। चुनाव से ठीक पहले ग्रह मेरे विपरीत हो गए थे। बस इसी वजह से जितने वोटों से जीतना था, उतने से पराजय हाथ लगी।' कहते हुए नेताजी ने मुझे वहां से चलता किया।

दर्द कम हुआ था इसलिए वे फोन पर किसी से राज्यसभा के विषय में कोई बात करने लगे थे।

X पोस्ट

क्षेत्रीय दलों के नेता अपने स्वार्थ और राष्ट्रीय सोच के अभाव में एकजुट होने से बचते गए और एक के बाद एक चुनाव हारते गए।
आशुतोष@ashutosh83B

भाजपा बंगाल जीत गई और द्रमुक तमिलनाडु हार गई। दो बड़े क्षेत्रीय दलों का गढ़ ध्वस्त हो गया। यह राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है।
सबा नकवी@_sabanaqvi

राजनीति में कोई भी किला 'अभेद्य' नहीं होना चाहिए। न किसी नेता को यह गलतफहमी होनी चाहिए कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वोटर से बड़ा कोई नहीं और परिवर्तन तो संसार का नियम है।
ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

असम में कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। बंगाल में कांग्रेस के दोनों विधायक भी मुस्लिम हैं। केरलम में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं। 2014 की हार के बाद एंटनी समिति ने कहा था कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण वाली छवि कांग्रेस को भारी पड़ी। 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला।
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आइएनडीआइए के लिए झटका हैं?

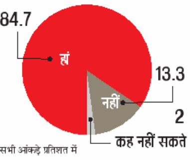

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

अंगड़ाई लेकर उठे जब सनातनी शेर,
'डेंगू के मच्छर' सभी हुए बराबर ढेर।
हुए बराबर ढेर खत्म बंगाल प्रदूषण,
दक्षिण से भी साफ हो गए सब खर-दूषण!
धीरे-धीरे साफ करेंगे फैली काई,
सनातनी जन जाग रहे लेकर अंगड़ाई!!
-ओम प्रकाश तिवारी

पंजाब डायरी

हौसला बढ़ा, पर भाजपा की राह आसान नहीं

रमनजीत सिंह मणकू
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

राष्ट्रीय स्तर से इतर पंजाब के संदर्भ में भी बंगाल के चुनाव परिणाम की चर्चा इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर यह कहा जाता है कि बंगाल और पंजाब की तासीर लगभग एक जैसी है। इसमें ऐतिहासिक तथ्य भी जोड़ा जाता है कि देश की आजादी के आंदोलन में इन दो प्रदेशों के नागरिकों ने बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए थे और जब देश का विभाजन हुआ, तो अंग्रेज हुकूमत ने इन्हीं दो प्रदेशों की जमीन पर लकीरें खींचकर इन्हें प्रताड़ित किया। किसी समय दोनों ही प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रहे हैं।

बहरहाल बंगाल के चुनाव परिणाम से पंजाब के भाजपाई खुश दिखे। प्रदेश कार्यालय में आयोजित जीत के जश्न में पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा करते हुए भाजपा नेताओं ने बंगाल की मशहूर झालमुड़ी का भी स्वाद चखा। नारे लगाकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया गया कि बंगाल का किला फतह करने के बाद अब बारी पंजाब की है। कार्यकर्ता भी जोश में नारे लगाकर हामी भरते रहे, लेकिन पंजाब में जीत इतना भी आसान नहीं है। बीते कई दशकों से भाजपा पंजाब की राजनीति में सक्रिय है और कई बार यहां की सत्ता का स्वाद चख चुकी है, पर यह भी सत्य है कि भाजपा कभी भी इतनी दमखम वाली नहीं रही है कि वह अकेले अपने बूते सत्ता हासिल कर सके। शिरोमणि अकाली दल के साथ ही वह सत्ता में भागीदार रही है।

मौजूदा समय में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार अकेले ही पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत देता रहा है। उस लिहाज से पंजाब में भाजपा के लिए चुनौती काफी बड़ी है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्षों पुराना काडर मौजूद है, जो हर बार भाजपा को ही वोट देता रहा है, लेकिन यह भी तथ्य है कि उम्रदराज चेहरों को युवा पीढ़ी के मतदाता ज्यादा पसंद नहीं करते। शायद यही कारण रहा कि भाजपा ने पिछले चुनावों से सबक लेते हुए बंगाल में भी साल-दर-साल दूसरे दलों के मजबूत और युवा चेहरों को पार्टी के साथ जोड़ा और अपना आधार मजबूत किया। रणनीति में स्थानीय स्तर पर बदलाव किए, जिसके नतीजे के तौर पर जीत हासिल हुई। एक बड़ा तबका बंगाल के इस नतीजे के लिए एसआइआर में काटे गए अवैध वोटों को भी श्रेय देता है।

ऐसा कुछ पंजाब के संदर्भ में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां ज्यादातर जनसंख्या स्थानीय ही है और माइग्रेशन वाले वोट भी पड़ोसी राज्यों से आकर बसे हुए लोगों के हैं। रही बात दूसरे मजबूत राजनीतिक दलों से बड़े और प्रभावशाली चेहरों को साथ जोड़कर चुनाव लड़ने की, तो भाजपा की ओर से इसकी शुरुआत काफी पहले ही कर दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, केवल सिंह ढिल्लों, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जैसे कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री सिकंदर सिंह मलूका के पुत्र गुरप्रीत सिंह मलूका और पुत्रवधू परमपाल कौर मलूका, परमिंदर सिंह बराड़, चरनजीत सिंह बराड़ तथा पंथक राजनीति के बाबा बोहड़ गुरचरन सिंह टोहड़ा की तीसरी पीढ़ी के सदस्य कंवरवीर सिंह टोहड़ा जैसे अकाली नेताओं और कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को समय रहते ही भाजपा की टीम में जोड़ा जा चुका है। जाखड़ तो प्रदेश भाजपा के प्रधान पद पर आसीन हैं। हालांकि बीच-बीच में टकसाली भाजपाई नाराज भी होते रहे, जिसके बाद अश्वनी शर्मा को कार्यकारी प्रधान बनाना पड़ा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए यही बड़ी चुनौती है-पुराने और टकसाली भाजपाइयों को रूठने से रोकना और हर तरफ से युवा एवं मजबूत चेहरों को लाकर पार्टी के साथ जोड़ना। बंगाल में भाजपा को टक्कर तृणमूल कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई, यही कारण है कि उन्हें सत्ता प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। ऐसी स्थिति पंजाब में भी है। भले ही सत्तासीन आम आदमी पार्टी सिर्फ 12-13 वर्ष पुरानी है, लेकिन इससे जुड़े कार्यकर्ता मजबूत हैं। साथ ही शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जूझने को तैयार खड़े हैं।

ऐसे में भाजपा की चुनौती न केवल इन मजबूत कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की होगी, बल्कि उसके बाद अपने काडर को भी इसी तरह के जुझारूपन की तालीम देनी होगी। सबसे बड़ी चुनौती पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ स्तर तक पहुंच बनाने और लोगों में भाजपा के विरोध वाली छवि को खत्म करने की होगी। संभावना जताई जा रही है कि बंगाल के चुनाव का अच्छा परिणाम आने के बाद अब भाजपा नेतृत्व, खासकर अमित शाह का फोकस पंजाब पर रहेगा और उनका यहां आना-जाना भी बढ़ेगा, जिससे पंजाब भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव दमदार तरीके से लड़ने की ऊर्जा मिलेगी। हालांकि चुनावी नतीजों पर इस ऊर्जा का कितना प्रभाव पड़ेगा, यह समय आने पर ही पता चलेगा।

चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद झालमुड़ी बांटकर मनाया जश्न। जागरण

मंथन

बाल स्वास्थ्य की चिंता

भारत जैसे देश में बच्चों का स्वास्थ्य केवल चिकित्सा से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास से जुड़ा एक गंभीर प्रश्न भी है

शिशिर शुक्ला
विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग, स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर

हाल में केंद्र सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-2.0 की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत पारंपरिक बीमारियों के साथ-साथ कुछ नई बीमारियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो तेजी से बच्चों को प्रभावित कर रही हैं। इनमें मुख्य रूप से मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और उनका समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करना है। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2013 में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अभियान के रूप में शुरू किया गया था। आरंभिक चरण में इस कार्यक्रम का मूल मंत्र 4-डी था, जिसमें जन्मजात विकार, रोग, पोषण संबंधी कमियां और विकास में देरी या विकलांगता जैसी बीमारियों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया था। समय के साथ नई बीमारियों ने बच्चों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में अक्षम सिद्ध होने लगा। परिणामस्वरूप बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के स्वरूप को विस्तारित एवं परिवर्द्धित करने की आवश्यकता महसूस हुई।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता देश की बदलती सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का स्वाभाविक परिणाम है। पिछले एक दशक में भारत ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, जैसे शिशु मृत्यु दर में कमी, टीकाकरण का दायरा बढ़ना और संस्थागत प्रसव में वृद्धि। फिर भी बच्चों के समग्र स्वास्थ्य की तस्वीर संतोषजनक नहीं है। कई चुनौतियां पारंपरिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के दायरे से बाहर रह गई हैं और समय के साथ गंभीर रूप ले लिया है। बदलती जीवनशैली, शहरीकरण और तकनीकी प्रभावों ने बच्चों के दैनिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। अनियंत्रित स्क्रीन टाइम, शारीरिक गतिविधियों में कमी और अनियमित खान-पान जैसी आदतों ने मोटापा, मधुमेह के शुरुआती लक्षण और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। इसके साथ ही, बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं एक गंभीर चुनौती बन गई हैं। अवसाद, चिंता, आक्रामक व्यवहार और सीखने में कठिनाइयां अब केवल वयस्कों तक सीमित नहीं रह गई हैं। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बच्चों की एक अच्छी खासी संख्या टाइप वन मधुमेह एवं रक्तचाप जैसी बीमारियों से जूझ रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमेह एवं रक्तचाप जैसी बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इनका मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। नए कार्यक्रम में 4-टी का मूल मंत्र शामिल किया गया है, जिसमें टायलेट, थर्स्टी, टायर्ड और थिनर जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की स्क्रीनिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्कूल आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से की जाएगी।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आया है। किसी भी नीति की सफलता उसके उद्देश्यों में नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन की गुणवत्ता में निहित होती है। भारत जैसे विशाल देश में, जहां भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं, वहां किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है कि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जागरूकता और सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना भी आवश्यक है। तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं। अंततः यह आवश्यक है कि इस कार्यक्रम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कौन-से पहलू प्रभावी हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है। समग्र रूप से देखा जाए तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भारत के भविष्य को नई दिशा देने की क्षमता रखता है। यदि चुनौतियों का सही दृष्टिकोण और ठोस रणनीति के साथ निस्तारण किया जाए, तो यह कार्यक्रम बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। स्वस्थ और सशक्त बचपन ही एक समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान बन सकता है।

एक समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र की पहचान है स्वस्थ और सशक्त बचपन। प्रतीकात्मक

काफी निर्यात जनवरी-अप्रैल में 27 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: देश का काफी निर्यात 2026 की जनवरी-अप्रैल अवधि में 26.6 प्रतिशत बढ़कर 1.74 लाख टन रहा। इसकी मुख्य वजह रोबस्टा और इंस्टेंट काफी के निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। पिछले साल इसी अवधि में देश ने 1.37 लाख टन कॉफी का निर्यात किया था। भारत अरेबिका और रोबस्टा किस्मों के साथ-साथ इंस्टेंट काफी का भी निर्यात करता है। मूल्य के हिसाब से, कुल निर्यात एक साल पहले के 757.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 936.57 करोड़ रुपये हो गया। (प्रेट्र)

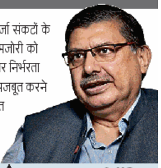

पश्चिम एशिया संघर्ष ने ऊर्जा संकटों के प्रति भारत की ढांचागत कमजोरी को उजागर किया है। ऐसे में आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत बढ़ गई है।

- नागेश कुमार, एमपीसी सदस्य

सेंसेक्स	77,017.79	▼ 251.61
निफ्टी	24,032.80	▼ 86.50
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,52,500	▼ ₹ 300
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,51,000	▲ ₹ 1,500
डालर	₹ 95.18	▼ ₹ 0.05
क्रूड प्रति बैरल	$ 113	

एक नजर में

प्रमोटर इकाई ने अदाणी पोर्ट का दो प्रतिशत हिस्सा बेचा

नई दिल्ली: प्रमोटर समूह की इकाई ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनमिक जोन की दो प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है। यह हिस्सेदारी खुला बाजार लेनदेन के जरिये 7,486 करोड़ रुपये में बेची गई है। बीएसई पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, अदाणी पोर्ट्स के प्रमोटर समूह की इकाई वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड ने यह हिस्सेदारी अमेरिका के कैपिटल ग्रुप को बेची है। यह सौदा 1,632.45 रुपये प्रति शेयर पर हुआ है और प्रमोटर इकाई ने कुल तीन किस्तों में 4,58,58,705 शेयरों की बिक्री की है। (प्रेट्र)

14 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करेगा क्वाइनबेस

नई दिल्ली: क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइनबेस ने मंगलवार को कहा कि वह अपने 14 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। इसका कारण यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) लोगों के काम करने के तरीके को बदल रहा है। कंपनी ने कहा कि प्रभावित सभी टीम सदस्यों को उनके पर्सनल अकाउंट पर ज्यादा जानकारी के साथ एक ईमेल मिलेगा। एक्सचेंज के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने एक्स पोस्ट में कहा, आज मैंने क्वाइनबेस का आकार 14 प्रतिशत तक कम करने का कठिन निर्णय लिया है। (आइएएनएस)

महिंद्रा एंड महिंद्रा का शुद्ध लाभ 48.5 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मंगलवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में उसका शुद्ध लाभ 48.5 प्रतिशत बढ़कर 5,259.91 करोड़ रुपये रहा है। इसमें आटो और कृषि क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है। जनवरी-मार्च 2025 में कंपनी को 3,541.85 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बीती तिमाही के दौरान कंपनी का संचालन राजस्व 54,891.55 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 42,585.67 करोड़ रुपये था। कंपनी ने 33 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। (प्रेट्र)

अप्रैल में 26 लाख से ज्यादा वाहनों की खुदरा बिक्री

जीएसटी में कटौती, रेपो रेट में नरमी और मजबूत रबी फसल ने आटोमोबाइल उद्योग को दी रफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में मोटर वाहनों की कुल खुदरा बिक्री अप्रैल में 12.94 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 26,11,317 इकाई रही जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 23,12,221 यूनिट थी। उद्योग संगठन 'फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन' (फाडा) ने मंगलवार को कहा कि जीएसटी में कटौती, आरबीआइ द्वारा रेपो रेट में नरमी, मजबूत रबी फसल के बाद ग्रामीणों के हाथ में आए पैसे जैसे सकारात्मक कारकों ने उद्योग को मजबूत प्रदर्शन में मदद की।

यात्री वाहन (पीवी) की खुदरा बिक्री पिछले महीने रिकार्ड 4,07,355 इकाई रही जो अप्रैल 2025 के 3,63,028 इकाइयों की तुलना में 12.21 प्रतिशत अधिक है। दोपहिया वाहनों की बिक्री भी अप्रैल में अब तक के सर्वाधिक मासिक स्तर 19,16,258 इकाइयों पर पहुंच गई। यह पिछले वर्ष के इसी महीने की 16,95,638 इकाइयों की तुलना में 13.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। तिपहिया वाहनों की बिक्री अप्रैल 2025 की 99,741 इकाइयों के मुकाबले 7.19 प्रतिशत बढ़कर 1,06,908 इकाई पर पहुंच गई। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी अप्रैल 2025 के 86,364 इकाइयों से 15.02 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रिकार्ड 99,339 इकाई रही। अगले तीन महीनों के परिदृश्य पर फाडा ने कहा कि लगभग 51 प्रतिशत डीलर वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।

भारतीय मोटर वाहन खुदरा उद्योग ने वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत बेहद मजबूत तरीके से की है। छह में से पांच वाहन श्रेणियों में अप्रैल में अब तक के सर्वोच्च रिकार्ड दर्ज किए गए, जो यह दर्शाता है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में दिखी संरचनात्मक मांग नए वित्त वर्ष में भी जारी है।

- साई गिरधर, वाइस प्रेसिडेंट, फाडा

बिक्री पर प्रभाव डाल सकती है पश्चिमी एशिया की स्थिति

मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कई राज्यों में सामान्य से अधिक गर्मी की भविष्यवाणी, पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिति और ईंधन कीमतों पर संभावित प्रभाव तथा कुछ माडल की आपूर्ति में बाधाएं दोपहिया खंड के लिए जोखिम कारक हैं। पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव के अलावा वाणिज्यिक वाहन खंड में नकदी भी एक महत्वपूर्ण कारक रहेगी, जिस पर नजर रखनी होगी।

तिपहिया वाहन सेगमेंट में ईवी की हिस्सेदारी 60.38%

नई दिल्ली, एएनआइ: पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के चलते ईंधन कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव का असर वाहनों की मांग पर दिखाई दिया। फाडा के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी श्रेणी में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी का रुझान दिखाई दिया। तिपहिया वाहन सेगमेंट में ईवी की हिस्सेदारी 60.38 प्रतिशत तक हो गई है। यात्री वाहनों में ईवी की हिस्सेदारी बढ़कर 5.77 प्रतिशत हो गई जबकि दोपहिया श्रेणी में यह

हिस्सेदारी 7.76 प्रतिशत रही। मार्च दोपहिया वाहनों हिस्सेदारी 9.79 प्रतिशत थी। ईवी इंसेंटिव बंद होने से पहले हुई तेज खरीदारी के चलते मार्च का आंकड़ा ज्यादा बढ़ा दिखाई दे रहा है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

बैंकिंग सेक्टर पर वित्त मंत्रालय व मैकेंजी का अलग-अलग दावा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। फंसे कर्ज (एनपीए) रिकार्ड न्यूनतम स्तर पर हैं। वित्त मंत्रालय ने इस आधार पर मंगलवार को बैंकिंग उद्योग के मौजूदा दौर को पिछले कई दशकों का सबसे शानदार करार दिया। लेकिन इसी दिन वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी एंड कंपनी ने चेतावनी दी कि अब मुनाफा बढ़ाना और मार्जिन बनाए रखना भारतीय बैंकिंग के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दोनों रिपोर्टों के बीच का यह विरोधाभास भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर भी कुछ गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है।

- वित्त मंत्रालय ने उद्योग के मौजूदा दौर को पिछले कई दशकों का सबसे शानदार समय बताया
- कंसल्टेंसी फर्म ने कहा- बैंकिंग सेक्टर ऐसे मोड पर पहुंचा, जहां से नीचे जाने का खतरा

वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-खाद्य ऋण वृद्धि दर 15.9 प्रतिशत रही, जो पिछले साल के 10.9 प्रतिशत से 497 आधार अंक की भारी बढ़ोतरी है। कुल ऋण बकाया मार्च 2026 तक 212.9 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 29.2 लाख करोड़ रुपये अधिक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ऋण वृद्धि 15.7 प्रतिशत (पिछले साल 10.4), उद्योग क्षेत्र में 15 प्रतिशत (पिछले साल 8.2), सेवा क्षेत्र में 19 प्रतिशत (पिछले साल 12) और व्यक्तिगत ऋणों में 16.2 प्रतिशत (पिछले साल 11.7) की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंत्रालय ने इसे आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और निजी निवेश में उछाल का नतीजा बताया और कहा है कि कम ब्याज दर वातावरण, सरकारी पूंजीगत खर्चे में वृद्धि और संरचनात्मक सुधारों ने निजी निवेश को बढ़ावा दिया है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है और बैंकिंग सेक्टर ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम फंसे कर्जे और पर्याप्त पूंजी के साथ अर्थव्यवस्था का इंजन बनकर उभरा है।

बैंकों को जमा जुटाने के लिए देना पड़ रहा ज्यादा ब्याज : मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां से आगे नीचे जाने का खतरा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) के 1.4 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (निम) 3.3 प्रतिशत से घटकर 3.1 प्रतिशत रह गया है। ऋण-जमा अनुपात दशक के उच्चतम स्तर 80 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जिससे बैंक महंगे टर्म डिपाजिट की ओर मजबूर हो रहे हैं। यानी बैंकों को जमा जुटाने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। मैकेंजी का यह भी कहना है कि असुरक्षित रिटेल लोन में कर्ज अदाएगी में गड़बड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। पर्सनल लोन में एनपीए 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 1.6 प्रतिशत और क्रेडिट कार्ड एनपीए 2.2 से 3.3 प्रतिशत हो गया है। परिचालन खर्च तेजी से बढ़ रहा है, खासकर प्राइवेट बैंकों में, लेकिन आय में उतनी वृद्धि नहीं हो रही।

रेगुलेटरी बदलाव और टेक्नोलाजी के बीच संतुलन बनाना चुनौती: मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेगुलेटरी बदलाव, ग्राहक व्यवहार और तेज टेक्नोलाजी को अपनाने के बीच संतुलन बनाना अब चुनौती है। मैकेंजी ने पांच आयामों वित्तीय प्रदर्शन, उद्योग स्वास्थ्य, ग्राहक अनुभव, सामाजिक प्रभाव और परिचालन लचीलापन पर बैंकिंग सेक्टर का मूल्यांकन किया है। रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि बैंकों को अब केवल मुनाफे पर नहीं, बल्कि जोखिम प्रबंधन, लागत अनुशासन, साइबर सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान देना होगा। जाहिर है कि रिपोर्ट बैंकिंग के मौजूदा सुनहरे दौर के चुनौतीपूर्ण दौर में बदलने को लेकर सचेत कर रहा है।

आइफोन-17 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन

नई दिल्ली, आइएएनएस: एपल का आइफोन-17 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा। वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन बिक्री में इसकी हिस्सेदारी छह प्रतिशत रही। काउंटरप्वाइंट रिसर्च के मुताबिक, स्मार्टफोन की सूची के पहले 10 स्थानों में से तीन पर आइफोन-17 के विभिन्न माडल रहे। पांच माडल के साथ सैमसंग गैलेक्सी-ए सीरीज की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही।

जनवरी-मार्च 2026 के दौरान वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन बिक्री में शीर्ष 10 में शामिल माडल की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत रही। काउंटरप्वाइंट के वरिष्ठ विश्लेषक हर्षित रस्तोगी ने कहा कि आइफोन-17 अपने पिछले माडल से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा बेस स्टोरेज, बेहतर कैमरा रेजोल्यूशन और बेहतर डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जैसे खास अपग्रेड हैं, जिससे यह प्रो वेरिएंट के करीब आ गया है। आइफोन ने चीन और

- वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन बिक्री में आइफोन-17 की हिस्सेदारी छह प्रतिशत रही
- स्मार्टफोन बिक्री में शीर्ष 10 में शामिल माडल की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत रही

अमेरिका जैसे बाजार में साल-दर-साल दो अंकों की वृद्धि दर्ज की और दक्षिण कोरिया में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे उभरते बाजार में मजबूत मांग के चलते एंड्रायड डिवाइस में सैमसंग का गैलेक्सी ए07 4जी सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बना। बेहतर साफ्टवेयर और सिक्योरिटी सपोर्ट ने वैल्यू फोकस्ड खरीदारों के बीच इसकी मांग को बढ़ाया।

उधर, साइबरमीडिया रिसर्च ने अनुमान जताया कि चिप की कीमत बढ़ने से 2026 में भारत में स्मार्टफोन बिक्री में 10-12 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

आयातित रेंज रोवर के मूल्य में 75 लाख रुपये तक की कटौती

नई दिल्ली, प्रेट्र: जेएलआर इंडिया ने मंगलवार को ब्रिटेन से पूरी तरह से निर्मित आयातित रेंज रोवर के मूल्य में 75 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की। टाटा समूह की इस कंपनी ने भारत-ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने से पहले ही यह कदम उठाया है। कंपनी ने कहा कि एफटीए से लाभान्वित होने वाले प्रमुख माडल रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी हैं।

कंपनी ने बताया कि इस कटौती के बाद भारत में रेंज रोवर एसवी की कीमत 4.25 करोड़ से घटकर 3.5 करोड़ रुपये (शुरुआती कीमत, एक्स-शोरूम) और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी की कीमत 2.75 करोड़ रुपये से घटाकर 2.35 करोड़ रुपये हो गई है। इससे बाजार में इसकी स्थिति काफी मजबूत हुई है। संशोधित कीमतें एफटीए के तहत लागू नई ड्यूटी संरचना को दर्शाती हैं और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

निफ्टी-500 में डीआइआइ ने एफआइआइ को पीछे छोड़ा

मुंबई, आइएएनएस: भारतीय शेयर बाजार में घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआइआइ) की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। मार्च, 2026 में निफ्टी500 कंपनियों में डीआइआइ की हिस्सेदारी रिकार्ड 20.9 प्रतिशत तक पहुंच गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमओएफएसएल) की रिपोर्ट के अनुसार, लगातार आठवीं तिमाही में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। साल-दर-साल आधार पर हिस्सेदारी में 170 आधार अंकों की वृद्धि हुई है जबकि तिमाही आधार पर 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी हुई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की हिस्सेदारी 17.1 प्रतिशत के नए निचले स्तर पर आ गई है।

निफ्टी 500 में एफआइआइ-डीआइआइ का अनुपात अब घटकर 0.8 गुना रह गया है। यह एक ऐसा स्तर है, जो भारत के शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है, उसका संकेत देता है। एमओएफएसएल के

Nifty500

मार्च, 2026 में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी रिकार्ड 21% हुई, एफआइआइ की हिस्सेदारी 17.1 प्रतिशत पर आई

अनुसार, डीआइआइ की मजबूती के पीछे मुख्य चालक एसआइपी के माध्यम से लगातार निवेश आना रहा है। कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली तिमाही में, घरेलू कंपनियों ने भारतीय इक्विटी में 27.2 अरब डालर का निवेश किया जबकि विदेशी निवेशकों ने 15.8 अरब डालर निकाले। विदेशी निवेशकों ने अकेले 14.2 अरब डालर मार्च में निकाले। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार जब पश्चिम एशिया में शांति आ जाएगी तो एफआइआइ निवेश का माहौल बेहतर होने की संभावना है।

राष्ट्रीय फलक

नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, भूपेंद्र हुड्डा को नोटिस जारी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

पंचकूला स्थित नेशनल हेराल्ड प्लाट आवंटन मामले में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सीबीआइ द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद शीर्ष अदालत ने हुड्डा को नोटिस जारी किया है।

फरवरी 2026 में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि रिकार्ड पर ऐसा कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपितों ने कोई अपराध किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई निर्णय नीति या दिशा-निर्देशों के विपरीत लिया गया हो, तो मात्र इसी आधार पर उसे भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए आरोपों को रद कर दिया गया और पूरे मामले की कार्यवाही समाप्त कर दी गई। इसके बाद सीबीआइ की विशेष अदालत और ईडी की अदालत ने भी अपने-अपने केस बंद कर दिए थे।

सीबीआइ की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में गंभीर खामियां छोड़ी हैं। जांच एजेंसी ने दलील दी कि उपलब्ध साक्ष्यों से भ्रष्टाचार निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध बनता है।

- सीबीआइ ने हाई कोर्ट के निर्णय को शीर्ष अदालत में दी चुनौती
- हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद करते हुए हुड्डा को दी थी राहत

यह है मामला

इस मामले की जड़ें पंचकूला के सेक्टर-6 में स्थित प्लाट नंबर सी-17 से जुड़ी हैं। यह जमीन मूल रूप से एसोसिएट्स जनरल्स लिमिटेड (एजेएल) को 1982 की दरों पर 'नो-प्राफिट, नो-लास' आधार पर दी गई थी, ताकि वहां अखबार का प्रकाशन शुरू हो सके, लेकिन निर्माण नहीं होने से 1996 में यह प्लाट वापस ले लिया गया। विवाद तब खड़ा हुआ, जब वर्ष 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसी प्लाट को दोबारा पुरानी दरों पर एजेएल को आवंटित किया गया। एजेंसियों का आरोप है कि यह पुनः आवंटन नियमों के खिलाफ था और इससे राज्य सरकार को 1.75 करोड़ का नुकसान हुआ। ईडी ने दावा किया कि एजेएल ने इस जमीन को स्वच्छ संपत्ति दिखाकर करीब 72.57 करोड़ के ऋण हासिल किए और बाद में संपत्तियां बनाईं।

अब यूपीएससी नतीजों में दिखेगी उप-जाति की झलक

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों में अब एक बड़ा और पारदर्शी बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक महत्वपूर्ण सिफारिश भेजी है। इसमें कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अंतिम चयन परिणामों में केवल मुख्य श्रेणियों (एससी, एसटी, ओबीसी) का ही जिक्र न हो, बल्कि अभ्यर्थियों की उप-जाति का विवरण भी शामिल किया जाए। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण और 'सकारात्मक कार्रवाई' का लाभ वास्तव में उन वर्गों तक पहुंच रहा है या नहीं, जो अब भी हाशिए पर हैं।

यह मामला तब सामने आया जब आरटीआइ आवेदक ने 1995 की सिविल सेवा में चयनित आइएएस की जाति-वार जानकारी मांगी थी।

व्यापारिक संबंध और प्रगाढ़ करेंगे भारत और जमैका : जयशंकर

किंग्स्टन, प्रेट्र: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जमैका व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। स्वास्थ्यकर्मियों और शिक्षकों समेत कुशल पेशेवरों की भर्ती व दोनों देशों में उनके आवागमन को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की संभावनाओं को तलाशने पर सहमत भी हुए हैं। जयशंकर इस कैरेबियाई देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। वह जमैका, सूरीनाम व त्रिनिदाद और टोबैगो की अपनी नौ दिवसीय यात्रा के तहत शनिवार को किंग्स्टन पहुंचे।

जयशंकर ने सोमवार को जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस से मुलाकात की और फिर विदेश व व्यापार मंत्री कामिना जानसन स्मिथ के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। स्मिथ के साथ संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि व्यापक चर्चा हुई और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए नए रास्ते भी तलाशे गए। हमने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।

- विदेश मंत्री ने जमैका की समकक्ष के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता
- स्वास्थ्य, सौर ऊर्जा और प्रसारण के क्षेत्रों में तीन समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

किंग्सटन में मंगलवार को यूनिवर्सिटी आफ वेस्ट इंडीज मोना कैंपस में संबोधित करते विदेश मंत्री एस जयशंकर। एएनआइ

बैंकों के अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़े नियमों का मसौदा जारी

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा कर्ज वसूली के तौर पर अचल संपत्ति के अधिग्रहण के नियम तय करने के लिए मसौदा जारी किया है। इन नियमों का उद्देश्य स्पष्टता लाना और अचल संपत्तियों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करना है।

26 मई तक आम लोग आरबीआइ के इस मसौदे पर अपनी राय दे सकते हैं। दरअसल, बैंक सामान्यतः अचल संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करते हैं। हालांकि, जब कोई कर्ज एनपीए बन जाता है और कानूनी उपाय काम नहीं आते हैं तो बैंक रिकवरी के लिए अचल संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। इन संपत्तियों को रखने की अधिकतम अवधि सात साल प्रस्तावित की गई है। जोखिम को कम करने को बैंक अधिग्रहित अचल संपत्ति को मूल उधारकर्ता या उससे संबंधित पक्ष को नहीं बेच पाएंगे।

बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार ने भतीजी क्लेयर को बनाया उत्तराधिकारी

नई दिल्ली, आइएएनएस: भारत की प्रमुख बायोटेक्नोलाजी कंपनी बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार शा ने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। फार्च्यून इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में 73 वर्षीय मजूमदार ने कहा कि वह क्लेयर (37) को बायोकान की वृद्धि को अगले चरण में ले जाने के लिए सही व्यक्ति मानती हैं।

उन्होंने कहा, "मैं बायोकान की अकेली मालकिन हूं और मुझे यह पक्का करना है कि मैं इसे अच्छे हाथों में सौंपूं। मैंने अपनी भतीजी क्लेयर को अपना उत्तराधिकारी इसलिए बनाया है, क्योंकि उसने साबित किया है कि वह एक कंपनी चला सकती है।" क्लेयर अभी बिकारा थेराप्यूटिक्स की संस्थापक और सीईओ हैं। नैस्डेक सूचीबद्ध इस कंपनी की स्थापना बायोकान की मदद से की गई थी।

किरण मजूमदार शा के कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा, 'एक बड़ा फैमिली इकोसिस्टम भी कंपनी की वृद्धि में मदद कर सकता है। इसमें क्लेयर के भाई एरिक मजूमदार भी हैं।

एरिक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में प्रोफेसर और एआइ विशेषज्ञ हैं।' कंपनी में बड़े बदलाव के हिस्से के तौर पर बायोकान ने अपने जेनरिक और बायोलाजिक्स बिजनेस का विलय कर दिया है और कर्ज को कम किया है। किरण ने कहा कि कंपनी बायोसिमिलर पर अपना फोकस बढ़ा रही है, जिसकी कंपनी के राजस्व में बड़ी भूमिका है।

किरण मजूमदार शा व क्लेयर। फाइल

एफडीआइ प्रस्तावों का 12 सप्ताह में होगा निपटान, जारी की गई नई एसओपी

नई दिल्ली, प्रेट्र: उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। नई एसओपी के अनुसार, सरकार अब एफडीआइ से जुड़े सभी आवेदनों का 12 सप्ताह में निपटान किया जाएगा। इसमें वह समय शामिल नहीं है जो आवेदक प्रस्तावों में कमियों को दूर करने या सक्षम अधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी देने में लगाते हैं। 2017 के एसओपी में एफडीआइ आवेदन के निपटान के लिए अधिकतम 10 सप्ताह का समय तय किया गया था। नई एसओपी के मुताबिक, डीपीआइआइटी को उन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दो हफ्ते का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, जिन्हें खारिज करने का प्रस्ताव है या जिन पर सक्षम अधिकारी द्वारा अतिरिक्त शर्तें लगाने का प्रस्ताव है। डीपीआइआइटी ने कहा कि इस एसओपी का उद्देश्य एफडीआइ आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। इसलिए, आवेदक को प्रस्तावों प्रस्तावों को प्रोसेस करने के लिए जरूरी किसी भी दस्तावेज की फिजिकल कापी जमा करने की जरूरत नहीं होगी। डीपीआइआइटी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा है जो एफडीआइ से जुड़े मामलों को देखता है।

- डीपीआइआइटी ने एफडीआइ को लेकर जारी की नई एसओपी
- 2017 की एसओपी में 10 सप्ताह का समय तय किया गया था

नई एसओपी के मुताबिक, सभी आवेदनों को विदेश मंत्रालय को उसकी टिप्पणियों और मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। एसओपी में कहा गया है कि किसी भी प्रस्ताव पर जिन सभी मंत्रालयों और विभागों से सलाह ली जाती है उनमें आरबीआइ, गृह और विदेश मंत्रालय शामिल हैं। इन सभी को तय समयसीमा के भीतर अपनी टिप्पणियां देनी होंगी। तय समय में टिप्पणी नहीं मिलती है तो मान लिया जाएगा कि उनके पास देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।

इसके अलावा सरकार ने रेयर अर्थ-मैग्नेट और प्रिंटेड सर्किट जैसे 40 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनके लिए जमीन साझा करने वाले देशों से आने वाले एफडीआइ प्रस्तावों को 60 दिन में मंजूरी दी जाएगी। भारत से जमीन साझा करने वाले देशों में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में निवेश प्राप्त करने वाली संस्था की अधिकांश हिस्सेदारी और नियंत्रण हर समय भारत के निवासी नागरिक या संस्था के पास हो।

बैंकों के खाताधारक उदगम पोर्टल पर खोज सकते हैं दावारहित जमा

नई दिल्ली, प्रेट्र: आरबीआइ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उदगम पोर्टल पंजीकृत खाताधारक को दावारहित जमा को खोजने की सुविधा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंक ने यह दलील जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय विश्नोई की उस पीठ के सामने दी, जो पत्रकार सुचेता दलाल की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुचेता दलाल ने अपनी याचिका में मृत खाताधारक के कानूनी वारिसों को बैंक खाते में पड़े दावा रहित जमा के बारे में बताने के लिए एक प्रणाली बनाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

आरबीआइ की ओर से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उदगम पर लगभग 44 लाख सर्च किए गए हैं और यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि बड़ा मुद्दा यह है कि मृतक खाताधारक के कानूनी वारिसयों को बैंक खातों में पड़े दावा रहित जमा के बारे में कैसे पता चलेगा। केंद्र की तरफ से पेश वकील ने पीठ को बताया कि उन्होंने एक नया एफिडेविट तैयार किया है, जिसे कोर्ट में फाइल किया जाएगा। पीठ ने केंद्र से एक हफ्ते के अंदर संबंधित विवरण देते हुए अपडेटेड एफिडेविट फाइल करने को कहा और मामले की अगले सुनवाई 19 मई तय कर दी। 17 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने केंद्र और आरबीआइ से पूछा था कि आखिर मृतकों के बैंक खातों का विवरण उनके वारिसों को क्यों नहीं बताया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर एक नीति बनानी चाहिए।

- आरबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, कहा-पोर्टल पर अब तक 44 लाख सर्च किए गए
- मृत खाताधारक के कानूनी वारिसों को धन दिलाने वाली याचिका पर कोर्ट कर रहा था सुनवाई

24 फरवरी 2022 को रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की थी। तब से अब तक युद्ध में हजारों की संख्या में सैनिक और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। लाख लोग विस्थापित भी हुए हैं।

साइबर धोखाधड़ी उजागर करने वाले दो भारतीय पत्रकारों ने जीता पुलित्जर

- आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा ने जीता यह प्रतिष्ठित पुरस्कार
- दोनों को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में मिला सम्मान

सुपर्णा शर्मा व आनंद आरके। सौ. एक्स@डीडीन्यूज

न्यूयार्क, प्रेट्र : दो भारतीय पत्रकारों ने पत्रकारिता क्षेत्र के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी उजागर करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा सोमवार को हुई।

आनंद और सुपर्णा को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में यह सम्मान मिला है। उन्होंने इस पुरस्कार को ब्लूमबर्ग की नताली ओबिको पियर्सन के साथ साझा किया है। पुलित्जर पुरस्कार की वेबसाइट के अनुसार, "ट्रैप्ड" शीर्षक से ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की गई यह खबर भारत की एक न्यूरोलाजिस्ट की सहमा देने वाली कहानी बयां करती है, जिन्हें डिजिटल अरेस्ट किया गया था। तस्वीरों और शब्दों के अनूठे मिश्रण से तैयार इस खबर ने डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते वैश्विक खतरे को बेहद प्रभावशाली तरीके से उजागर किया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ओर से संचालित पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों में गिना जाता है।

चीन पर खोजी रिपोर्टिंग के लिए एपी को पुरस्कार : एपी के अनुसार, चीन में सरकारी निगरानी और इसमें अमेरिकी टेक कंपनियों की भूमिका को लेकर अपनी खोजी खबरों के लिए एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है। एपी के पत्रकारों डेक कांग, गैरांस बर्क, बायरन ताउ, अनिरुद्ध घोषाल और स्वतंत्र पत्रकार येल ग्राउर को पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

डोनाल्ड ट्रंप को लेकर रायटर ने जीते दो पुस्कार

रायटर के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक बदले से जुड़े अभियान और इंटरनेट मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा के जान-बूझकर अपने यूजर्स को नुकसान पहुंचाने वाले एआइ चैटबाट्स और धोखाधड़ी संबंधी विज्ञापनों की रिपोर्टिंग के लिए रायटर ने दो पुलित्जर पुरस्कार जीते हैं।

रूस के मिसाइल-ड्रोन हमले में यूक्रेन के गैस संयंत्रों पर पांच की मौत

कीव, रायटर: रूस ने यूक्रेन के गैस उत्पादन संयंत्रों पर मंगलवार को मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने कहा, रूस की सेना ने पोल्टावा व खार्किव क्षेत्रों में गैस उत्पादन संयंत्रों पर हमला किया, जिसमें तीन कर्मचारी और दो आपातकालीन सेवा कर्मी मारे गए, जबकि 37 लोग घायल हो गए। इस बीच, यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हमला किया। हमले के कारण किरीशी शहर के एक औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई, जिसे काबू कर लिया गया है।

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि प्रचार के उद्देश्य से युद्धविराम की मांग करना और इसके बाद मिसाइल व ड्रोन हमले करना घोर निंदनीय है। इससे एक दिन पहले पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के लिए आठ से नौ मई तक दो दिनी युद्धविराम की घोषणा की थी।

पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में फंसे भारतीय पोत के लिए दिखाई दरियादिली

- ओमान से भारत की ओर बढ़ रहे भारतीय पोत 'एमवी गौतम' में अचानक आई तकनीकी खराबी
- मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोआर्डिनेशन सेंटर ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क साधा
- फंसे चालक दल को तकनीकी सहायता के साथ भोजन व जरूरी चिकित्सा सहायता भी दी गई

भारतीय पोत एमवी गौतम। फाइल»

इस्लामाबाद, प्रेट्र : अरब सागर की लहरों के बीच जब जिंदगी और मौत का संघर्ष चल रहा था, तब मानवता ने सरहदों की दीवारों को बौना साबित कर दिया। ओमान से भारत की ओर बढ़ रहे भारतीय जहाज 'एमवी गौतम' में आई तकनीकी खराबी ने चालक दल को गहरे संकट में डाल दिया। इस आपात स्थिति में पाकिस्तानी नौसेना और पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने दरियादिली दिखाते हुए सहायता का हाथ बढ़ाया।

संकट का संदेश और तत्काल सक्रियता : जहाज पर सवार छह भारतीय और एक इंडोनेशियाई नागरिक उस समय सकते में आ गए जब इंजन में अचानक खराबी आ गई। संकट की गंभीरता को देखते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोआर्डिनेशन सेंटर ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क साधा। सूचना मिलते ही पाकिस्तानी नौसेना ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। यह केवल एक मिशन नहीं, बल्कि समुद्र में फंसे नाविकों की उम्मीदों को बचाने की जंग थी।

सहायता का हाथ और मानवीय संवेदनाएं : अंग्रेजी दैनिक 'डान' ने पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया, फंसे हुए चालक दल को न केवल तकनीकी सहायता दी गई, बल्कि उनके लिए भोजन और आवश्यक चिकित्सा सहायता भी सुनिश्चित की गई। समुद्र के सीने पर यह दृश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का एक जीवंत उदाहरण बन गया।

पाकिस्तानी नौसेना ने पिछले महीने भी ऐसी ही सक्रियता दिखाते हुए एक अन्य व्यापारिक जहाज के 18 सदस्यों की जान बचाई थी। फिलहाल, भारतीय जहाज को पूरी तरह ठीक करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया है कि कूटनीतिक तनाव के बीच भी मानवता का लंगर कभी कमजोर नहीं पड़ता।

गोलीबारी के बावजूद अमेरिका-ईरान युद्धविराम बरकरार, तेल कीमतों में राहत

पश्चिम एशिया में तनाव ▸ होर्मुज में 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के दौरान झड़प, फिर भी टकराव सीमित

- कच्चा तेल तीन प्रतिशत गिरकर 111 डालर प्रति बैरल पर आया
- अमेरिका बोला- ईरान के हमले इतने गंभीर नहीं, जवाब टाला
- ईरान का आरोप- अमेरिकी नौसेना ने नागरिक नौकाओं को बनाया निशाना

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच मंगलवार को राहत की बात रही कि होर्मुज जलडमरूमध्य में झड़पों के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम कायम है। 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' के तहत फंसे जहाजों को निकालने की अमेरिकी कोशिशों के विरोध में ईरान ने हमले किए, जिनके जवाब में अमेरिकी नौसैनिक कार्रवाई भी हुई, पर दोनों पक्षों ने स्थिति को सीमित रखा।

एपी के अनुसार, अमेरिका ने कहा, ईरानी हमले इतने गंभीर नहीं थे कि करारा जवाब देकर युद्धविराम तोड़ा जाए। ज्वाइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल डैन केन के अनुसार, सी हाक व अपाचे हेलीकाप्टरों ने ईरान की छह सैन्य नौकाओं को डुबो दिया। कहा, युद्धविराम के बाद से ईरान नौ बार वाणिज्यिक जहाजों पर हमला कर चुका है, दो जहाज जब्त किए गए हैं और 10 से अधिक बार अमेरिकी बलों को निशाना बनाया गया है।

दूसरी ओर, ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा, अमेरिकी नौसेना ने रिवोल्यूशनरी गार्ड के डर में नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया, जिसमें पांच की मौत हुई। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये नौकाएं ओमान के खसाब तट से ईरान की ओर जा रही थीं और इनमें यात्री व व्यापारिक सामान था।

प्रेट्र के अनुसार, तनाव सीमित रहने से वैश्विक तेल बाजार को राहत मिली और कच्चे तेल के दाम तीन प्रतिशत गिरकर 111 डालर प्रति बैरल पर आ गई। यूएई पर हालिया हमले की पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कड़ी आलोचना की है, जबकि ईरान ने इसे न तो स्वीकारा, न ही खारिज किया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचना चाहिए।

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा,'प्रोजेक्ट फ्रीडम' अस्थायी मिशन है। इसका उद्देश्य जहाजों को सुरक्षित मार्ग देना है। होर्मुज में 1550 से अधिक जहाजों पर 22,500 नाविक मौजूद हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने अपने ध्वज वाले दो जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया। उधर, ईरानी संसद के स्पीकर एमए गलीबाफ ने कहा, अमेरिका समुद्री सुरक्षा को दरकिनार कर रहा है और नए समीकरण बन रहे हैं। ईरान ने अभी पूरी क्षमता से जवाब नहीं दिया है। ज्ञात हो, होर्मुज में दो माह से फंसे मालवाहक जहाजों को निकालने के लिए अमेरिका ने सोमवार को 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' शुरू किया था, जिसका ईरान विरोध कर रहा है। इसी क्रम में दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई हुई, लेकिन फिलहाल युद्धविराम बरकरार है।

ईरान को पता है कि क्या नहीं करना है : ट्रंप

रायटर के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमता को खारिज करते हुए कहा है कि तेहरान को सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, हालांकि वह घमंड के कारण ऐसा नहीं कर रहा। ओवल आफिस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा,ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है। वह निजी तौर पर समझौता चाहता है। उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रभावी साबित हो रही है। युद्धविराम उल्लंघन पर ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान जानता है उसे क्या नहीं करना चाहिए।

विदेश से धन भेजे जाने में भारत 137 अरब डालर के साथ शीर्ष पर

- आइओएम ने मंगलवार को जारी की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026
- 100 अरब डालर का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र देश भारत

प्रतीकात्मक

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र: भारत ने वर्ष 2024 में 137 अरब डालर से अधिक राशि विदेश से (रेमिटेंस) हासिल कर दुनिया में शीर्ष स्थान बरकरार रखा और वह 100 अरब डालर का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र देश रहा। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने यह जानकारी दी है।

इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन फार माइग्रेशन (आइओएम) की तरफ से मंगलवार को जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, भारत विदेशों से लगातार सबसे अधिक रेमिटेंस पाने वाला देश बना हुआ है। वर्ष 2024 में भारत, मेक्सिको, फिलीपींस व फ्रांस वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस पाने के मामले में शीर्ष चार देशों में शामिल रहे। रिपोर्ट कहती है कि भारत को 2024 में 137.67 अरब डालर का रेमिटेंस मिला, जो अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। 2010 में भारत के लिए यह आंकड़ा 53.48 अरब डालर था, जो 2015 में 68.91, 2020 में 83.15 और 2024 में 137 अरब डालर से अधिक हो गया। क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया में 2024 के दौरान रेमिटेंस में 11.8 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि का अनुमान है। इसमें भारत, पाक और बांग्लादेश को मिले मजबूत प्रवाह की अहम भूमिका रही। रिपोर्ट के अनुसार, उच्च आय वाले देश इस रेमिटेंस के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। अमेरिका से 2024 में सर्वाधिक 100 अरब डालर से अधिक राशि दूसरे देशों को भेजी गई। सऊदी अरब से 46 अरब डालर से अधिक, स्विट्जरलैंड से 40 अरब डालर व जर्मनी से 24 अरब डालर की राशि भेजी गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों में एशियाई देशों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। वर्ष 2022 में चीन के 10 लाख से अधिक छात्र विदेश में पढ़ रहे थे, जबकि भारत विदेश में पढ़ने वाले 6.2 लाख छात्रों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय प्रवासी समुदाय को देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार में अहम भूमिका निभाने वाला बताया गया है। रिपोर्ट में 'ब्रेन ड्रेन' की चुनौती को 'ब्रेन गेन' में बदलने के लिए नीतिगत उपायों की जरूरत पर भी बल दिया गया है।

ग्लोबल स्कूल्स प्राइज 2026 की शार्टलिस्ट में दो भारतीय स्कूल शामिल

लंदन, प्रेट्र : ग्लोबल स्कूल्स प्राइज 2026 के लिए दुनिया भर से आए करीब तीन हजार नामांकन के बीच भारत के दो स्कूलों ने शीर्ष 50 में जगह बनाकर देश का परचम लहरा दिया है। दिल्ली का कथा लैब स्कूल आर्ट्स और कल्चर कैटेगरी में और दिल्ली पब्लिक स्कूल बैंगलोर नार्थ इनक्लूसिव एजुकेशन श्रेणी में शार्टलिस्ट हुए हैं। यह उपलब्धि सिर्फ दो स्कूलों की नहीं, बल्कि भारत की उस सोच की जीत है, जो शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं मानती, बल्कि जीवन से जोड़ती है।

कथा लैब स्कूल ने दिल्ली के गोविंदपुरी जैसे वंचित इलाके में सैकड़ों बच्चों को नई दिशा दी है। पद्मश्री से सम्मानित गीता धर्मराजन द्वारा स्थापित इस स्कूल ने कहानी-आधारित शिक्षण पद्धति जैसे अनोखे माडल से पढ़ाई को कहानी और अनुभव का हिस्सा बना दिया है जहां भाषा, विज्ञान, गणित और कला एक साथ बहते हैं।

वहीं डीपीएस नार्थ ने सेवा परमो धर्मः के सिद्धांत पर चलते हुए यह साबित किया है कि समावेशी शिक्षा और उत्कृष्टता एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। यूके स्थित वार्की फाउंडेशन के संस्थापक सनी वार्की ने इन स्कूलों की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान दिखाते हैं कि कैसे शिक्षा भविष्य गढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम है।

क्रूज शिप पर हंटावायरस का साया, सात मामले आए सामने

- मानव से मानव संक्रमण की आशंका, जांच तेज

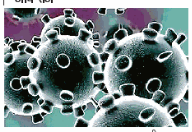

प्रतीकात्मक

एम्सटर्डम, रायटर : अटलांटिक महासागर में केप वर्डे के पास फंसे क्रूज शिप एमवी होंडियस पर हंटावायरस का खतरा गहराता जा रहा है। डब्लयूएचओ के अनुसार, जहाज पर अब तक दो मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि पांच और संदिग्ध हैं। इन सात मामलों में तीन लोगों की मौत हो चुकी है, एक मरीज गंभीर हालत में है और तीन में हल्के लक्षण देखे गए हैं। करीब 150 यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ यह जहाज कई दिनों से समुद्र में ही रुका हुआ है, क्योंकि केप वर्डे ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए इसे किनारे लगने की अनुमति नहीं दी है। जहाज पर सवार बाकी लोगों को एहतियात के तौर पर अपने-अपने केबिन में रहने को कहा गया है।

मानव से मानव संक्रमण की आशंका : डब्लयूएचओ ने साफ किया है कि हंटावायरस आमतौर पर चूहों जैसे संक्रमित कृंतकों के संपर्क से फैलता है, लेकिन कुछ मामलों में सीमित मानव-से-मानव संक्रमण की भी आशंका जताई गई है, खासकर नजदीकी और लंबे संपर्क में।

क्या है हंटावायरस, लक्षण, खतरा और बचाव : हंटावायरस एक दुर्लभ लेकिन खतरनाक बीमारी है, जो मुख्य रूप से चूहों के मल, पेशाब या लार के संपर्क से फैलती है। यह शरीर में पहुंचकर फेफड़ों या किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण फ्लू जैसे होते हैं बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और थकान। लेकिन कुछ मामलों में यह तेजी से गंभीर रूप ले लेती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत और जान का खतरा बढ़ जाता है।

चीन के पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके में 26 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल

- धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके के पेड़ तक उखड़ गए
- राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने दिए जांच के आदेश, कंपनी प्रमुख हिरासत में

चीन के हुनान प्रांत के लियुयांग में एक पटाखा बनाने वाली फैक्टरी में मंगलवार को धमाके के बाद आग बुझाते दमकलकर्मी। रायटर

बीजिंग, प्रेट्र: चीन के हुनान प्रांत में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने भारी तबाही मचा दी। इस हादसे में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 61 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाका सोमवार दोपहर हुआशेंग फायरवर्क्स कंपनी के प्लांट में हुआ, जो इस क्षेत्र में पटाखा उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। धमाके के बाद सामने आए वीडियो में कई किलोमीटर तक फैली तबाही, धुएं के ऊंचे गुबार और ढही हुई इमारतें दिखाई दीं। झटके इतने तेज थे कि आसपास के पेड़ तक उखड़ गए और पूरा इलाका बारूद की गंध से भर गया।

रोबोट, ड्रोन और 1500 से ज्यादा कर्मी तैनात : हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए 1500 से ज्यादा दमकलकर्मी, मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है। ड्रोन और तीन रोबोट की मदद से मलबे में फंसे लोगों की तलाश की गई। घायलों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने इस हादसे की गहन जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की बात कही है। वहीं, फैक्ट्री के जिम्मेदार अधिकारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच जारी है।

पेशावर में आइसिस ने की मौलाना की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

- मौलाना पर उस समय हमला हुआ जब वह कार से कहीं जा रहा था
- वजीरिस्तान में सुरक्षाबलों ने एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराया

प्रतीकात्मक

पेशावर, प्रेट्र : पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को हिंसा की दो बड़ी घटनाओं ने सुरक्षा हालात पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पहली घटना में आइसिस ने प्रमुख मौलाना मोहम्मद इदरीस की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरी घटना में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। पुलिस के अनुसार, मौलाना मोहम्मद इदरीस पर उस वक्त हमला हुआ, जब वे किसी कार्यक्रम में जा रहे थे। हमलावरों ने उनके वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनके साथ मौजूद दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए।

गंभीर रूप से घायल इदरीस ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसी बीच, प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकी को मार गिराया, जो विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर चेकपोस्ट को निशाना बनाने जा रहा था।

सुरक्षाबलों की कार्रवाई के दौरान वाहन पास की इमारत से टकराकर फट गया, जिससे सात नागरिक घायल हो गए। धमाके में पास के पेट्रोल पंप, मदरसे और कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा।

ओहियो गवर्नर पद के लिए विवेक रामास्वामी ने अभियान तेज किया

कोलंबस, एपी : रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी ओहियो के गवर्नर चुनाव में प्राइमरी चरण पार कर अब नवंबर के आम चुनाव की कड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ट्रंप के समर्थन से मजबूत हुए रामास्वामी का मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन से होगा, जो कोविड-19 के दौरान राज्य की स्वास्थ्य निदेशक के रूप में काफी चर्चित रहीं। राज्य में इस बार सभी प्रमुख पदों पर चुनाव हो रहे हैं, पर गवर्नर की रेस सबसे ज्यादा सुर्खियों में है।

रामास्वामी, जो 2024 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में भी शामिल थे, राज्य राजनीति में नए हैं, पर राष्ट्रीय पहचान और तकनीकी क्षेत्र से जुड़ाव उन्हें बढ़त दिला रहा है। वहीं, एमी एक्टन को महामारी के दौरान उनकी भूमिका के कारण लोकप्रियता मिली, हालांकि उनके फैसलों को लेकर विरोध भी हुआ। इसी के साथ ओहियो में सीनेट और हाउस की कई सीटों पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से सनसनी; सुरक्षा घेरा सख्त, मुठभेड़ में आरोपित घायल

- घटना के समय व्हाइट हाउस में ही थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
- घटनास्थल से पुलिस ने हथियार बरामद किया, जांच जारी है
- इस घटना के दौरान व्हाइट हाउस को कुछ समय के लिए 'लाकडाउन' कर दिया गया था।
- आरोपित को पकड़ने के दौरान फायरिंग में एक नाबालिग राहगीर भी हुआ घायल

व्हाइट हाउस। फाइल

वाशिंगटन, आइएएनएस : व्हाइट हाउस के पास एक सशस्त्र संदिग्ध द्वारा की गई गोलीबारी के बाद सनसनी फैल गई। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपित को गोली मार दी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के दौरान व्हाइट हाउस को कुछ समय के लिए 'लाकडाउन' कर दिया गया था। घटना के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही थे। हालांकि, उन्होंने इस घटना पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान वाशिंगटन को सुरक्षित शहर बताया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि संदिग्ध का निशाना राष्ट्रपति या कुछ समय पहले वहां से गुजरा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का काफिला था। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार बरामद कर लिया है और जांच जारी है। डिप्टी डायरेक्टर मैट क्विन के अनुसार, दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सादे कपड़ों में तैनात सीक्रेट सर्विस कर्मियों ने व्हाइट हाउस परिसर के बाहरी घेरे में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जिसके पास हथियार होने का अंदेशा था। जब वर्दीधारी अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो आरोपित ने भागते हुए अधिकारियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी गोलीबारी में आरोपित घायल हो गया। इस मुठभेड़ के दौरान एक नाबालिग राहगीर भी घायल हुआ है, जिसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि बच्चा संदिग्ध की गोली का शिकार हुआ।

शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी

लाहौर प्रेट्र: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी और उनके पति को भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग के मामले में सिर्फ एक सुनवाई में निर्दोष घोषित कर सभी आरोपों से बरी कर दिया है।

भ्रष्टाचार निरोधक संस्था ने सोमवार को अदालत को बताया कि पीएम की बेटी राबिया इमरान और उनके पति अली इमरान यूसुफ पंजाब साफ पानी कंपनी के भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग मामले में संलिप्त नहीं पाए गए हैं। उनके खिलाफ कोई सुबूत उपलब्ध नहीं है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने अरबों डालर के भ्रष्टाचार मामले में दंपती के खिलाफ जारी आजीवन गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था। इमरान खान सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022 में उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए थे। रबिया व अली इमरान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2022 में ब्रिटेन भाग गए थे, जिसके बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया था।

बलूच संगठन ने दस पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का किया दावा

- फ्रंटियर क्राप्स के चेकपोस्ट, सैन्य कैंप को बनाया निशाना :बीएलएफ
- कहा, हमले के बाद कैमरों को नष्ट कर दिया, हथियार उठा ले गए

प्रतीकात्मक

बचूचिस्तान, एएनआइ: बलूच सशस्त्र संगठन ने दावा किया है कि उसने बलूचिस्तान के खारान, वाशुक, अवारान, केच और मस्तंग में पाकिस्तान की सेना के खिलाफ दस हमले किए और दस सैन्यकर्मियों और चार सरकारी एजेंटों को मार गिराया।

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने बयान में कहा कि उनके लड़ाकों ने पाकिस्तान की फ्रंटियर कार्प्स (एफसी) के चेकपोस्ट, सैन्य कैंप, एक काफिले, सड़क निर्माण कंपनी की सुरक्षा में लगे जवानों और उन लोगों को निशाना बनाया जिन्हें उन्होंने 'डेथ स्क्वाड एजेंट' और 'सरकारी एजेंट' बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इन हमलों के दौरान हथियार भी कब्जे में लिए गए और निगरानी कैमरे नष्ट कर दिए गए।

बीएलएफ के अनुसार, तीन मई को खारान के गाजी रोड पर एफसी चेकपोस्ट को राकेट और ग्रेनेड लांचर से निशाना बनाया गया। उनका दावा है कि गोले सीधे पोस्ट के अंदर गिरे, जिससे नुकसान और हताहत हुए। प्रवक्ता ने यह आरोप भी लगाया कि हमले के बाद पाकिस्तानी बलों ने लड़ाकों का पीछा करते हुए क्वाडकाप्टर इस्तेमाल किए और आसपास के नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग की।

बल्लेबाज	रन
केएल राहुल	445
अभिषेक शर्मा	440
हेनरिक क्लासिन	425

दैनिक जागरण
आइपीएल 19
धूम धड़ाका
www.jagran.com
बुधवार 6 मई, 2026

गेंदबाज	विकेट
भुवनेश्वर कुमार	17
अंशुल कंबोज	17
कैगिसो रबादा	16

संजू ने मुश्किल की दिल्ली कैपिटल्स की डगर

चेन्नई सुपरकिंग्स आठ विकेट से विजयी

दिल्ली की प्लेआफ की उम्मीदों को लगा झटका, घर पर मिली चौथी हार

लोकेश शर्मा ● जागरण

नई दिल्ली: संजू सैमसन (87*) की शानदार अविजित अर्धशतकीय पारी के दम पर चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) ने आइपीएल मुकाबले में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हराकर उसके प्लेआफ में पहुंचने की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। अब दिल्ली को प्लेआफ में जगह बनाने के लिए अपने बाकी चारों मैच जीतने होंगे। वहीं चेन्नई के लिए इस जीत ने उसके प्लेआफ में पहुंचने की उम्मीदों को थोड़ा बल दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने 156 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे सीएसके ने दो विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर शेष रहते आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू मैदान अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली की यह लगातार चौथी हार है। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में संजू ने दिल्ली के विरुद्ध ही शतक लगाया था और मंगलवार को एक बार फिर वह दिल्ली पर मिली जीत के नायक बने।

अर्धशतकीय पारी के दौरान शाट लगाते संजू सैमसन ● प्रेट्र

लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत भी डगमगाई। 45 रन तक टीम ने दो विकेट गंवा दिए, लेकिन जिस पिच पर अन्य बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, सैमसन ने वहां धाराप्रवाह बल्लेबाजी करते हुए सात चौके और छह छक्के लगाने के अलावा तीसरे विकेट के लिए युवा कार्तिक शर्मा (41) के साथ 114 रन की अटूट साझेदारी की। मिशेल स्टार्क और लुंगी नगिदी जैसे बड़े गेंदबाजों के विरुद्ध आक्रमक अंदाज में बल्लेबाजी की। स्टार्क, नगिदी और कुलदीप यादव जैसे अनुभवी गेंदबाज छोटे लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके। विकेट लेने में विफलता ने दिल्ली की उम्मीदें खत्म कर दीं। स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव की गेंदों पर संजू ने प्रहार किया और उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया।

दिल्ली की रणनीति पर उठे सवाल: टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला गलत साबित हुआ। अरुण जेटली स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करना आसान माना जाता है, जिसे नजरअंदाज करना टीम पर भारी पड़ा। ये कुछ ऐसी पिच थी, जैसी आरसीबी के विरुद्ध मुकाबले में थी। इसके बावजूद अक्षर पटेल ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया। लगातार घरेलू हार और खराब फैसलों ने दिल्ली के प्लेआफ की डगर मुश्किल बना दी है। टीम के लिए बाकी चारों मैच करो या मरो की स्थिति वाले हो गए हैं। एक और हार उसे प्लेआफ से बाहर का रास्ता दिखा देगी।

दबाव में दिखे दिल्ली के बल्लेबाज: दिल्ली की हार की कहानी उसकी कमजोर बल्लेबाजी से शुरू हुई। पिछली बार आरसीबी के विरुद्ध 76 रन पर सिमटने के बाद इस मुकाबले में भी बल्लेबाज दबाव में दिखे। केएल राहुल और पाथुम निसांका ने सतर्क शुरुआत की, लेकिन रन गति धीमी रही। पावरप्ले में टीम केवल 37 रन ही बना सकी, जिसने आगे के बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया। दिल्ली को मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन निसांका (12) और राहुल (19) जल्द आउट हो गए। दोनों बल्लेबाज बड़े शाट के प्रयास में विकेट गंवा बैठे। नीतीश राणा (15) और करुण नायर (13) टीम को संभाल नहीं सके। 11 ओवर तक दिल्ली के पांच विकेट 69 रन पर गिर चुके थे, जिससे टीम बैकफुट पर चली गई। मुकेश चौधरी, अकील हुसैन और नूर अहमद ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। लगातार डाट गेंदों ने दबाव बढ़ाया। हालांकि, अंत के ओवरों में ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच 65 रन की साझेदारी हुई, जिससे दिल्ली 155 रन तक पहुंच सकी। यह स्कोर लड़ने लायक जरूर था, लेकिन पिच के हिसाब से पर्याप्त नहीं माना जा रहा था।

स्कोर बोर्ड

दिल्ली कैपिटल्स: 155/7 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
निसांका का. ब्रेविस बो. मुकेश	19	15	3/1
राहुल का. गायकवाड़ बो. अकील	12	13	2/0
नीतीश का. कार्तिक बो. नूर	15	13	2/0
करुण का. गुरजपनीत बो. नूर	13	13	2/0
अक्षर का. अकील बो. गुरजपनीत	2	6	0/0
स्टब्स का. मुकेश बो. ओवरटन	38	31	1/2
समीर अविजित	40	24	0/4
आशुतोष रन आउट	14	5	0/2
स्टार्क अविजित	0	0	0/0

अतिरिक्त: 2 (वा: 2)
विकेटपतन: 1-29 (निसांका 3.6), 2-36 (राहुल, 5.1), 3-52 (करुण, 7.6), 4-61 (नीतीश, 9.3), 5-69 (अक्षर, 10.6), 6-134 (स्टब्स, 18.5), 7-149 (आशुतोष, 19.5)
गेंदबाजी: अकील 4-0-19-1, मुकेश 4-0-31-1, अंशुल 4-0-49-0, नूर 3-0-22-2, गुरजपनीत 4-0-29-1, ओवरटन 1-0-5-1

चेन्नई सुपर किंग्स: 159/2 (17.3 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
संजू अविजित	87	52	7/6
गायकवाड़ का. समीर बो. नगिदी	6	13	1/0
उर्विल स्टंप राहुल बो. अक्षर	17	9	0/2
कार्तिक अविजित	41	31	4/2

अतिरिक्त: 8 (लेबा: 1, वा: 7)
विकेटपतन: 1-24 (गायकवाड़, 3.6), 2-45 (उर्विल, 6.3)
गेंदबाजी: स्टार्क 4-0-30-0, अक्षर 4-0-25-1, नगिदी 4-0-30-1, कुलदीप 3-0-34-0, नटराजन 2.3-0-39-0

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	रद	नेट रन रेट	अंक
1	पंजाब	9	6	2	1	+0.855	13
2	आरसीबी	9	6	3	0	+1.420	12
3	हैदराबाद	10	6	4	0	+0.644	12
4	राजस्थान	10	6	4	0	+0.510	12
5	गुजरात	10	6	4	0	-0.147	12
6	चेन्नई	10	5	5	0	+0.151	10
7	दिल्ली	10	4	6	0	-0.949	8
8	कोलकाता	9	3	5	1	-0.539	7
9	मुंबई	10	3	7	0	-0.649	6
10	लखनऊ	9	2	7	0	-1.076	4

थाला धौनी के नहीं खेलने से निराश दिखे फैंस

चेन्नई सुपरकिंग्स के पूर्व कप्तान थाला महेंद्र सिंह धौनी के दिल्ली न आने और उनके मैच नहीं खेलने से दिल्ली के फैंस निराश दिखे। फैंस धौनी की एक झलक पाने और उन्हें खेलते देखने के लिए मैदान पर आए थे। लेकिन वह इस बात से बेहद अंजान थे कि धौनी चेन्नई में ही रिहैब कर रहे है।

हैदराबाद के सामने पंजाब को दिखाना होगा दम

हैदराबाद, प्रेट्र : पिछले दो मैचों में बल्लेबाजों की विफलता के कारण हार का सामना करने वाली पंजाब किंग्स की टीम को अगर अपना अभियान वापस पटरी पर लाना है तो उसे बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध होने वाले आइपीएल मुकाबले में फिर से अपनी आक्रामक लय हासिल करनी होगी। लगातार छह मैच जीतने वाली पंजाब की टीम पिछले दो मैचों में लड़खड़ा गई है। इन मैचों में हार ने उसकी उन कमजोरियों को उजागर किया है जिन्हें वह जल्द से जल्द दूर करना चाहेगी। पंजाब किंग्स भले ही नौ मैचों में 13 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है लेकिन अब गलतियों की गुंजाइश काफी कम हो गई है, क्योंकि आरसीबी, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रायल्स और गुजरात टाइटंस सभी उससे केवल एक अंक पीछे हैं।

बल्लेबाजों की नाकामी के कारण पंजाब किंग्स को पिछले कुछ मैच में हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले के मैचों में उसके बल्लेबाजों ने अपने आक्रामक अंदाज का शानदार नमूना पेश किया था। बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन के कारण इन मैचों में उसकी गेंदबाजी की कमियों पर किसी का खास ध्यान नहीं गया। शुरुआती दौर में लय बनाने वाले शीर्ष क्रम के बल्लेबाज लड़खड़ा गए हैं। प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह और कूपर कोनोली की युवा तिकड़ी की आक्रामक रणनीति लापरवाही में बदल गई है। पंजाब का मध्य क्रम भी चोटी के बल्लेबाजों की विफलता के बाद अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाया जबकि पूरे टूर्नामेंट के दौरान उसकी गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं रही है।

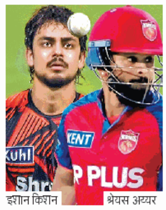
इशान किशन श्रेयस अय्यर

सनराइजर्स हैदराबाद: पैट कमिंस (कप्तान), सलिल अरोड़ा, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, रविचंद्रन अश्विन, अनिकेत वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंदु मेंडिस, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, शिवम मावी, शिवांग कुमार, अमित कुमार, गेराल्ड कोएत्जे, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, दिलशान मदुशंका, इशान मलिंगा, ओंकार तरनाले, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी।

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंह, प्रभसिमरन सिंह, मिचेल ओवेन, नेहाल वढेरा, मार्को जेनसेन, मुशीर खान, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, सूर्यांश शेड्गे, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लाकी फर्ग्युसन, हरप्रीत बराड़, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, पाइला अविनाश, विष्णु विनोद।

खेल डायरी

भारतीय कंपाउंड पुरुष टीम शीर्ष तीन में

शंघाई, प्रेट्र: पूर्व विश्व चैंपियन ओजस देवताले ने भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का नेतृत्व करते हुए मंगलवार को तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के क्वालीफाइंग राउंड में व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष 10 में जगह पक्की की। बर्लिन में 2023 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जीतकर भारत के पहले पुरुष विश्व चैंपियन बने देवताले ने इस टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग में भारतीय खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 711 अंक हासिल करके कुल मिलाकर सातवां स्थान हासिल किया। इससे भारतीय टीम को भी फायदा हुआ और वह शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल रही। वहीं साहिल जाधव ने भी 711 अंक बनाए लेकिन केंद्र पर सर्वाधिक निशाना लगाने के कारण देवताले उनसे आगे रहे। भारतीय टीम के एक अन्य खिलाड़ी कुशल दलाल ने कुल मिलाकर 18वें स्थान पर रहकर इस तिकड़ी को पूरा किया। इस तरह से भारत ने टीम स्पर्धा में तीसरा स्थान हासिल किया।

जीपीकेएल ने लागू की इओआइ प्रक्रिया

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन (एचआइपीएसए) के स्वामित्व वाली ग्लोबल प्रवासी कबड्डी लीग (जीपीकेएल) ने फ्रेंचाइजी ओनरशिप के लिए औपचारिक एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआइ) प्रक्रिया की घोषणा की है। यह कदम विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों से मिल रही मजबूत रुचि के बाद उठाया गया है। सीमित संख्या में उपलब्ध फ्रेंचाइजी स्लाट्स को देखते हुए, लीग ने सीजन-2 के लिए उपयुक्त और दीर्घकालिक साझेदारों के चयन हेतु एक संरचित मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया लागू की है। लीग का लक्ष्य कबड्डी को 75 देशों (पुरुष) और 45 देशों (महिला) तक विस्तार देना है। हिप्सा की अध्यक्ष कांथी डी. सुरेश ने कहा कि जीपीकेएल के प्रति प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि कबड्डी को लेकर धारणा में एक बड़ा बदलाव आया है। यह एक वैश्विक अवसर के रूप में उभर रहा है।

अंडर-18 हाकी टीम आस्ट्रेलिया से खेलेंगी

भोपाल, प्रेट्र: भारत की पुरुष और महिला अंडर-18 हाकी टीम एशिया कप की तैयारियों के सिलसिले में आस्ट्रेलिया के विरुद्ध 15 से 20 मई तक भोपाल में चार मैचों की सीरीज खेलेंगी। यह सीरीज इस महीने के आखिर में जापान के काकामिगाहारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप की तैयारी को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। इन दोनों टीम के लिए यहां भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के केंद्र में 19 अप्रैल से अभ्यास शिविर भी लगाया गया था। पुरुष टीम के कोच सरदार सिंह ने कहा कि इस शिविर के दौरान मुख्य ध्यान सभी विभागों में खिलाड़ियों के बुनियादी कौशल और क्षमता को मजबूत करने पर रहा है। महिला टीम की कोच रानी रामपाल ने कहा कि आस्ट्रेलिया की अंडर-18 टीम के विरुद्ध मैच खिलाड़ियों के लिए उच्च स्तर पर खेलने काs शानदार मौका होगा।

टी-20 रैंकिंग में भारतीय टीम का शीर्ष स्थान बरकरार

भारत ने मार्च में जीता था टी-20 विश्व कप, 275 अंक के साथ भारत इंग्लैंड (262) और आस्ट्रेलिया (258) से आगे

दुबई, प्रेट्र: तीन बार के विश्व कप विजेता भारत ने मंगलवार को आइसीसी टी-20 रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए टी-20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। साथ ही टीम ने रिकार्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी।

आइसीसी ने कहा कि नवीनतम रैंकिंग में मई 2025 के बाद खेले गए सभी मुकाबलों को शत प्रतिशत और उससे पिछले दो वर्षों के मुकाबलों को 50 प्रतिशत भार दिया गया है। इसमें 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज भारत की इंग्लैंड (262 अंक) पर बढ़त एक अंक कम हुई है, जबकि आस्ट्रेलिया 258 अंक के साथ तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के और करीब आ गया है। इस रैंकिंग में शीर्ष सात टीम की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड (247), दक्षिण अफ्रीका (244), पाकिस्तान (240) और वेस्टइंडीज (233) अपने-अपने स्थानों पर बरकरार हैं। हालांकि श्रीलंका (221) को छह रेटिंग अंक का नुकसान हुआ है।

रघु ने लहराया नोट, लिखा दुखदायी सफर समाप्त हुआ

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच सोमवार को हुआ आइपीएल मुकाबला उस समय सामान्य नहीं रहा, जब मुंबई के लिए अपना दूसरा ही आइपीएल मैच खेल रहे जालंधर से ताल्लुक रखने वाले लेग स्पिनर रघु शर्मा ने एलएसजी के अक्षत रघुवंशी के रूप में अपना पहला आइपीएल विकेट लेते हुए एक नोट लहराया, जिस पर लिखा था- 'राधे-राधे। 15 साल के दुखदायी सफर का आज गुरुदेव की कृपा से अंत हो गया' और इस नोट के अंत में लिखा था 'जय श्री राम'।

यह नोट बेहद आध्यात्मिक और गले में तुलसी की माला, लंबी चोटी रखने वाले रघु के संघर्ष और कभी भी हार न मानने की उस कहानी को बयां कर रहा था, जब करीब 15 वर्ष पहले 21 वर्षीय रघु के पास मैकेनिकल इंजनियरिंग की डिग्री थी और वजन 102 किग्रा था। उसके बाद भी उन्होंने वर्ष 2011 में एमएस धौनी के वनडे विश्व कप के फाइनल में विजयी छक्के से प्रेरणा लेते हुए मन में क्रिकेटर बनने की ठान ली थी। पिता ने उन्हें यह कहते हुए चेताया भी था कि तुम क्रिकेटर नहीं बन पाओगे, इतने वजन के साथ दौड़ नहीं पाओगे, लेकिन उन्होंने इसे सच कर दिखाया और इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध पदार्पण करने के बाद एलएसजी के विरुद्ध मैच से चार ओवर में 36 रन देकर एक विकेट लिया।

इससे पहले पंजाब में एनओसी की उलझन और रणजी ट्राफी के लिए यो-यो और दो किलोमीटर रन टेस्ट में मिली असफलता भी उन्हें तोड़ नहीं सकी। उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया। श्रीलंका में क्रिकेट खेला, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेला और हर जगह से अनुभव बटोरा और वह कर दिखाया जो उनका सपना था।

इंजीनियरिंग की डिग्री, 102 किग्रा वजन के साथ धौनी से प्रेरणा लेकर क्रिकेटर बने थे रघु शर्मा

विकेट लेने के बाद नोट लहराते मुंबई के गेंदबाज रघु शर्मा ● प्रेट्र

हमने राजस्थान रायल्स की बोली वापस नहीं ली : सोमानी

- **काल सोमानी की अगुआई वाले कंसोर्टियम ने कहा, फ्रेंचाइजी का स्वामित्व का हिस्सा न बनने से निराश**
- **मित्तल परिवार और अदार पूनावाला ने 15600 करोड़ रुपये में खरीदी थी 83 प्रतिशत की हिस्सेदारी**

नई दिल्ली, प्रेट्र: अमेरिका स्थित काल सोमानी की अगुआई वाले कंसोर्टियम ने भारतीय मूल के दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी एन मित्तल के नेतृत्व वाले समूह से आइपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रायल्स के स्वामित्व की बोली हारने पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि हमने कभी भी बोली वापस नहीं ली थी और हमारा समूह निश्चित रूप से सौदा पूरा करने के लिए तैयार था, लेकिन जो हुआ वह 'निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा' को नहीं दर्शाता है।

राजस्थान रायल्स ने कहा था कि लक्ष्मी मित्तल और उनके बेटे आदित्य मित्तल ने वैक्सीन निर्माता अदार पूनावाला के साथ मिलकर फ्रेंचाइजी में 1.65 बिलियन अमेरिकी डालर (लगभग 15,600 करोड़ रुपये) में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली, क्योंकि सोमानी (टेक्नोलाजी उद्यमी), राब वाल्टन (वालमार्ट समूह) और शीला फोर्ड हैम्प (फोर्ड समूह) के समूह ने अपना नाम वापस ले लिया। इस पर सोमानी की अगुआई वाले कंसोर्टियम मंगलवार को कहा, छह महीने की लंबी प्रक्रिया के दौरान हम शुरू से अंत तक प्रमुख बोलीदाता थे और ऐसे में राजस्थान रायल्स के स्वामित्व समूह का हिस्सा न बन पाने से हम बेहद निराश हैं। मीडिया में जो बातें फैलाई गई हैं उसके विपरीत हमारा समूह पूरी तरह से फंडिंग प्राप्त थी और हम टीम का स्वामित्व हासिल करने के लिए तैयार थे। हमने कभी भी अपनी बोली वापस नहीं ली थी। हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं और हमें बताया गया था कि शनिवार को फ्रेंचाइजी के बोर्ड की बैठक उसकी बोली को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। हमने इस प्रक्रिया को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पेशेवरपन और सद्भावना के उच्चतम मानकों के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से यह पर्याप्त नहीं था।

राजस्थान रायल्स की टीम ● फाइल फोटो

सोमानी के नेतृत्व वाले समूह ने 1.63 बिलियन अमेरिकी डालर की पेशकश की थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसके दस्तावेजों को लेकर कई समस्याएं थीं, जो फ्रेंचाइजी के मौजूदा मालिकों मनोज बदाले और समूह की जांच में खरी नहीं उतरी। मित्तल परिवार के पास लगभग 75 प्रतिशत, जबकि पूनावाला के पास लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा होगा। शेष लगभग सात प्रतिशत हिस्सेदारी बडाले सहित मौजूदा निवेशकों के पास रहेगी।

डोप टेस्ट के लिए मौजूद नहीं रहने पर विनेश को नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र: पहलवान विनेश फोगाट को अंतरराष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (आइटीए) ने 18 दिसंबर 2025 को प्रतियोगिता से इतर हुए डोपिंग परीक्षण के लिए मौजूद नहीं रहने के मामले में नोटिस भेजा है। पिछले 12 महीनों में यह पहली बार है जब उन्होंने रहने के स्थान संबंधी नियम का उल्लंघन किया है।

चार मई 2026 को भेजे गए पत्र में आइटीए ने विनेश को बताया कि 19 जनवरी 2026 को उनके द्वारा दी गई सफाई की समीक्षा करने के बाद छूटे हुए परीक्षण को औपचारिक रूप से रिकार्ड कर लिया गया है। इस नोटिस में पांच जनवरी 2026 को भेजे गए एक पिछले पत्र का भी जिक्र है, जिसमें परीक्षण के लिए मौजूद नहीं रहने की बात उठाई गई थी और विनेश से इस पर जवाब मांगा गया था। यह नोटिस डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाता, लेकिन यह रहने के स्थान संबंधी नियम के तहत एक चेतावनी के तौर पर दिया जाता है। नियमों के अनुसार एक साल के भीतर तीन बार परीक्षण के लिए मौजूद नहीं रहने और/या अपने रहने के स्थान की जानकारी देने में चूक होने पर इसे उल्लंघन माना जाता है।

विनेश फोगाट

एरीना सबालेंका ने दी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी

ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंटों के राजस्व में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे शीर्ष टेनिस खिलाड़ी

रोम, एपी: विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में खिलाड़ियों की कमाई के हिस्से को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यदि उन्हें राजस्व में उचित हिस्सा नहीं मिला तो खिलाड़ी बहिष्कार का रास्ता अपना सकते हैं। सबालेंका और पुरुष वर्ग के नंबर एक खिलाड़ी जानिक सिनर समेत शीर्ष-10 के कई खिलाड़ियों ने सोमवार को संयुक्त बयान जारी कर फ्रेंच ओपन की पुरस्कार राशि को लेकर गहरी निराशा जताई थी।

इटालियन ओपन के दौरान अपने 28वें जन्मदिन पर बोलते हुए सबालेंका ने कहा, हमारे बिना न तो टूर्नामेंट होगा और न ही मनोरंजन। इसलिए हमें ज्यादा प्रतिशत मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी समय हमें बहिष्कार करना पड़ सकता है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए यही एक रास्ता बचता है। खिलाड़ी सिर्फ इनामी राशि ही नहीं, बल्कि बेहतर प्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन व्यवस्था की भी मांग कर रहे हैं। ये मांगें चारों ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन को लेकर हैं। चार बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन इगा स्वियातेक ने हालांकि बहिष्कार को अत्यधिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और आयोजकों के बीच बेहतर संवाद हो, ताकि बातचीत और समाधान का रास्ता निकले।

हैरी कैन ● रायटर
ओस्मान डेंबले ● रायटर

म्यूनिख में आज फिर 'गोल वर्षा' की उम्मीद

सेमीफाइनल दूसरा लेग
बायर्न म्यूनिख vs पीएसजी
रात 12:30 बजे | स्थान: म्यूनिख
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क

म्यूनिख, एपी : यूईएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में गत चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) और बायर्न म्यूनिख के बीच बुधवार को म्यूनिख के एलियांज एरीना में हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। पहले लेग में 5-4 की रोमांचक जीत दर्ज करने के बाद पीएसजी के पास बढ़त है, लेकिन बायर्न की आक्रामक शैली इस मुकाबले को यादगार बना सकती है। दोनों टीमों के बीच अब तक 17 मुकाबले हुए हैं, जिनमें बायर्न ने नौ और पीएसजी ने आठ मैच जीते हैं। खास बात यह है कि दोनों के बीच कभी कोई मुकाबला ड्रा नहीं रहा। ऐसे में दर्शकों को एक बार फिर 'गोल वर्षा' की देखने को मिल सकती है।

दोनों टीमों के बीच पिछले सप्ताह खेला गया पहले लेग का मुकाबला टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक रहा। खिवचा क्वारात्सखेलिया और ओस्मान डेंबले ने दो-दो गोल कर पीएसजी को 5-4 से जीत दिलाई। मुकाबले में हैरी केन ने पेनाल्टी से बायर्न को बढ़त दिलाई थी, लेकिन पीएसजी ने शानदार वापसी की। पहले हाफ में ही दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया और स्कोर 3-2 तक पहुंच गया। दूसरे हाफ में पीएसजी ने बढ़त को 5-2 तक पहुंचा दिया, लेकिन बायर्न ने भी हार नहीं मानी। दायोट उपामेकानो और लुइस डियाज के गोल ने मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया।

बायर्न के कोच विसेंट कोंपानी ने साफ कर दिया है कि उनकी टीम अपनी आक्रामक रणनीति नहीं बदलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी ताकत हमारी आक्रामकता है, और हम इसे नहीं छोड़ सकते। बायर्न इस सीजन बुंडेसलीगा में 32 मैचों में 116 गोल कर चुका है, लेकिन उसकी रक्षात्मक कमजोरी भी सामने आई है, जहां पिछले छह मैचों में टीम ने 16 गोल खाए हैं। मिडफील्डर जोशुआ किमिच ने भी यही संकेत दिए कि टीम रक्षात्मक खेल नहीं अपनाएगी। उन्होंने कहा कि हमें जीतना है, चाहे स्कोर 5-4 हो, 3-2 हो या 1-0।

दूसरी ओर पीएसजी के कोच लुइस एनरिक अपनी टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियंस लीग खिताब दिलाने के करीब पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि म्यूनिख में जीत के लिए उनकी टीम को फिर से आक्रामक खेल दिखाना होगा और कम से कम तीन गोल करने पड़ सकते हैं। पीएसजी का आत्मविश्वास भी ऊंचा है, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने पहली बार चैंपियंस लीग जीती थी।

सिटी के ड्रा से आर्सेनल खिताब के करीब

लिवरपूल, एपी: जेरेमी डोकु के दूसरे हाफ के इंजरी टाइम के सातवें मिनट में किए गए गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने सोमवार रात एवर्टन के विरुद्ध 3-3 से ड्रा खेला। इस परिणाम से इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) फुटबाल टूर्नामेंट में शीर्ष पर चल रहे आर्सेनल की स्थिति मजबूत हो गई और उसकी खिताब जीतने की संभावना बढ़ गई। इस ड्रा के साथ सिटी का लगातार तीन जीत का सिलसिला भी टूट गया और वह अब आर्सेनल से पांच अंक पीछे हो गया है। अब आर्सेनल के 35 मैच में 76 और सिटी के 34 मैच में 71 अंक हैं।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

आयुर्वेद

सूखे मेवे या नट्स प्रोटीन, आयल, विटामिन और खनिजों के छोटे पैकेज की तरह होते हैं, जो शरीर की वृद्धि व सेहतमंद रहने के लिए आवश्यक हैं। जानते हैं कुछ प्रचलित सूखे मेवों और उनके प्रयोग के सही तरीकों के बारे में...

ड्राइ फ्रूट्स के प्रयोग का क्या है सही तरीका

शरीर के पोषण के लिए फलों को संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये न केवल आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, बल्कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत भी हैं। फल ताजे या सूखे रूप में प्रयोग किए जाते हैं।

बादाम : इसे फाइटो-केमिकल पावरहाउस माना जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, साथ ही इसमें फास्फोरस, जिंक और मैग्नीशियम जैसे तत्व भी होते हैं। विटामिन-ई होने से बादाम त्वचा की सेहत के लिए काफी उपयोगी है। इसे एंटी एजिंग एजेंट माना जाता है। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में बादाम को उष्ण, चिकना और भारी प्रभाव वाला बताया गया है। यह कफ और पित्त को बढ़ाता है और वात को कम करता है, बादाम का तेल भी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। कभी-कभी गुनगुने दूध के साथ आधा चम्मच बादाम तेल लेने से एंटी आक्सीडेंट्स का लाभ मिलता है। आंतों के लिए यह स्नेहक का काम करता है, जिससे पुरानी कब्ज में काफी लाभ मिलता है।

डा. आर. वात्स्यायन
आयुर्वेदाचार्य, संजीवनी आयुर्वेदशाला, लुधियाना

अखरोट : संस्कृत में इसे 'अक्षोत' और सामान्यतः अखरोट कहा जाता है। यह गर्म प्रभाव वाला सूखा मेवा है। यह अच्छा ब्रेन टानिक माना जाता है। इसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और एंटीआक्सीडेंट्स के साथ साथ ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है। गर्मी में अत्यधिक प्रयोग से त्वचा पर दाने और मुंह में छाले पड़ सकते हैं। प्रयोग करने से पहले पानी में भिगोकर रखें।

खजूर : यह मध्य एशियाई देशों में मुख्य भोजन की तरह प्रयोग होता है। प्राकृतिक शर्करा की प्रचुरता के कारण यह तात्कालिक ऊर्जा प्रदान करता है। दुर्बलता की बीमारियों और लंबे उपवास के बाद इसका प्रयोग गुणकारी होता है। खजूर हाइपर एसिडिटी, कब्ज, एनीमिया, पुरानी खांसी के उपचार में काफी सहायक है।

काजू : यह मूलतः ब्राजील के वर्षावनों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन बी की अच्छी मात्रा के साथ मोनोअनसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है। गर्म प्रभाव के कारण इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।

किशमिश : इसे 'द्राक्षा' या 'दाख' भी कहा जाता है। यह विटामिन, अमीनो एसिड और खनिजों से भरपूर होता है। इसका प्रभाव ठंडा होता है, इसे बुखार, कब्ज, हाइपर एसिडिटी और रजोनिवृत्ति सिंड्रोम के उपचार में दिया जाता है।

इन दिनों

गर्मी से बचना है तो रोजाना चार से पांच लीटर पानी पीना चाहिए। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह एक धारणा है, पूरा सच नहीं। दरअसल, आपको पानी कितना लेना चाहिए यह आपकी शरीर की स्थिति और आपकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर सादा पानी ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। दफ्तर में डेस्क पर बैठकर काम, हल्की-फुल्की सैर या घरेलू कामकाज करते हैं और संतुलित भोजन के साथ पानी लेते रहते हैं तो इससे आप गर्मी से आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, पर आप रोजाना कसरत या अधिक मेहनत वाला काम करते हैं, बाहर धूप में अधिक समय बिताते हैं तो केवल पानी से हाइपोनेट्रेमिया का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए आपको पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रोलाइट्स को आप केवल पानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। बता दें कि हमारे सामान्य भोजन में भी इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं लेकिन अधिक पसीना आने की स्थिति या अधिक समय तक धूप में रहने या किसी अन्य परिस्थिति में आने के बाद इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन जरूरी हो जाता है अन्यथा सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। आप बेहोशी या कोमा की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं।

कितना घातक है हाइपोनेट्रेमिया

हाइपोनेट्रेमिया ऐसी स्थिति है जो रक्त में सोडियम की कम मात्रा के कारण उत्पन्न होती है। सोडियम शरीर की कोशिकाओं में और उसके आसपास पाए जाने वाले पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। हाइपोनेट्रेमिया किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्या से लेकर अत्यधिक पानी पीने के कारण उत्पन्न होती है। ऐसा होने पर, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और कोशिकाएं फूलने लगती हैं। यह सूजन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है और अधिकतम रूप से आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ सकती है।

गर्मी के दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी जरूरी तो है ही, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी आवश्यक है अन्यथा हाइपोनेट्रेमिया के रूप में एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। क्या है हाइपोनेट्रेमिया? क्या है इसका समाधान, किन बातों का रहे ध्यान, बता रही हैं सीमा झा...

पानी ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट्स भी जरूरी

• फ्रीपिक

क्यों है हाइड्रेशन महत्वपूर्ण

शरीर में पर्याप्त पानी होने से ऊर्जा, एकाग्रता और संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर बनी रहती है। काम करने, चलने या छोटे-मोटे काम करने जैसे रोजमर्रा के कार्यों के दौरान अक्सर पानी पीना ही पर्याप्त होता है, अलग से इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन अधिक शारीरिक श्रम करने के दौरान, जिसमें पसीना आए तो शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट रखने के लिए सिर्फ पानी से ज्यादा की जरूरत पड़ सकती है। यहीं पर इलेक्ट्रोलाइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

क्या हैं इलेक्ट्रोलाइट्स

इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे खनिज हैं जो शरीर में तरल संतुलन, मांसपेशियों के संकुचन और तंत्रिका क्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शामिल होते हैं। यदि आप इनका सेवन करते रहें तो इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और शारीरिक सक्रियता को बनाए रखने में उससे मदद मिलती है।

कब नहीं लें इलेक्ट्रोलाइट्स

जब शरीर से तरल पदार्थ की हानि न्यूनतम होती है यानी जब आप सोडियम या पोटेशियम की महत्वपूर्ण मात्रा नहीं खो रहे हैं। इस तरह की स्थिति में आपके शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय पदार्थों की अलग से आवश्यकता नहीं होती है।

कब लेना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स

लंबे समय तक पसीना आने पर, चाहे गर्मी, व्यायाम या बीमारी के कारण हो, शरीर से काफी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त पेय पदार्थ उपयोगी साबित होते हैं।

- गर्म, उमस भरे दिन जिनमें बाहरी गतिविधियां शामिल हों।
- एक घंटे से अधिक समय तक कसरत कर रहे हों।
- कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें बहुत अधिक और बार-बार पसीना आता हो।
- बार बार उल्टी या दस्त होने की स्थिति में।

हाइपोनेट्रिमिया के क्या हैं लक्षण

साइकोजेनिक पालीडिप्सिया तो नहीं

डा. सुशीला कटारिया
डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, मेदांता, गुरुग्राम

प्यास न भी लगे तो खूब पानी पीना चाहिए या अधिक पानी से कोई नुकसान नहीं होता। यदि ऐसा सोचते हैं तो इसे आज ही बदल दें। हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जो ऐसा ही सोचते हैं। उनमें से कई तो एक दिन में दस लीटर तक पानी पी लेते हैं। बता दें कि दिन भर अधिक पानी पीने की इच्छा एक मानसिक बीमारी है जिसे साइकोजेनिक पालीडिप्सिया कहा जाता है। ऐसे मरीजों में अक्सर नमक की मात्रा कम होती है। वे हमारे पास अक्सर बेहोशी की स्थिति में आते हैं। वास्तव में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दो से तीन लीटर पानी पीना काफी है। इसमें दूध, चाय, छाछ, लस्सी सब शामिल है। वहीं यदि कैल्शियम में सीरम कम है और हृदय की समस्या है, किडनी स्टोन है और आप अधिक पानी लेते हैं तो उन्हें अधिक नुकसान हो सकता है। सांस की समस्या और हाथ-पैरों में सूजन हो सकती है जो कई बार अधिक घातक भी हो सकती है। ऐसे में इन मरीजों को पानी के संबंध में भी अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए।

इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त कुछ आहार

केला, नारंगी, आलूबुखारा, चेरी, तरबूज, स्ट्राबेरी, आम, एवाकाडो, अनानास, नींबू पानी, नारियल पानी, पालक, शकरकंद, दही, भूने सुखे हुए मेवे, लस्सी-छाछ आदि।

इलेक्ट्रोलाइट्स पेय कैसे काम करते हैं

इलेक्ट्रोलाइट्स पेय पदार्थों में घुले खनिज पदार्थ, मुख्य रूप से सोडियम और पोटेशियम होते हैं। ये प्रभावी ढंग से तरल पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। आप तेजी से हाइड्रेट होते हैं और तनाव की स्थिति में भी लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी नहीं होती।

लेख विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

मानसिक स्वास्थ्य

स्क्रीन न बढ़ा दे आटिज्म का जोखिम

बच्चा रो रहा है या खाना खाने में आनाकानी कर रहा है तो उसे मोबाइल थमा देना आसान उपाय बनता जा रहा है। एम्स, दिल्ली के ताजा अध्ययन के अनुसार, इससे आंखों की परेशानी ही नहीं आटिज्म विकार का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में किन बातों का रहे ध्यान? आइए जानें...

डा. शेफाली गुलाटी
प्रभारी, बाल तंत्रिका विज्ञान विभाग, एम्स, नई दिल्ली

बच्चों के लिए सबसे जरूरी जुड़ाव, प्यार, और बातचीत की जगह स्क्रीन लेती जा रही है। उनके जीवन से कहानियां, खेलना, छूकर किसी चीज को देखना, उन अनुभवों से सीखना कम होता जा रहा है। स्क्रीन टाइम का बढ़ते जाना उनमें आटिज्म के लक्षण उभरने का एक कारण हो सकता है। हालांकि यह जानना महत्वपूर्ण है कि आटिज्म का कोई एक कारण नहीं होता। यह एक जटिल चीज है जिसमें आनुवंशिक, पर्यावरणीय और जीवनशैली संबंधी कारक भी शामिल हैं, लेकिन जिस तरह आटिज्म के मामले बढ़ रहे हैं, वहां एम्स में इस बाबत हुए अध्ययन सचेत करते हैं। इससे पता चलता है कि कम उम्र में अधिक स्क्रीन टाइम बिताने वाले बच्चों में आटिज्म से संबंधित लक्षण दिखने की आशंका अधिक हो सकती है।

क्या है आटिज्म स्पेक्ट्रम विकार

आटिज्म स्पेक्ट्रम विकार एक तंत्रिका विकास संबंधी स्थिति है जो बच्चे के सामाजिक मेलजोल और बातचीत को प्रभावित करती है। ऐसे में यदि जन्म के पहले वर्ष में बच्चे के साथ मानवीय स्पर्श और संवाद के बजाय मशीनी संवाद यानी मोबाइल के साथ जुड़ाव हो जाए तो उनके व्यवहार पैटर्न में बदलाव होने की संभावना प्रबल हो सकती है। एम्स में हुआ यह हालिया अध्ययन इस बात को पुष्ट करता है कि शुरुआती वर्षों में बच्चों को स्क्रीन से कहीं अधिक मानवीय जुड़ाव की आवश्यकता होती है।

आटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के शिकार बच्चे खिलौने से सामान्य तरीके से नहीं खेलते बल्कि वे उनके कुछ हिस्सों पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यहां 'स्पेक्ट्रम' शब्द पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हर बच्चा अलग है। उनमें एक जैसे लक्षण नहीं होते और गंभीरता भी भिन्न होती है।

पहले हजार दिन महत्वपूर्ण

एम्स के अध्ययन के अनुसार, छोटे बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित होता है। इस समय स्क्रीन टाइम से जुड़ाव उन्हें गंभीरता से प्रभावित कर सकता है। हालांकि स्क्रीन टाइम आटिज्म का कोई एक कारण नहीं है, पर इस विकार एक अहम कारक जरूर बन सकता है। बच्चों को शुरू से ही स्वाभाविक परिवेश से दूर कर दिया जाता है, वे सहज ही स्क्रीन की दुनिया से जोड़ दिए जा रहे हैं। यह उनके मस्तिष्क के विकास में बड़ी बाधा बन रहा है। दरअसल, बच्चे जीवन के पहले कुछ वर्ष, विशेषकर पहले 1,000 दिन में उनका मस्तिष्क कोई चीज आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसी उम्र में उनमें कुछ लक्षण उभर सकते हैं। इस समय आटिज्म के लक्षण भी पहचाने जा सकते हैं। यदि समय रहते आटिज्म की पहचान हो जाए तो उसका समाधान भी जल्द शुरू हो सकता है। अध्ययन के अनुसार, 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना अच्छा रहता है।

बातचीत : सीमा झा

इन संकेतों पर गौर करें

तीन वर्ष की आयु के बाद, मस्तिष्क में पैटर्न अधिक स्थिर हो जाते हैं, जिससे परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चे के कुछ शुरुआती संकेत पर ध्यान देना चाहिए। आंखों से संपर्क न करना, नाम पुकारने में प्रतिक्रिया न देना, बोलने में देरी हो या जो कौशल सीखा है उन्हें भूल जाना आदि। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आटिज्म को पहचानने में सहायक हो सकते हैं।

आज का भविष्यफल : 06 मई, 2026 बुधवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का राशिफल।

आज का राहुकाल : दोपहर 12 बजे से 01 बजकर 30 मिनट तक।

आज का दिशाशूल : उत्तर

कल 07 मई, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल : दक्षिण

विशेष : रवींद्रनाथ टैगोर जयंती

विक्रम संवत 2083 शके 1948 उत्तरायण, उत्तरगोल, वसंत ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष पंचमी 10 घंटे 15 मिनट तक, तत्पश्चात षष्टी पूर्वाआषाढ़ नक्षत्र 18 घंटे 46 मिनट तक, तत्पश्चात उत्तराआषाढ़ा नक्षत्र साध्य योग 26 घंटे तक, तत्पश्चात शुभ योग धनु में चंद्रमा 25 घंटे 27 मिनट तक तत्पश्चात मकर में।

मेष : मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।

वृष : अपनों से तनाव मिल सकता है। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी होगी।

मिथुन : संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। सहयोग प्राप्त होगा। जीवन सुखमय होगा।

कर्क : आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। शासन का सहयोग मिलेगा।

सिंह : अधीनस्थ या पड़ोसी से सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

कन्या : जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। तनाव मिल सकता है। आर्थिक जोखिम न उठाएं।

तुला : परेशानी दूर होगी। पारिवारिक या व्यावसायिक सफलता मिलेगी। संतान के कारण तनाव मिलेगा।

वृश्चिक : मौसम के रोग के प्रति सचेत रहें। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी।

धनु : आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।

मकर : पिता या संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

कुंभ : चली आ रही परेशानी दूर होगी। जीविका में प्रगति होगी। शासनसत्ता का सहयोग रहेगा।

मीन : संतान या शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे। संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी।

वर्ग पहेली - 3326

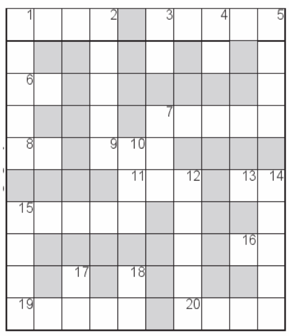

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं :
1. फंसना (4)।
3. एक भारतीय फिल्म निर्देशक (5)। 6. शरीर, तन (2)।
7. बदलाव, हेर-फेर, घुमाव (5)।
8. धूल का अत्यंत छोटा टुकड़ा (2)।
9. श्रेष्ठ पुरुष, अगुआ, एक फिल्म का नाम (3)।
11. स्वीकार कराना, राजी करना (3)। 13. सर्वदा, प्रतिदिन (2)।
15. जनेऊ संस्कार (5)।
16. पार्थिव शरीर (2)।
19. रचनाओं का समूह (5)।
20. प्रसिद्धि प्राप्त, ख्यातिलब्ध (4)।

ऊपर से नीचे :
1. सिखलाने वाला (5)।
2. प्रसिद्धि प्राप्त करना (2,3)।
3. प्यारा (2)।
4. स्थिति, अवस्था (2)।
5. नमक-सा स्वाद (4)।
7. सिद्ध होना, सीझना, कच्चा न रहना (3)।
10. रोकना, बंद करना (3)।
12. इज्जत जाना, मान-सम्मान खोना (2,3)। 14. तमाशा देखने वाला (5)।
15. भलाई, किसी का अच्छा करना (4)।
17. पेड़ के दो भाग होते हैं- जड़ और ... (2)। 18. अपशब्द (2)।

कल का हल

म[1]	■	■	स[2]	त	त[3]	■	स[4]	हा	रा
ह	■	■	ह	■	पो	■	र	■	■
ज[5]	ल	ध[6]	र	■	भू[7]	मि	का	■	■
■	■	व	■	भू[8]	मि	■	र[9]	खा	ना[10]
अ[11]	दा	ल	त[12]	■	■	र[13]	■	■	स
द्वे	■	■	म	■	■	वि[14]	दे[15]	च	ना
ष[16]	डं	गी[17]	■	र[18]	मा	■	द	■	■
■	■	ला[19]	ल	सा	■	च[20]	ना	खा	र[21]
■	■	प	■	त	■	य	■	■	ह
स[22]	ह	न	■	ल[23]	ग	न	■	■	स्य

सुडोकू - 3326

		1	2			9		
	5			6			8	7
9				1		2		
	1		6				3	
	8			4		6		
3		2		8			9	4
5						4		8
	9			7				2
	2	7		3		5	1	

कल का हल

4	5	1	8	6	2	7	3	9
6	3	8	9	7	5	1	4	2
7	2	9	3	4	1	8	6	5
3	6	7	2	8	4	9	5	1
5	8	4	7	1	9	6	2	3
1	9	2	6	5	3	4	8	7
9	4	5	1	3	6	2	7	8
2	7	6	5	9	8	3	1	4
8	1	3	4	2	7	5	9	6

राष्ट्रीय फलक

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर गलियारा के लिए सेवायत देंगे अपनी भूमि

जागरण संवाददाता, वृंदावन

ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर गलियारा के लिए अब तक किसी सेवायत परिवार ने अपनी भूमि की रजिस्ट्री नहीं की है। ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के सदस्य और मंदिर सेवायत विजय कृष्ण गोस्वामी इसकी पहल करेंगे। वह हरगुलाल बेरीवाला की हवेली के पास स्थित अपना आवास गलियारा के लिए देकर दूसरे सेवायतों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। मंदिर गलियारा के लिए 19,182 वर्ग मीटर भूमि की जरूरत है। अब तक हुई 13 रजिस्ट्री से केवल 1186 वर्ग मीटर भूमि खरीदी गई है।

मंदिर के लिए प्रस्तावित गलियारे का सेवायत शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। इसके लिए वह न्यायालय में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मंदिर उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने बताया कि समिति में शामिल सभी सेवायत सदस्य मंदिर गलियारा के समर्थन में हैं। सेवायत सदस्य विजयकृष्ण गोस्वामी उच्चाधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति सदस्य के साथ गलियारा क्षेत्र के लोगों से संपर्क स्थापित कर भूमि ट्रस्ट के नाम सौंपने के लिए गठित उप समिति के सदस्य भी हैं। यही कारण है कि वे अपना भवन ट्रस्ट को सौंपकर गलियारा क्षेत्र में आ रहे लोगों को संदेश देना चाहते हैं।

▶ **गलियारा के लिए हुई 13 रजिस्ट्री करने वालों में कोई सेवायत नहीं**

वृंदावन : ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में मंगलवार को फूलबंगला में विराजित ठाकुरजी के दर्शन करते श्रद्धालु। जागरण

कैंची व जागेश्वर धाम के दर्शन से पूरी होगी आदि कैलास और मानसरोवर यात्रा

जागरण संवाददाता, नैनीताल

▶ **8 से हल्द्वानी, 9 से टनकपुर व धारचूला से शुरू होगी आदि कैलास यात्रा**

उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल विकास निगम (केएमवीएन) संचालित आदि कैलास-ओम पर्वत यात्रा आठ मई से शुरू हो रही है। यह यात्रा हल्द्वानी, धारचूला (पिथौरागढ़) व टनकपुर (चंपावत) से संचालित की जाएगी। पहला दल हल्द्वानी से आठ मई और धारचूला व टनकपुर से नौ मई को रवाना होगा। दूसरी ओर, कैलास मानसरोवर यात्रा की तैयारियां भी जोरों पर हैं। यह यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। आदि कैलास व कैलास मानसरोवर यात्रा कैंची धाम, चितई गोलज्यू मंदिर, जागेश्वर धाम व पाताल भुवनेश्वर आदि के दर्शन के साथ पूर्ण होगी।

समुद्र तल से 14500 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलास में शिव मंदिर के कपाट एक मई को खुल चुके हैं। इसके साथ ही निजी स्तर पर व टूर आपरेटर एजेंसियों के माध्यम से लोग आदि कैलास व ओम पर्वत के दर्शन भी कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन पांच मई तक 2200 लोगों को यात्रा पास जारी कर चुका है।

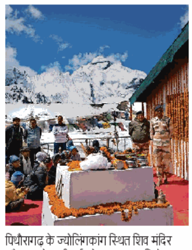

पिथौरागढ़ के ज्योलिंगकांग स्थित शिव मंदिर और सामने ताजी बर्फ से लकदक आदि कैलास पर्वत। जागरण आकाईव

केएमवीएन संचालित आदि कैलास व कैलास मानसरोवर यात्रा में कैंची धाम, चितई गोलज्यू मंदिर, जागेश्वर धाम, पाताल भुवनेश्वर जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामिल हैं। यात्रा में जागेश्वर, पिथौरागढ़, धारचूला, गुंजी, बूंदी, नाभीढांग, ज्योलिंगकांग, चौकोड़ी, अल्मोड़ा, काठगोदाम, लोहाघाट पड़ाव हैं। निगम के व्यवसाय विकास प्रबंधक दीपक पांडे के अनुसार हल्द्वानी से प्रति यात्री शुल्क 45 हजार, धारचूला से 36 हजार और टनकपुर से 42 हजार रुपये के अलावा पांच प्रतिशत जीएसटी निर्धारित है। कैलास मानसरोवर यात्रा दूसरी बार टनकपुर (चंपावत) से आयोजित की जा रही है। पहला दल चार जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा। मानसरोवर यात्रा के दस दलों में इस बार 500 यात्री जाएंगे। 22 दिवसीय यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी।

चारधाम यात्रा मार्ग पर कदम-कदम पर परीक्षा ले रहा मौसम

जागरण टीम, गढ़वाल

बर्फबारी के बीच भले ही चारधाम यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें कदम-कदम पर चुनौतियां भी है। प्रतिकूल मौसम यात्रियों की परीक्षा ले रहा है। केदारनाथ धाम में एक सप्ताह से जारी वर्षा व हालिया बर्फबारी ने यात्रा को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिसलने से 12 से अधिक यात्री घायल हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम से लौट रही बस हनुमान चट्टी के पास पहाड़ी से गिरे मलब की चपेट में आ गई।

केदारनाथ धाम में लगभग छह इंच तक बर्फ जमी है। जगह-जगह कीचड़ हो गया है। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ घोड़े-खच्चरों से यात्रा करने वाले यात्री भी जोखिम में हैं। प्रतिदिन सात से आठ हजार श्रद्धालु घोड़े-खच्चरों से धाम पहुंचते हैं, ऐसे में खराब मौसम ने यात्रा संचालन को प्रभावित कर दिया है। पैदल मार्ग पर तैनात पुलिस और आपदा राहत टीमें घायल यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार देकर अस्पतालों तक पहुंचा रही हैं।

उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर मलबे व पत्थर की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त यात्री बस। स्रोत आपदा प्रबंधन विभाग

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार, 6 मई, 2026
आजकल
14
www.jagran.com

पहली बार अमेरिका में की गई सफल ओपन-हार्ट सर्जरी

1953 में आज ही अमेरिका में डा. जान हेयशम गिब्बन ने अपनी माडल 2 हृदय-फेफड़े की मशीन का उपयोग करके रोगी सेसिलिया बावोलेक पर पहली सफल ओपन-हार्ट सर्जरी की थी। इसके उन्नत संस्करणों की मदद से आज सर्जन बाईपास सर्जरी और हृदय प्रत्यारोपण करते हैं।

लंदन में दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट जारी किया गया

1840 में आज ही के दिन लंदन में दुनिया का पहला चिपकने वाला डाक टिकट पेनी ब्लैक जारी किया गया था। सर रोलैंड हिल द्वारा विकसित इस टिकट पर महारानी विक्टोरिया का चित्र अंकित था। इसने डाक प्रणाली में क्रांति ला दी और पत्रों को भेजना बहुत किफायती बना दिया।

दुनिया के बेहतरीन राइफल निशानेबाजों में गिने जाते हैं गगन नारंग

निशानेबाज गगन नारंग का जन्म 1983 में आज ही चेन्नई में हुआ था। दो साल की उम्र में मरीना बीच पर खिलौना बंदूक से गुब्बारे फोड़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 2006 में आइएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सोना जीता। उसी वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में चार स्वर्ण पदक हासिल किए। 2010 में नई दिल्ली में आयोजित खेलों में भी यही उपलब्धि दोहराई। 2006 के एशियाई खेलों में व्यक्तिगत कांस्य पदक व दो टीम पदक (कांस्य) जीते। 2012 के लंदन ओलिंपिक 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य जीता। 2005 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए।

दुनिया ने देखी राजा रवि वर्मा की कला से लेकर ईशा की शाही चमक

मेट गाला ▶ न्यूयार्क में आयोजित कार्यक्रम में भारत की रचनात्मक शक्ति के मुरीद हुए लोग, भारतीय हस्तशिल्प और विरासत ने बिखेरा जलवा

ईशा अंबानी के ब्लाउज को तैयार करने में 500 घंटे और 40 कारीगर लगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : न्यूयार्क में आयोजित प्रतिष्ठित मेट गाला 2026 इस बार भारतीय कला, शिल्प और परंपरा का भव्य मंच बन गया। थीम फैशन इज आर्ट के बीच भारतीय हस्तकला और विरासत ने ऐसा जलवा बिखेरा कि पूरी दुनिया भारत की रचनात्मक शक्ति की मुरीद हो गई।

यहां हर धागा, हर कढ़ाई और हर डिजाइन भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा की कहानी कहता नजर आया। सबसे ज्यादा चर्चा रही ईशा अंबानी की रही जिनका परिधान भारतीय शिल्प का जीवंत उदाहरण बना। उनके ब्लाउज को तैयार करने में 500 घंटे और 40 कारीगर लगे, जिसमें एक हजार से ज्यादा हीरे और बहुमूल्य रत्न जड़े थे। यह केवल फैशन नहीं, बल्कि विरासत का प्रदर्शन था।

करण जौहर ने मेट गाला में डेब्यू किया : करण जौहर ने मेट गाला में डेब्यू करते हुए मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किया गया फ्रेम्ड इन इटर्निटी आउटफिट पहना, जो राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध पेंटिंग्स से प्रेरित था। इस पोशाक को बनाने में 5,600 घंटे और 50 से ज्यादा कारीगरों की मेहनत लगी। यह फैशन नहीं बल्कि एक चलती-फिरती कला गैलरी थी।

सुधा रेड्डी ने 1.5 करोड़ डालर का ऐतिहासिक नेकलेस पहनकर शाही ठाठ दिखाया, जबकि अनन्या बिड़ला ने सुबोध गुप्ता द्वारा बनाया गया स्टील मास्क पहनकर आधुनिक कला का अलग ही आयाम पेश किया।

इंटरनेट मीडिया पर मेट गाला का मसालेदार तड़का : मेट गाला के ग्लैमर के साथ-साथ इंटरनेट मीडिया पर इसका मजाकिया रूप भी खूब वायरल हुआ। कई विदेशी सितारों के लुक्स की तुलना बालीवुड किरदारों से की गई। विजय वर्मा ने इंटरनेट मीडिया पर अपने मटका किंग किरदार को मेट गाला में पहुंचा दिया तो वहीं, वीर दास ने एआइ से बना फेक लुक शेयर कर मजेदार अंदाज में एंट्री ले ली। इसे लेकर यूजर्स ने अलग-अलग प्रतिक्रिया दी।

न्यूयार्क स्थित मेट्रोपालिटन म्यूजियम आफ आर्ट में सोमवार को मेट गाला 2026 में (बाएं से दाएं) ईशा अंबानी, अनन्या बिड़ला, करण जौहर और सुधा रेड्डी ने अपने अनोखे परिधानों से सभी का ध्यानाकर्षण किया। एएफपी/एपी

भारतीय कला को वैश्विक मंच पर स्थापित किया

नताशा पूनावाला का आर्किड-प्रेरित गाउन और दीया मेहता जटिया का बंगाल की शोला क्राफ्ट से सजा आउटफिट भारतीय शिल्प की विविधता को दर्शाता नजर आया। वहीं जयपुर के शाही परिवार से जुड़ी गौरवी कुमारी और सवाई पद्मनाभ सिंह ने पारंपरिक शाही अंदाज में सबका ध्यान खींचा। इन सभी परिधानों में कढ़ाई की पारंपरिक विधाएं जरी, जर्दोजी, कढ़ाई, कलमकारी और अजंता की गुफाओं से प्रेरित डिजाइन शामिल थे, जिसने भारतीय कला को वैश्विक मंच पर स्थापित किया।

गर्मी में लोगों को आता है छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा

नई दिल्ली, नेशनल डेस्क : गर्मी का आगाज होते ही न केवल धरती तपने लगती है, बल्कि लोगों का स्वभाव भी चिड़चिड़ा होने लगता है।

फरीदाबाद के अमृता हास्पिटल साइकायट्री डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डा. मीनाक्षी जैन का कहना है कि बढ़ता तापमान केवल शरीर को ही नहीं थकाता, बल्कि यह मानसिक स्वास्थ्य व भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित करता है। जब बाहर का तापमान बढ़ता है, तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है और पसीना निकलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। जब शरीर इसके कारण थकावट महसूस करता है, तो इसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। इसलिए तनाव बढ़ने की वजह से गर्मी में छोटी-छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है।

इधर-उधर

रोबोट बना पैसेंजर तो एक घंटा लेट हुई फ्लाइट

खिड़की वाली सीट पर बैठकर रोबोट ने की यात्रा ● इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, एजेंसी: कैलिफोर्निया के ओकलैंड से सैन डिएगो जाने वाली साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट एक असामान्य यात्री, ह्यूमनाइड रोबोट से एक घंटे से अधिक देरी से रवाना हुई। एलीट इवेंट रोबोटिक्स के एली बेन अब्राहम और उनका चार फीट लंबा, 31 किग्रा वजनी रोबोट बेबाप ओकलैंड सैन फ्रांसिस्को बे एयरपोर्ट से विमान में सवार हुए। बेन ने बेबाप के लिए टिकट खरीदा था, लेकिन प्रारंभिक देरी रोबोट के गलियारे वाली सीट पर बैठे होने के कारण हुई।

टीबी मरीजों को पोषण सहायता देकर टाली जा सकती हैं 1,20,000 मौतें

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत में टीबी (तपेदिक) के मरीजों के लिए पोषण सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अध्ययन के अनुसार, भारत में 28 लाख तपेदिक (टीबी) के मरीजों को खाद्य बास्केट प्रदान करने से हर साल 1,20,000 से अधिक मौतें टाली जा सकती हैं। अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय के चिकित्सा विद्यालय में सहायक प्रोफेसर और बोस्टन मेडिकल सेंटर में संक्रामक रोग विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखक प्रणय सिन्हा ने कहा कि कई बायोमेडिकल हस्तक्षेपों की लागत से कम में हम हर साल 1,00,000 से अधिक टीबी मौतों को रोक सकते हैं।

टीबी से पीड़ितों के लिए प्रभावी तरीका : शोधकर्ताओं ने भारत के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के सहयोग से पाया कि अध्ययन के 94 प्रतिशत सिमुलेशन में टीबी पीड़ितों के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए भोजन सहायता एक लागत प्रभावी तरीका है। ये निष्कर्ष ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (बीएमजे) ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित हुए हैं।

- ▶ अध्ययन के 94 प्रतिशत सिमुलेशन में टीबी से पीड़ितों के स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए भोजन सहायता एक लागत प्रभावी तरीका
- ▶ कुपोषण टीबी के लिए बड़ा परिवर्तनीय कारक हो सकता है, जो प्रतिरक्षा दबाव और मृत्यु में योगदान करता है

शोधकर्ताओं ने कहा कि कुपोषण टीबी के लिए सबसे बड़ा परिवर्तनीय जोखिम कारक हो सकता है, जो प्रतिरक्षा दबाव, उपचार में विफलता और मृत्यु में योगदान करता है। एनटीईपी की पूर्व उप महानिदेशक उर्वशी सिंह ने कहा कि कुपोषण केवल टीबी की एक जटिलता नहीं है, यह इसके मूल कारणों में से एक है। जब तक हम टीबी के लिए प्रभावी टीकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाद्य सहायता वह टीका है जो हमारे पास पहले से है, और टीबी से प्रभावित परिवारों को खाद्य बास्केट प्रदान करना टीबी उन्मूलन के लिए सबसे प्रभावशाली कदमों में से एक हो सकता है।

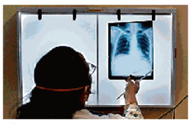

प्रतीकात्मक

बैक्टीरियल संक्रामक रोग का उन्मूलन : 2020 में संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) का नाम बदलकर एनटीईपी रखा गया, जिसका उद्देश्य भारत में बैक्टीरियल संक्रामक रोग का उन्मूलन करना है। अध्ययन ने मानक देखभाल की तुलना एक घरेलू स्तर पर पोषण संबंधी खाद्य बास्केट हस्तक्षेप से की। शोधकर्ताओं ने पहले से प्रकाशित अध्ययनों, जिसमें प्रणालीगत समीक्षाएं भी शामिल हैं पर भी ध्यान दिया। लेखकों ने कहा कि पोषण सहायता के माध्यम से प्रति 10,000 टीबी मरीजों (पीडब्लूटीबी) के लिए 10,470 डीएएलवाइएस (खराब स्वास्थ्य के वर्ष) टालने का अनुमान लगाया गया। जब इसे भारत के 28 लाख वार्षिक टीबी मामलों पर लागू किया गया, तो यह पूरे देश में लगभग 1,20,120 टीबी मौतों को टालने के बराबर है।

लगभग 141 अमेरिकी डालर लगात का अनुमान : स्वास्थ्य लाभ की प्रत्येक इकाई की लागत लगभग 141 अमेरिकी डालर होने का अनुमान है, जो शोधकर्ताओं के अनुसार भारत के मानक 550 अमेरिकी डालर से काफी कम है और यह सुझाव देता है कि यह हस्तक्षेप एक अच्छा निवेश हो सकता है। सिन्हा ने कहा कि इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में इन-काइंड (वस्तु-रूप में) पोषण सहायता का विस्तार करना केवल सही काम नहीं है, यह एक उत्कृष्ट निवेश भी है। बोस्टन विश्वविद्यालय में बायोस्टैटिस्टिक्स की डाक्टोरल उम्मीदवार जूलिया गैलिनी ने कहा, यह कार्य क्लिनिकल साक्ष्य और नीति के बीच की खाई को पाटता है।

शारीरिक गतिविधि है दिमाग को चुस्त रखने का नेचुरल पंप

अनुसंधान

क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ चलना-फिरना भी आपके दिमाग को चुस्त-दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है? अमेरिका की पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों के एक नए अनुसंधान ने यही चौंकाने वाली बात सामने रखी है।

यह शोध प्रतिष्ठित जर्नल नेचर न्यूरोसाइंस में प्रकाशित हुआ है। शोध के अनुसार, जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं चाहे वह खड़े होना हो, कदम बढ़ाना हो या शरीर को थोड़ा कसना तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। यह प्रक्रिया शरीर में एक पंप की तरह काम करती है, जो खून को स्पाइनल कार्ड की ओर धकेलती है और हल्का दबाव बनाती है। इस दबाव से दिमाग में सूक्ष्म हलचल होती है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रवाह को बढ़ाती है। यह फ्लूइड दिमाग के लिए महत्वपूर्ण है। यह पोषण पहुंचाता है, झटकों से बचाता है और सबसे अहम, दिमाग में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। यह पूरी प्रक्रिया ग्लिम्फैटिक सिस्टम का हिस्सा है, जो दिमाग की सफाई व्यवस्था माना जाता है। शोध में चूहों पर प्रयोगों से पता चला कि जैसे ही पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, दिमाग हिलता है और फ्लूइड का प्रवाह तेज हो जाता है। विज्ञानियों ने इसे गंदे स्पंज को निचोड़कर साफ करने जैसा बताया। जैसे स्पंज को दबाने से जमा गंदगी बाहर निकलती है, वैसे ही दिमाग की हलचल सफाई में मदद करती है। (प्रेट्र)

स्क्रीन शाट

प्रियंका चाहर चौधरी ने कहा, कभी-कभी हो जाता है

नागिन 7 में शीर्षक भूमिका में हैं प्रियंका। @priyankachaharchoudhary

कंटेंट में विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) ज्यादा हों, तो एडिटिंग पर खासा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो गलती हो सकती हैं। ऐसी ही गलती हुई है नागिन 7 के हालिया एपिसोड में, जहां शो वीएफएक्स की गलती को लेकर ट्रोल हो गया। दरअसल, एपिसोड के एक सीन में गलती से वीएफएक्स इफेक्ट्स की जगह ब्लू स्क्रीन दिखाई दे गई।

जिसके बाद शो में शीर्षक भूमिका निभाने वाली प्रियंका चाहर चौधरी ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए, इसे मानवीय त्रुटि बताई। एक पैपराजी वीडियो में प्रियंका से जब इस गलती पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमने भी देखा, यह ह्यूमन एरर (मानवीय त्रुटि) है।अब क्या ही कह सकते हैं? इस चीज पर काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी गलती न हो। मानवीय त्रुटि है, हो जाता है कभी-कभी। वीएफएक्स में हुई इस गलती का वीडियो खासा वायरल भी रहा है। इस सीक्वेंस में वीएफएक्स के जरिए जंगल का बैकग्राउंड दिखाया जाना था, वहां एडिटेड विजुअल्स की जगह ब्लू स्क्रीन नजर आ गया, जो आमतौर पर शूटिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। जंगल के वीएफएक्स की जगह एडिटर इफेक्ट्स जोड़ना ही भूल गया। इस क्लिप के वायरल होने के बाद शो की गिरती गुणवत्ता को लेकर आलोचना शुरू हो गई। उल्लेखनीय है कि नागिन का सातवां सीजन सात जून को खत्म हो जाएगा।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले, किरदार से निकलने को कई तरीके हैं

कई कलाकार अपनी भूमिकाओं को निभाने के लिए अपनी कुछ अच्छी बुरी यादों का सहारा लेते हैं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी ने अपने करियर में विविध किरदार निभाएं हैं। कुछ किरदार काफी गंभीर भी रहे हैं। ऐसे में पात्र निभाने को लेकर अपनी यादों को इस्तेमाल करने को लेकर वह कहते हैं कि ऐसा फिल्म रमन राघव में किया था। यादों का क्या है कि जब आपको वैसा सीन करना पड़ता है, तो उन पुराने जख्मों को कुरेदना पड़ता है या ऐसी घटना जिसने आपको चोट पहुंचाई हो। कलाकार की जिंदगी ही ऐसी होती है कि उन्हें बार-बार खुद को कटोचना पड़ता है। उन बुरी यादों में जाना पड़ता है, जिन्हें आप याद नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए न्यूयार्क में मैं एक फिल्म कर रहा था। मेरा शूट का आखिरी दिन था। मेरी बहन गुजर गई थी। मुझे सीन करना था। मैंने बहन को याद किया, क्योंकि वो सीन ऐसा था। कर तो दिया मैंने बहुत देर तक लोगों ने संभाला बाद में, लेकिन किरदार से निकलने के बहुत से साधन हैं। आप दोस्तों के साथ बैठ जाओ या गांव चले जाओ। नवाज आठ मई को रिलीज हो रही फिल्म मैं एक्टर नहीं हूं में नजर आएंगे।

मैं एक्टर नहीं हूं में नजर आएंगे नवाज। फाइल

ऐसा अनुभव और कहां...

कामेडी फिल्में तभी बेहतरीन बनती है जब कलाकार और निर्देशक में बेहतर तालमेल हो। फिल्म सिंह इज किंग और वेलकम जैसी कामेडी फिल्मों में साथ काम कर चुके निर्देशक अनीस बज्मी और अक्षय कुमार फिर एकसाथ कामेडी फिल्म कर रहे हैं। इस फिल्म का केरल शेड्यूल पूरा होने की जानकारी खुद अक्षय ने इंस्टाग्राम पर फोटो साझा करके दी है। इस फोटो में उनके साथ विद्या बालन और राशि खन्ना भी हैं। अक्षय ने लिखा कि केरल का शेड्यूल खत्म। खूबसूरत जगह पर अच्छे लोगों के साथ काम करने जैसा कुछ नहीं होता। आगे उन्होंने लिखा यह अनुभव सच में बहुत खास रहा। अक्षय हालिया रिलीज फिल्म भूत बंगला में नजर आए हैं। इसके अलावा वेलकम टू जंगल में भी वह कामेडी करते दिखेंगे।

अक्षय कुमार। इंस्टाग्राम - @akshaykumar

ट्रोल्स को दिया आकाशदीप ने जवाब, कहा आनलाइन ट्रोलिंग शोर है

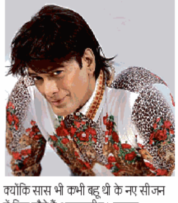

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के नए सीजन में फिर लौटे हैं आकाशदीप। फाइल

कई बार ट्रोल्स को जवाब देना जरूरी हो जाता है। खासकर अगर कोई किसी के काम पर गलत टिप्पणी कर रहा हो तो। अभिनेता आकाशदीप सहगल को भी जवाब देना पड़ा। साल 2002 में जब सास भी कभी बहू थी शो आया था, तब आकाशदीप उसमें स्मृति ईरानी के पात्र तुलसी विरानी के बेटे के रोल में थे। अब जब यह शो दोबारा नई कहानी और पुराने पात्रों के साथ आया है, तो शो में आकाशदीप की भी वापसी हुई है, लेकिन तुलसी के पोते के रोल में। उनके इस कमबैक पर दोनों के बीच कम उम्र के अंतर को लेकर आलोचना और ट्रोलिंग शुरू हो गई है। एक इंटरव्यू में अब आकाशदीप ने इस ट्रोलिंग पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, 'सच्चाई सामने है और कुछ लोगों की असुरक्षाएं इसे बदल नहीं सकतीं। आनलाइन जो ट्रोलिंग आप देखते हैं, वह सिर्फ शोर है। यह कुछ लोगों के डर और असुरक्षाओं से आती है, जो स्क्रीन के पीछे छिपे होते हैं। उन्होंने निर्माता एकता कपूर पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर मैं और एकता कपूर कुछ शोर मचाने वाले आलोचकों की चिंता में पड़ जाते, बजाय उन लाखों दर्शकों पर ध्यान देने के जो इस शो को पसंद करते हैं, तो बेहतरीन कहानियां कभी बन ही नहीं पातीं। एकता एक दूरदर्शी हैं, वह किसी से अनुमति नहीं मांगतीं। उन्हें पूरी तरह पता है कि वह क्या कर रही हैं।

इसलिए बंदर करने से पहले हिचकिचा रहे थे बाबी

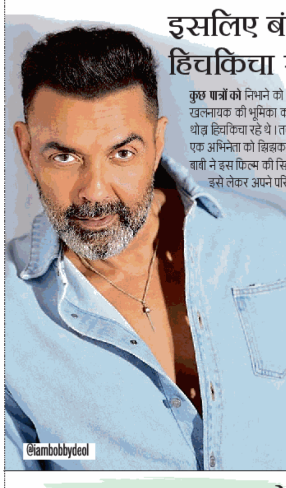

@iambobbydeol

कुछ पात्रों को निभाने को लेकर कलाकार संशय में होते हैं। एनिमल में खलनायक की भूमिका कर चुके बाबी देओल भी फिल्म बंदर करने को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तब अभिनेता व उनके पिता धर्मेंद्र ने उन्हें समझाया कि एक अभिनेता को झिझकना नहीं चाहिए। बंदर से जुड़े सूत्रों के अनुसार, जब बाबी ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो किरदार की गहराई को देखते हुए उन्होंने इसे लेकर अपने परिवार के साथ चर्चा करने का फैसला किया। जब उनके परिवार वालों ने कहानी सुनी, तो वे बाबी के इस चुनाव से थोड़ा हैरान थे, क्योंकि वे हमेशा एक सुपरस्टार इमेज में देखे जाते रहे हैं। हालांकि, पिता धर्मेंद्र ने उन्हें यह भूमिका स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वह फिल्म अनुपमा कर रहे थे, तब भी कई लोगों ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी, लेकिन जोखिम उठाया और वही फैसला सही साबित हुआ। बंदर फिल्म पांच जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में सान्या मल्होत्रा और सबा आजाद भी प्रमुख भूमिका में

रणवीर को देना चाहूंगा सौ रुपये का नोट

किसी का काम पसंद आए, तो उसकी सराहना तो बनती है। हालांकि सत्ते पे सत्ता फिल्म के अभिनेता सचिन पिलगांवकर का सराहना करने का तरीका थोड़ा अलग है। जब वह मराठी रियलिटी शो एका पेक्षा एक को जज करते थे, तो उसमें जब उन्हें किसी की परफार्मेंस पसंद आती थी, तो वह उसे सौ रुपये का नोट देकर हौसला बढ़ाते थे। आज के दौर में किस कलाकार को सचिन सौ रुपये का नोट देना चाहेंगे? इस पर सचिन अभिनेता रणवीर सिंह का नाम लेते हुए कहते हैं, 'उनकी फिल्म 83 मुझे बेहद पसंद आई थी। मैं उन्हें सौ रुपये का नोट देना चाहूंगा। मुझे उनका काम धुरंधर में भी बेहद पसंद आया था।' आगे पसंदीदा हिंदी फिल्मों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल देखने के बाद सात साल की उम्र में उन्होंने निर्देशक बनने का सोच लिया था।

@sachin.pilgaonkar

लंबा रास्ता तय करने वालों में से हूं

नया काम जब करते हैं, तो वह काम सही से हो रहा है या नहीं, उसके लिए किसी न किसी से मान्यता की जरूरत होती है। हालांकि, रैपर और अब अभिनेता बने किंग ऐसा नहीं सोचते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पर आठ मई को रिलीज होने वाली वेब सीरीज लुक्खे से अभिनय में कदम रखने वाले किंग कहते हैं, 'मुझे वैलिडेशन (मान्यता) नहीं चाहिए। कलाकार प्रशंसा का भूखा होता है। मैं कोई एक काम नहीं कर रहा हूं, ऐसे में मान्यता किन-किन चीजों के लिए लूं। मान्यता तब चाहिए होती है, जब पता होता है कि मैं खुद क्या करने वाला हूं। मैं धीरे, लेकिन लंबा रास्ता तय करने वालों में से हूं। मुझे सब कुछ आज ही नहीं चाहिए, इससे मजा खत्म हो जाएगा। बहुत पैसा देकर अगर कोई यह कहे कि पांच साल का संगीत बनाकर दे दो, तो मैं पैसा वापस कर दूंगा। संगीत से मुझे प्यार है, लेकिन जो मिल रहा है वह उसका बायप्रोडक्ट होना चाहिए, फिर चाहे पैसे हों या

मनोरंजन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

@ifeelking

एसवीसी63 के लिए विलेन की तलाश

@beingsalmankhan

सलमान-नयनतारा की फिल्म एसवीसी63 में अक्षय खन्ना या मलयालम फिल्मों के अभिनेता फहाद फासिल निभा सकते हैं खलनायक की भूमिका। टीम अरविंद स्वामी पर भी विचार कर रही थी।

अभिनेता सलमान खान की फिल्म मातृभूमि की रिलीज तारीख की प्रशंसक प्रतिक्षा कर रहे हैं। वहीं खबरें हैं कि उन्होंने निर्देशक वामशी पैडिपल्ली के साथ अपनी अगली फिल्म, जिसका अस्थायी शीर्षक एसवीसी63 है के पहले शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। सलमान और नयनतारा अभिनीत इस एक्शन फिल्म के अगले चरण की शूटिंग मनाली में होगी। इस बीच खबरें हैं कि फिल्म के लिए खलनायक अभी तय नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अक्षय खन्ना और मलयालम फिल्मों के अभिनेता फहाद फासिल इस भूमिका के लिए शीर्ष दावेदार हैं। निर्माता दिल राजू और निर्देशक दोनों अभिनेताओं से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल, स्क्रिप्ट की मांग है कि ऐसा अभिनेता हो जो सलमान के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। फहाद और अक्षय दोनों अलग-अलग तरह की ऊर्जा लेकर आते हैं। यही वजह है कि चयन में वक्त लग रहा है। मनाली में शूटिंग के बाद यूनिट हैदराबाद जाएगी। सूत्र ने आगे बताया कि हैदराबाद शेड्यूल शुरू होने से पहले विलेन को तय करना जरूरी होगा, क्योंकि आमने-सामने वाले दृश्य उसी दौरान शूट किए जाएंगे। सलमान व अक्षय इससे पहले फिल्म सलाम-ए-इश्क में साथ नजर आए थे, हालांकि दोनों के बीच कोई सीन नहीं था।